Mentally Retarded, regarding need for separate legislation for the metally retarded persons.

14.31 hrs.

DISCUSSION RE. FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

MR. CHAIRMAN: Now, we will start discussion on the flood and drought situation in the country These two discussions are being taken up simultaneously. The hon. Members may make their observations on both these subjects together.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, हमारा देश महान है और हमारे देश की जनता भी महान है। देश की महानता को देखते हुए इस की समस्याएं भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, महान हैं। देश इतना बड़ा है कि हर साल विभिन्न तरह की समस्याएं उपस्थित होती रहती हैं। कोई साल ऐसा बाकी नहीं होता जिस साल कहीं बाढ़ की बात सुनने को न मिले। इस बार भी हमारे देश में भयंकर सत्यानाशी बाढ़ आई और कई राज्यों में भयंकर सूखे की स्थिति है। हमारे देश के बारह प्रदेश बाढ़ से ग्रसित हुए। (1) आन्ध्र प्रदेश का कुछ भाग (2), आसाम, (3) बिहार जिस में पहले चरण में उत्तर बिहार के नौ जिलो में बाढ़ आई जो जुलाई और अगस्त के महीने में आई और दूसरे चरण में सितम्बर में बाढ़ आई, वह मुख्य तौर से दक्षिण बिहार के जिलों में और कुछ उत्तर बिहार के जिलों में भी आई। (4) गुजरात, (5) हरयाना, (6) उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और उस पूर्वी हिस्से के अलावा आगरा और मथुरा जिले, (7) जम्मू और कश्मीर, (8) पंजाब, (9) मणिपुर, (10) राजस्थान, (11) त्रिपुरा और (12) पश्चिम बंगाल जहां 15 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित हैं।

मैं बिहार से आता हूं। बिहार की बात मैं ज्यादा जानता हूं। मैंने निवेदन किया कि जुलाई और अगस्त के महीने मे उत्तर बिहार के नौ जिलों में भयंकर बाढ़ आई जिस से बहुत भारी वहां के नागरिको को क्षति उठानी पड़ी। कई लाख लोग बाढ़ से पीड़ित रहे। उस के बाद 17 सितम्बर, को दक्षिण बिहार के 16 जिलों के 167 प्रखण्ड बाढ़ के आक्रांत हो गए। पटना जिले के सोलहो प्रखण्ड पानी में थे। जब उत्तर बिहार में बाढ़ थी तो दक्षिण बिहार में सूखा था और फसल मारी गई। पानी के अभाव में आधी फसल बोई नहीं गई और फिर दक्षिण बिहार में बाढ़ आ गई। पहले तो कम बारिस के कारण, अनावृष्टि से दक्षिण बिहार में त्राहि माम, त्राहि माम कर रहा था और उस के सेबाद 11 16 सितम्बर तक भयंकर बारिस हुई जिस के फलस्वरुप गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गू, दुर्गावती, ओरगा, कर्मनाशा, उत्तर कोइल, बटाने, सुवर्णरेखा, दामोदर तथा कोंऊल इन 12 नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई जिस की बजह से डेढ़ करोड़ लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। तमाम फसलें नष्ट हो गईं। अरबों रुपये की क्षति हुई। दक्षिण बिहार में जिन दिनो में बाढ़ आई, जिन इलाकों में बाढ़ आई वहां की फसल नहीं बची, लोग पेड़ों और छप्परों पर रह कर जिन्दगी व्यतीत करने लगे। कई दिनों तक सरकारी सहायता भी नहीं पहुंची। जब वायु सेना के लोग पहुंचे दो तीन दिनों के बाद तब कुछ इलाको में जहां सहायता नहीं पहुंच पा रही थी वहां भी सहायता भेजी गई। इस तरह से बिहार में जो बाढ़ ग्रस्त जिले हैं सितम्बर की बाढ़ से जो ग्रसित हुए उन में पटना, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, नालन्दा, गया, सारन, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मूंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, कटिहार, पालमू और हजारीबाग जिलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह बात ठीक है कि सरकार से जो कुछ बन पड़ा, संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सहायता भेजी गई। मैंने जिक्र किया कि वायु सेना के जवानों ने

[श्री रामावतार शास्त्री]

बड़ा अच्छा काम किया। कहीं कहीं सी आर पी के लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया। लोगों को बचाने की कोशिश की गई। नावों की कमी रही। जो सामग्री भेजी जा रही थी उस का आम तौर से बटवारा होता रहा। अधिकारियों ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन कई गलत अधिकारी भी देखने को मिले और कुछ हमारे मुखिया लोगों ने भी गोलमाल करने की कोशिश की जिस में से एक मुखिया पटना जिले के फतुहा प्रखंड में पकड़े गए और उन पर मुकदमा चल रहा है।

तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग भी दिखलाई पड़े जो जनता की मुसीबतों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरा अन्दाज है हर सूबे में ऐसे लोग होंगे। हमारे बिहार में कई जिलों में इस तरह की बातें हुई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बाढ का सम्बन्ध है, बिहार में पिछले तीन सालों से हर साल बाढ आ रही है। 1974, 1975 और इस साल भी वहां पर बाढ आई। 1975 में पटना शहर जो बिहार की राजधानी है, बिहार का मुकुट है, बाढ में डूब गया था। 8–9 फ़ीट पानी पिछले साल पटना शहर में था जिसके कारण सरकारी और गैर-सरकारी करोड़ों रूपए की क्षति हुई। इस बार भी पटना के लिए खतरा था लेकिन जो नया बांद बना पटना शहर बचाने के लिए और जो बाई-पास रोड बनी—उन दोनों की वजह से और अधिकारियों की चुस्ती की वजह से पटना शहर में पानी नहीं आ सका जो कि पुनपुन नदी का बांध तीन जगह से टूट गया—सलारपुर, चिहुट और एक तीसरे गांव के पास, ये गांव मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। यह बांध जो टूटा उसके लिए अधिकारियों को पकड़ा जाना चाहिए। मेरी समझ से उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसी वजह से चूहों ने बांध में बिल (होल्स) बना दिए थे और कुछ शराब चुआने वालों ने डिस्टिलरी बना रखी थी जिसको भरा नहीं गया। इसी वजह से बांध टूट गया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर साहब को हमने जो मेमोरंडम दिया है उसमें भी हमने मांग की है कि इन बातों की जांच होनी चाहिए। नया बांध जो बना उसमें भी कहीं कहीं गड़बड़ी थी जिस पर 17 करोड़ या उससे भी ज्यादा रुपए खर्च होने वाले हैं। तो इन तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। तमाम अफ़सर खराब है—ऐसा मैं नहीं कहता। ज्यादातर अफ़सरों ने ठीक काम करने की कोशिश की लेकिन फ़िर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं विस्तार के साथ उन बातों में नहीं जाऊंगा, 16 जिलों में जहां जहां बाढ़ आई है वहां पर फ़सल नष्ट हो गई है और आगे भी बारिश नहीं हो रही है। बहुत जगह समस्या यह है कि फ़सल बोय कैसे, रबी की फ़सल कैसे बोई जाये क्योंकि जमीन कड़ी हो गई है और बिजली की कमी की वजह से ट्यूबवेल और पंपिंग सेटों से भी पानी नहीं मिल रहा है।

ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से दो तरह की बातें कहना चाहता हूं। एक तो इस सिलसिले में फ़ौरी कदम उठाने चाहिए। जैसे कि खेत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है क्योंकि किसानों के पास काम नहीं है, उनकी फ़सल मारी गई है। इसके लिए कठिन श्रम योजना चालू की जाएं लेकिन बिहार में कठिन श्रम योजना ठीक से चालू नहीं की गई है। जो बाढ़ग्रस्त हैं उनको आप कुछ मुफ़्त में न दीजिए लेकिन कम से कम लोन तो दीजिए और जो असक्त, अपाहिज हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं उनको लाल कार्ड दीजिए। (व्यवधान) सरकार का कहना है कि 4 लाख मकान गिरे हैं लेकिन मेरा अन्दाजा है कि 5–7 लाख मकान गिरे हैं। घर बनाने के लिए आप 100 रुपया देते हैं। जो नेचुरल कैलेमिटी ऐक्ट है उसके अन्तर्गत आप 100 और 300 से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं आप उनको पूरा पैसा दीजिए। इसी प्रकार उनको बीज नहीं मिल रहा है, वह दीजिए। आप लोकप्रिय सहायता समितियों

का निर्माण कीजिए । ताकि अफ़सर गड़-बड़ न कर सकें । और कोई गैर-सरकारी आदमी गड़बड़ न कर सके, आपस में मिलकर बटवारा न कर लें । उसमें किसी तरह की मनमानी या पक्षपात को रोका जाये और धांधली को रोका जाये । पीने के पानी का इन्तजाम किया जाये । जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है उसके लिए इन्जाम किया जाये । चिकित्सा का बन्दोबस्त किया जाये । इसके अलावा छठे वित्त आयोग ने जो बन्दिश लगा दी है कि साढे चार करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, इस सीमा को प्राप्त किया जाये । तीन सालों में 4 करोड़ 61 लाख देने थे, इस सीमा को भी समाप्त करना चाहिए । मालगुजारी की वसूली स्थगित करनी चाहिए । यह तो जो फ़ोरी बातें थीं वह मैं ने बताई ।

जहां तक बुनियादी बातों का सम्बन्ध है, जब तक आप पूरे देश को मिलाकर और बिहार को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार नहीं करते तब तक आप बाढ को रोक नहीं सकेंगे । मेरा कहना है कि भारत सरकार बाढ और सिंचाई की एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक योजना तैयार करे जिससे बाढ पर नियंत्रण किया जा सके और प्रत्येक वर्ष करोड़ों और अरबों रुपए की बरबादी और तबाही से देश को बचाया जा सके । मेरा यह भी अनुरोध है कि बिहार में केन्द्रीय सरकार अपनी देखरेख में योजना को कार्यान्वित करे ताकि व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके और किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो । केन्द्रीय सरकार अपनी देखरेख में करे, बिहार सरकार पर मत छोड़े ताकि हर साल बिहार को बाढ से नुकसान न पहुचें ।

पटना नगर की रक्षा के लिए पुनपुन नदी की बाढ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना क्रियान्वित की जाये और अगले वर्ष की बरसात के पहले पूरा कर लिया जाये । इसके अलावा फ़तुहा, मुकामा, बड़दिया टाल योजना को क्रियान्वित किया जाये ।

जहां तक सुखाड़ का सम्बन्ध है, उसका प्रभाव 8 राज्यों में है जैसे केरल, कर्नाटक आदि । मेरे राज्य में भी चार जिलों— संथाल परगना, हजारीबाग, गिरिडीह और सिंहभूमि में उसका प्रभाव है ।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Mr. Chairman, Sir, this year in our country, there have been floods in Assam, Bihar, Gujarat, Punjab and Haryana and droughts in Karnataka, Tamilnadu, U.P. and Andhra Pradesh and in some parts of Andhra Pradesh. Now, I will start with droughts. As per the newspaper information, the entire world has been affected by droughts this year. Now, there are 12 districts in Karnataka which have been hit by drought affecting the standing crops like paddy, sugar cane, etc. In Tamilnadu, an amount of Rs. 26.0 crores was demanded by the Karunanidhi Ministry and I do not know what amount had been sanctioned for that State and in what way the money has been spent by the Karunanidhi Government. In Tamilnadu, 20 elephants perished because they could not withstand the starvation for a long period. Due to drought and water being scarce in most rivers famine conditions prevailed and about 3.5 lakh people in Naupara in Kalahadi district were hovering between life and death. About 8.5 million people of Orissa have been affected by drought. In Andhra Pradesh, 8 or 9 districts are squarely affected by drought and crops like ground-nut, jowar etc. have totally failed. Drinking water is scarce in the districts.

Now, in Bihar, from where I come, we have faced devastating floods this year, not once but twice, once in July-August and then in September. As you know, there are 31 districts in Bihar, grouped into 7 divisions. The total area is 7.4 million hectares. There are about 800 C.D. Blocks. The net area sown is about 85 lakh hectares. Out of this 85 lakh hectares, kharif crop covered an area of [illegible]

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

lakh hectares and rabi crop covered 32 lakh hectares. The flood was very serious and unprecedented this year. In Patna district alone, excepting the uplands of the State capital, the area affected had been 1225 sq. miles, with a population of 14.52 lakhs. 16 blocks in Bhojpur district covering area of 1196 sq. miles and a population of 13.07 lakhs have been affected. In Rohtas district, 20 blocks covering an area of 923 sq. miles and a population of 9.71 lakhs have been affected. Similarly other districts of Aurangabad, Gaya, Nalanda, Palamau etc. have been affected. In all 15 districts have been affected badly. Roughly on a preliminary estimate the total damage to the national highway system in Bihar is to the tune of Rs. 4 crores. Altogether 124 rural water supply systems have been affected Pumping plants, transformers, sub-stations, etc. have generally been damaged. The estimated cost of renovation and reconstruction to the various irrigation and flood protection schemes is about Rs. 17.35 crores. The present floods have completely submerged paddy crops in parts of several districts, covering paddy area of over 11.26 hectares.

The minimum requirement of credit for certified seed alone would be of the order of Rs. 15.70 crores in Bihar. To implement the normal rabi production programme this year, the Government of India has already been requested to sanction a sum of Rs. 15 crores as S.T.C. loan. The ravages due to this flood has necessitated an additional requirement of at least Rs. 10 crores making a total requirement of Rs. 25 crores as short term loan repayable after one year.

The Bihar Government submitted a memorandum before the experts committee of the Government of India on 11th October. The Bihar Government has sought Rs. 137 crores for flood repairs. It is very essential that the Government of India should without and delay sanction this money and save Bihar. It has to be noted that while there were floods in North Bihar, there was drought in South Bihar in Singhbhum, Hazaribagh and other areas. The State is under severe financial constraint. There is a provision of Rs. 4.61 crores in the State non-plan budget as per the sixth Finance Commission's recommendation. But this is not sufficient. We shall need another Rs. 10 crores to meet the needs of relief operations. Last but not least employment-oriented HML schemes are also required.

I suggest that permanent arrangement for floods and droughts in Bihar and other parts of the country should be evolved. North Bihar rivers should be channelised into South Bihar and a scheme should be evolved by the Centre. The Central Government should take up the schemes in hand for all States especially Bihar, where flood and drought are a permanent feature. This is out of the control of the State Government. Every year lakhs of people become beggers. Lift irrigation schemes should be taken up and sinking of more and more deep wells should be undertaken. Small dams on the rivers should be constructed to check the floods.

The Rashtriya Barh Ayog should be more active and they should do something more. I want to mention here one thing. The Rashtriya Barh Ayog was constituted under the chairmanship of Shri Jaisukh Lal Hathi, who is now the Governor of Haryana. On 3rd July, 1976, the Commission was expected to go there. Since the launching of the Water Commission, about Rs. 400 crores have been spent till March last year, but we do not know with what results. Therefore, it should be more active.

Lastly, I would further suggest that the water from the reviers in the North should be pumped to the South and a scheme at the national level should be taken up.

With these words, I would request the Government of India to please do the needful and save Bihar.

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) :सभापति जी, देश में पिछले दिनो बाढ़ के कारण जितना नुकसान हुआ, उस से हम सभी परिचित हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां बाढ़ की चपेट न आई हो। असम, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, ये देश के जितने प्रान्त हैं, सब में बाढ़ की विभीषिका रही और साथ ही साथ कुछ हिस्सो में सूखे का प्रकोप भी रहा। लेकिन, सभापति जी, इस बार कुछ ऐसा रहा, खास कर मैंने अपने प्रांत बिहार में, देखा कि प्रकृति की लीला इस बार विचित्र थी। जिन हिस्सों में पहले सूखे से भंयकर क्षति होती थी, उनमें भंयकर बाढ़ आई और जहां बाढ़ आती थी, वहां इस बार सूखा पड़ा। प्रकृति ही उलट गई और जब प्रकृति उलटती है तो पुरुष लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। बाढ़ और सूखा दोनों ने हमें इस बार तबाह किया, आर्थिक रूप से बरबाद किया, देश की एकानमी को इस से बहुत अधिक क्षति पहुंची, लाखो, घर तबाह हुए। हम यह देखते है कि औसत प्रतिवर्ष 70 लाख हैक्टेयर में पानी आता है, जहां बाढ़ का प्रकोप रहता है और उस से करीब-करीब प्रतिवर्ष 180 करोड़ रुपए की क्षति होती है–देश भर में।

पिछले दिनो ता० 11–8–1976 को सैन्ट्रल वाटर कमीशन के चेअरमैन श्रीमूर्ति की एक वार्ता आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 1975–76 तक 4,490 मिलियन रुपए हम लोगो ने बाढ़ नियंत्रण के लिये खर्च किये हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, शायद हम लोग समझ नहीं पाये हैं। इसके साथ ही देश में 7500 किलोमीटर तक की दूरी के एम्बैकमेंट भी बांधे गये हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ है यह भी बहुत कुछ देखने में नहीं आया है। श्रीमन्, बिहार में जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अखबारो में भयंकर बाढ़ की खबरें न आई हों। अभी जैसा कि शास्त्री जी ने कहा–पिछले साल केवल पटना राजधानी में बाढ़ आई थी, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था, इस दफा जब वहां बांध बना दिया गया तो नतीजा यह हुआ कि दक्षिण बिहार के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। पहले बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ आती थी, कोसी, गण्डक, कमला में बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आई, वे उफान मारकर शेर की तरह से दहाड़ने लगीं, पुनपुन, अबरी, मुरहर, स्वर्णरेखा और यहां तक कि दामोदर में जो कि कन्ट्रोल्ड है, उसमें भी भयानक बाढ़ की स्थिति थी।

15.00 hrs.

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस को राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत लें। पिछले दिनों भी संविधान संशोधन के समय हम लोगों ने बार-बार कहा था कि कृषि और सिंचाई को राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। क्यों हमने कहा था? हमने इसलिए कहा था कि आप पैसा जरूर देते हैं लेकिन पैसे का उपयोग कैसे होता है, इस को भगवान ही जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं और मेरा अपना ऐसा विश्वास हो गया है कि जैसे धान, गेहूं और चने की फसल होती है वैसे ही बिहार में बाढ़ की फसल होती है और बिहार के जो अधिकारी हैं वे भी यह सोचते हैं कि हम भी क्यों न इस बाढ़ में हाथ धो लें। इसलिए शायद वे नहीं चाहते कि बाढ़ पर कन्ट्रोल हो और सूखे पर कन्ट्रोल हो। अगर बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण हो गया, तो उनका काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको एक राष्ट्रीय नीति के रूप में लेकर केन्द्र इसको अपने सुपरवीजन में ले और इसकी देखरेख करे। करोड़ो करोड़ रुपया आप देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है और बेचारी जनता बाढ़ की विभीषिका में फंसी रहती है,

[श्री शंकर दयाल सिंह]

सभापति महोदय, मैं आप को बताऊं कि पिछले दिनों बिहार के 31 जिलों में से 15 जिलों में जैसे हजारीबाग, औरंगाबाद, गया का हिस्सा नालन्दा का हिस्सा, बिहार-शरीफ़ का हिस्सा, और पटना के हिस्से में और दूसरी बहुत सी जगहों में बाढ़ का प्रकोप था। मैं इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बिहार के कुल 587 ब्लाकों में से 253 ब्लाकों में बाढ़ का प्रकोप था और पिछले साल 14 लाख हैक्टेयर जमीन में पानी का जमाव था। मैंने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा है और दूसरे जिन लोगों ने उस को देखा है वह भी जानते होंगे कि महा-प्रलय की तरह से पानी हर तरफ़ दिखाई देता था। मैं उन दिनों अपने क्षेत्र में घूम रहा था और मैं पटना जाना चाहता था लेकिन एक हफ़्ते तक मैं पटना में प्रवेश नहीं कर सका। पटना को जाने वाली सड़क बन्द हो गई थी और बांध कट गया था। नतीजा यह हुआ कि जहां भी देखो, पानी ही पानी दिखाई देता था। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं सरकार को तीन, चार बातें कहना चाहता हूं और आप का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आप की आंखों से लगता है कि प्रेम बरस रहा हो लेकिन डरता हूं कि कहीं आप का हाथ घंटी पर न चला जाए। इसलिए प्रेम बरसाने के साथ-साथ आप अपनी उंगली घंटी पर न ले जाइए।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण को ले कर सरकार चले और जैसे आपने फरक्का बांध की योजना बनाई है, उसी तरह से जिन जिन नदियों में बराबर बाढ़ आने की सम्भावना रहती है, उन की योजना सरकार बनाए और केन्द्र द्वारा उन का संचालन करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में इस बार बहुत भयंकर बाढ़ आई है। मेरे क्षेत्र में, जहां पर लोग यह नहीं जानते थे कि बाढ़ क्या होती है, छपरा, प्रतापपुर और हंटरगंज आदि जगहों में ऐसी बाढ़ आई कि सड़कें टूट गईं, फसलें बर्बाद हो गई और लोग तबाह हो गये। इसलिए मेरा कहना यह है कि जैसे आप ने दामोदर वली कार्पोरेशन बना कर बिजली और सिंचाई दोनों की व्यवस्था की है और उस से बहुत लाभ हुआ है, उसी तरह से आप सोन और पुनपुन वैली कार्पोरेशन जरूर बनाएं जिस से इन क्षेत्रों का भी विकास हो सके।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो भी काम करें वह टेम्पोरेरी रूप से न करें क्योंकि वह उड़ जाता है। कहीं बालू निकाल रहे हैं और कहीं छोटे बांध बना रहे हैं और इन पर 50, 50 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और नतीजा कुछ नहीं होता। इसलिए आप जो भी काम करें वह पर्मानेन्ट करें और वह पर्मानेन्ट वैल्यू का हो। सभापति जी, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि यह इन्द्र का प्रकोप ही है जो भयंकर बाढ़ें आती हैं और इस इन्द्र के प्रकोप से लोग त्राहि-त्राहि करने लगते हैं और जब ऐसा होता है तो लोग इन्दिरा जी के

पास आते हैं और इन्दिरा जी यानी केन्द्रीय सरकार लोगों की मदद करती है। तो मेरा कहना यह है कि जब केन्द्र से पैसा ले कर राज्यों को मदद पहुंचाने की जरूरत पड़ती है और सारी योजना को करना पड़ता है तो फिर आप क्यों नहीं इस पर ठीक से कन्ट्रोल रखते। पटना को बचाने के लिए जो बांध बनाया गया उस से लोक सभा के अध्यक्ष श्री भगत की कांस्टीटुयेन्सी के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। वे बोल नहीं पाते हैं लेकिन अगर आप उन से पूछेंगे तो आप को पता चलेगा कि पूरा उन का क्षेत्र बर्बाद हो गया। पटना शहर को बचाने के लिए बिहार के कम से कम एक करोड़ लोगों को पानी के अन्दर डूबो दिया गया। अगर पटना को डूबना था तो वह डूब जाता परन्तु उस को बचाने के लिए जो बांध बनाया गया उस से गांवों के एक करोड़ लोग तबाह हो गये। आज स्थिति यह है कि वहां पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को साइंटिफिक रूप से इस समस्या से निपटना चाहिए और अगर यही स्थिति रही है तो हर साल आप वहां पर लोगों को हेलीकोप्टर से खाना पहुंचाते रहेंगे और उस से कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति जी, सोखी जी अभी बोल रहे थे तो बता रहे थे कि ब्रिटेन में पिछले ढाई सौ सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। हमारे केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री, श्री जगजीवन राम जी जब बिहार गये थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में इतनी भयंकर बाढ़ पिछले 6 सौ सालों में नहीं आयी। फिर भी बिहार को जो पैसा दिया गया है वह महाराष्ट्र के अनुपात में कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जो मेमोरेण्डम केन्द्रीय सरकार को दिया है, उसको भी आपको देखना चाहिए और बिहार को मदद देनी चाहिए। हम को याद है जब महाराष्ट्र में सूखा पढा तो उसको दो साल के अन्दर 232 करोड़ रुपया दिया गया। बिहार की जनसंख्या को देखते हुए इस समय आपको बिहार को भी उसी अनुपात में मदद देनी चाहिए।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneshwar): Mr. Chairman, Sir, today, the entire State of Orissa is in the most distressing condition and almost all the 13 districts of the State have been affected by serious drought conditions.

Specially, my constituency comprising of Bhubaneswar, Jatni, Khurda, Bolgarh, Begunia, Nayagarh, Daspall and Khandapada have been worst hit as there is no canal system which serves this area. The people living in this area are really in very great distress.

The dry spell in Orissa began from first week of September and it continues since then. Only on 16th October, there was a little rain but it was confined to only areas near the sea shore within a limit of 20 to 25 miles. Therefore, the rest of the State remained dry.

I have recently visited many of the areas which are affected by drought. Everywhere, about 75 to 80 per cent of the standing crop has dried up. I must admire my people that without waiting for the help of the Government, through manual labour, they tried to save their lives' hope, their standing crop, by all possible means

[Shri Chintamani Panigrahi]

and they even carried water in jugs to sprinkle in their fields—all the wells had dried up—but the crop could not be saved.

According to meteorological sources, Orissa had 29 to 50 per cent less rainfall than the normal rainfall during this year's monsoon. Kharif is the principal crop of the State. This accounts for 77 per cent of the gross crop and over 83 per cent of the State's foodgrains is harvested this season. This crop mainly depends on monsoon. The irrigated area is only about 16 per cent of the net sown area. Therefore, the severity of the drought could be judged by the hon. Minister, Shri Annasaheb Shinde and the hon. Minister, Shri Shahnawaz Khan. Both of them have been kind enough to help us in distress. They always come to our help. I would request them again to come to the help of the people of Orissa who have been affected by the drought.

I must say that the scene is most heart-rending. During the last ten years, Orissa has suffered from drought for seven years. During the last one hundred years, Orissa has suffered from either serious drought or flood for sixty years. Therefore, Orissa cannot prosper and cannot catch up with the other States in improving the living standards of our people faster. This is the time when the farmers after exhausting all their resources wait in great hopes for the crops in the fields to be harvested for sustaining themselves. But severe drought has shattered all their hopes. They deserve all the help from the Government.

The points, that I would like to bring before the kind attention of the hon. Minister are, firstly, to provide work and food nearly to 2 crores of people in the State till the next year's khariff crop. Almost 75 to 80 per cent of the crop has been lost. Secondly, you should also provide seeds for the next year's khariff crop. Thirdly, you should open fair price shops in every village. Fourthly, you should undertake the construction of minor irrigation works, renovation of tanks and old minor irrigation works so that the people get work. Fifthly, to help the farmers for raising Rabi crops and early variety paddy crops in the irrigated areas; sixthly, to provide food for the children; and finally, collection of all Government and cooperative arrears to be stayed.

One more point is about the Manibhadra irrigation project in Daspalla area of the Mahanadi. It was going to provide irrigation to half-a-million acres. I would request that this should be taken up now.

Then, as far as our State or Orissa is concerned, there are a lot of drought-prone areas and since Rs. 70 crores is going to be spent on the drought-prone areas, I hope our State will get the maximum help possible from the Central Government.

✓ **श्री जगन्नाथ मिश्र** (मधुबनी)। सभापति महोदय, कहा जाता है कि वीणा का तार टूट जाता है लेकिन गूंज रह जाती है। हर साल बाढ़ आती है, लोग बाढ़-ग्रस्त होते हैं, सरकार के समक्ष गवाही दी जाती है, सरकार अपने साधन के अनुकूल सहायता करती है, लेकिन लोगों का दुख दर्द बना ही रह जाता है। आज जब देश ने विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कारिक उत्थान किया है, और कर रहा है, तब भी हर साल देश बाढ़ और सूखे से परेशान रहे और लोग दाने दाने को मोहताज रहें यह बर्दाश्त की चीज नहीं लगती है। अभी सारे देश में बाढ़ आयी, माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि किस तरह की बरबादी हुई और लोग परेशान हुए। इसलिए सारे देश की बातें यहां न उठा कर मैं अपने प्रान्त बिहार की ओर आप का ध्यान खींचना चाहता हूं जहां पारसाल 25 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ आयी और पटना की जो क्षति हुई उस की चर्चा आप ने सुनी।

इस साल 17 सितम्बर को बिहार की तीन नदियों—गंगा, सोन और पुनपुन—में बाढ़ आ गई और पुनपुन के तटबंध में दरारें पड़ गई। सरकार ने इस की जानकारी लोगों को दी और लोगों ने अपने स्थान छोड़ सुरक्षित स्थानों में शरण ली। पटना की रक्षा तो हुई, किन्तु अन्य स्थानों में जो बरबादी हुई उस की हम चाहे कितनी भी चर्चा करें, मुझे विश्वास है कि हम उस की वास्तविक चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, आप को मालूम हो कि बिहार के 15 जिलों में जिन में 145 प्रखंड होते हैं, बाढ आयी और लोग उस से परेशान हुए। पौने सोलह हजार वर्ग मील इलाके में साढे 95 लाख की आबादी बाढ़ से बरबाद हुई। बिहार सरकार ने अपने साधन के अनुकूल लोगों की सहायता की, लेकिन वह दाल में नमक के बराबर भी नहीं हुई। इसलिये सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तत्काल 16 करोड़ रु० की राहत के लिये लिखा और सड़कों की मरम्मत के लिये 15 करोड़ तथा रबी अभियान के लिये 25 करोड़ रु० की मांग की। श्रीमन्, प्रधान मंत्री भी द्रवित हुई और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने 15 जिलों का जैसे सासाराम, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, बरौनी, बेगुसराय, खगरिया, मुकामा, बड़हिया, फतूहाबाद, मसौढ़ी, नालन्दा, इस्लामपुर, हिलन्सा-पुनपुन, पटना आदि स्थानों का हवाई सर्वेक्षण किया और जो स्थिति उन्होंने देखी उस से वह द्रवित हो गई।

उसके फलस्वरूप एक केन्द्रीय दल वहां भेजा गया जो इस बात की जांच करे कि बाढ से बिहार को कितनी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री से वर्णन किया कि बरौनी और बेगुसराय बाढ़ से पर्याप्त आहत हुए हैं, यद्यपि बाढ़ से सुरक्षा और बचाव के काफी काम हुए, फिर भी लोगों को बाढ़ की चपेट में आना ही पड़ा और भारी बर्बादी सहन करनी पड़ी।

बिहार बाढ़ से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिये जो केन्द्रीय विशेषज्ञ दल भेजा गया था, उसका कहना है कि बिहार की कुल एक अरब 82 करोड़ की क्षति हुई है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है—

(1) 5 लाख 30 हजार हैक्टर भूमि में लगी धान की फसल नष्ट हो गई,

(2) 67 हजार हैक्टर भूमि में लगी मकई की फसल नष्ट हो गई,

(3) 98 हजार हैक्टर जमीन में लगी अन्य फसलें बेकार हो गई।

इसी प्रकार श्रीमन्, बिजली बोर्ड को 5 करोड़ 10 लाख रुपयें का तथा सिंचाई व्यवस्था को 19 करोड़ 21 लाख रुपये का नुक्सान हुआ। 4 लाख मकान ध्वस्त हो गये, जिनके पुनर्निमाण और मरम्मत के लिये 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गई है।

अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यह जो दल नियुक्त हुआ है, उसका पहला काम यह है कि वह इस बात का मूल्यांकन करे कि क्षति कितनी हुई है, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इस विनाशकारी बाढ़ से बिहार को कैसे बचाया जा सकता है।

बाढ़ से बचाव के लिये बिहार में विभिन्न नदियों पर तटबन्ध और पुल बना दिये गये हैं, जिससे नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बन्द हो गया है। होता यह है कि हर साल बाढ़ बहुत प्रबल वेग से आने लगी है। जो कार्यकारी दल है, उसको यह सोचना चाहिये कि जो तटबन्ध बांध दिये गये हैं और पुल निर्मित कर दिये गये हैं, कहीं उनसे तो पानी की धाराओं में व्यवधान नहीं होता है। और यही कारण तो बाढ़ आने का नहीं है। अगर यही कारण है, तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर वह अपनी सम्मति

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

दे, राय दे और बिहार सरकार को सोचना चाहिये कि इन कारणों से बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है ।

मैं सरकार से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह यह न समझे कि जब बाढ़ आती है तो उससे आम जनता को ही क्षति उठानी पड़ती है, बल्कि सरकार को भी भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसलिये बाढ़ से बचाव के लिये प्रयास करना उसका कर्तव्य हो जाता है। यह सरकार को स्पष्ट हो जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री भी चाहती हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाया जाये और इसके लिये वह एक परमानैन्ट सौल्यूशन चाहती हैं। इसके साथ ही जब मैं बाढ़ की चर्चा कर रहा हूं तो उसी सिलसिले में एक विशेष बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार में मधुबनी जिला है और वही मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। उसमें 18 प्रखंड हैं। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इन 18 प्रखंडों में से 14 प्रखंड सूखाग्रस्त हैं। वहां के लोग परेशान हैं, वहां तबाही है और अब वहां खरीफ की फसल होगी ही नहीं और रबी की फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिये सरकार का ध्यान दिलाने के साथ साथ मैं आग्रह करूंगा कि वह उधर ध्यान दे और लोगों की कठिनाईयों को सम्यक ध्यान देकर दूर करने का प्रयास करे।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Mr. Chairman, Sir, I speak on behalf of the State of Karnataka where there is a considerable amount of drought. I completely agree with the hon. Member that these natural calamities are very serious subjects.

In the State of Karnataka, about 15 districts are suffering from drought. The hon. Minister must have already been in receipt of the Memorandum of scarcity conditions in Karnataka; this is only for the period May to August, 1976 and there is a request for Central assistance. Concluding, the State Government has stated:

> "The State Government would request the Central assistance of Rs. 14 crores to be released during 1976-77 for tackling on a short-term basis the present drought conditions. 50 per cent of this assistance may kindly be released immediately since many of the programmes are already under execution and it is imperative that they should not be stopped."

They have given the detailed break-up of their programmes which are under execution, for example, minor irrigation, rural communication, soil conservation, afforestation, lift irrigation, deployment of rigs for drinking water, subsidy and assistance for transfer of fodder etc.

We also hear some alarming news that particularly the price of beef has gone down very enormously. The cultivators are selling this because they are not in a position to feed, which is again linked up with supply of fodder.

The memorandum that has been submitted is already outdated, because the conditions of scarcity have become more acute. Under the circumstances, we have been assured of a second Study Team. I hope that it will come up with factual details and provide the requisite financial assistance.

I want to make two or three points. The first point is in regard to the recommendations of the 5th Finance Commission. The 5th Finance Commission, headed by our present Home Minister, Shri K. Brahmananda Reddy had earmarked a specific amount for famine relief assistance to each one of the State. Andhra Pradesh received Rs. 4.31 crores and the State of Karnataka Rs. 1.91 crores. I do hope that the hon. Minister, while replying to this debate, will clarify

as to whether the assistance which we will be receiving during the current year by way of Central assistance under 64-Famine Relief, would be subject to these recommendations. The recommendations of the 5th Finance Commission are clear:

> "We strongly urge that instead of incurring expenditure on relief on *ad hoc* basis on schemes of dubious value, provision should be made on a much larger scale for development of drought and flood prone areas in the 5th Plan both in the Central and State sectors."

The State Government has sought for central assistance of Rs. 14 crores. Does the sum total of this recommendation mean that there will be a reduction of the central assistance to this extent in regard to the other projects that are on going in the State of Karnataka? The sum total result of the assistance for drought relief or famine relief will be that the works of development in other spheres of activity in the State of Karnataka will be affected adversely to that extent; it would mean that. In this context, I feel that constitutionally speaking, drought is not a State subject. It is not within the control of the State—the drought in Karnataka. ....(Interruptions) The southern part of Maharashtra was also affected by drought. That is a part of the Karnataka drought.—Drought knows no linguistic barriers. So, there was a clear case. Very recently we have amended our Constitution. At least drought, if not the whole of agriculture which cuts across the barriers, can be made a sort of concurrent subject.

Sir, we need assistance from UP, Punjab and Haryana for rigs. That I hope will be looked into by the Ministry. The last but not the least is that in the year 1972-73 when the State of Karnataka was in the grip of drought, some amounts were earmarked for lift irrigation by the Ministry and the hon. Minister himself had announced it. I am afraid, on the basis of the findings of the 20-point committee at the district level the utilisation of these funds earmarked on an *ad hoc* basis for building up lift irrigation schemes has not been proper. I have seen myself in the district of Belgaum at Mogatkhan near Hubli a scheme involving an expenditure of Rs. 15 lakhs was sanctioned and an expenditure of Rs. 7 lakhs was incurred irrigating an area of 15 acres of land. Sir, perennial irrigation was provided for 15 acres. The substance of what I am trying to suggest or submit for the consideration of the Government is: each year in some part of the country or the other there is a natural phenomenon or a sort of natural calamity and we give assistance for it. As to how it is used is nobody's business. It tends to get misused or improperly used and at times mostly abused. I would request the hon. Minister to kindly investigate what happened in that drought relief.

Then, Sir, Maharashtra demanded the construction of Bombay-Afta railway line as a sort of drought relief. On the same lines I also want that Karwar-Hubli line should be taken for up for construction as a drought relief as it is a labour-intensive project and will give a lot of relief to the drought affected people there.

DR. K. L. RAO (Vijayawada): I rise to make a few suggestions. The hon. Ministers were doing good work but the flood problem of India is very complicated. There are many rivers throughout the country, though smaller in size. The volume of water in all the rivers of India is only one-fourth of the water in one single river of Amazon in Brazil but the problem is vast because of the large number of rivers. That is why I said the problem of floods in this country is very complicated.

The idea of controlling the rivers on a national scale came from

[Dr. K. L. Rao]

Panditji in 1954. From 1954 onwards for the last 22 years there were many committees on floods headed by experts, Ministers, Engineers and so on and we have got ample material in those various reports. What we require really in this country is to realise the difficulties of the flood problem and make special studies on particular aspects which I will try to mention.

Some friends have been asking what is the result achieved so far. We have spent Rs. 400 crores on flood control. In this country the flood prone area is 20 million hectares. Out of this, one-third has been saved so far. In fact with this small sum of Rs. 400 crores we have achieved a magnificent result. Hereafter, we have got many more flood-prone areas which are difficult to secure protection from the floods.

As I generally do, I will divide the flood problem of the rivers of India into three sectors. Group I are the peninsular rivers of the Narmada and the Orissa rivers, the Baitarni, the Brahmani, the Subarnarekha, the Burbalang; what these rivers need is construction of reservoirs.

The construction of dams—at Hirakud on the Mahanadi, Ukai on the Tapi and DVCs dams have resulted in affording protection from the floods to extensive areas. Likewise in Orissa, Rangali on the Brahmini, Bhimkund on the Biterni, Chandli on the Swaran Rakha if constructed, will, benefit large areas. These projects are known to us. Time bound programmes have to be drawn to control the flood detention reservoirs.

The second group concerns with the Himalayan rivers. The Himalayan rivers are very difficult to deal with. Construction of dams presents —engineering problems. Also the sites of these dams are in Nepal—Pancheshwar on the Sarda, Karnali on the Ghagra, Sikitaron the Rapti, Nurthose on the Bhagmati, Chisapani on the Kamla Balan, Barakshekhtra or Kharar on the Kosi. All these have been investigated. But unless the dams are constructed, the problem will not be solved. The problem of floods in Eastern U.P. and North Bihar will not be solved unless these dams are constructed and completed in the next decade. I would submit the hon. Minister has to look into these seriously if we want to reduce the flood damage in north Bihar.

There is one aspect on which I would like to give a warning. That is in regard to Kosi barrage. When the Kosi Project was constructed, it was assumed that it will solve the problem for 25 to 30 years. 20 years are over. It is therefore, necessary to examine how far the Kosi Project will give protection. We have to take levels of the bed of the river to find out the amount of siltation that has taken place, and to find out as to what extent the barrage has lost its value. The whole area protected by the Kosi Project is very prosperous. To continue in prosperity we have to take up, if necessary Barrage at Kharar or Barakheshtra dam. Any construction will take 10 years. Therefore, we should not be complacent about Kosi. It is a dangerous river. We have to make a special study and we have to take steps in time. I would suggest that the Centre and the State must take steps to see that the study of this river is made in depth. Various alternatives have to be investigated, lest we should be taken by surprise.

Ganga is a good river. But it causes serious erosion. The erosion is at Balia (U.P.), Mansi (Bihar) and Dhulia (West Bengal). At all these places the river is attacking the banks seriously. We must have a comprehensive study of the river system in those reaches. Unless it is tackled now, more serious problems will arise.

In South Bihar the rivers are comparatively much smaller but they can

cause great suffering to the people. The Sone river rises at a great height. Pumpun and Sone cause a lot of trouble to the southern areas. Intensive study is required to draw up a suitable solution.

An intensive study should be made in this regard because south of the Ganga, the areas between Monghyr and Patna are some of richest tracts in the country. If Bansagar dam in the river Sone is constructed, them the Sone can be controlled. We will be able to save Patna city from frequent floods and, to a certain extent, reduce the flooding in the Thal area.

I would like to emphasise that the Ganga basin is most important. As rivers come from Nepal side, it is necessary to take it up with Nepal Government for permission to construct reservoirs which will be beneficial not only to us but also to Nepal. You should send the Minister for discussion. This has been pending for a long time and so we should take this up in a systematic manner and discuss with them to find a solution. Mere writing of letters will not do. I have also said that instead of having committees on the general flood controls, we must have a study team to make a detailed study of some of the problems that I have mentioned just a while ago. That is the best way to deal with serious problem of erosion and inundation.

In Assam, one of the first priority that we should do is to strengthen the embankments already constructed and bring them to the standard.

We should also fill up the gaps with banks built to the proper standard. In Subansari, there is a good site where granite rock is found and a dam can be constructed on the river Subansari. Also we should try for the construction of a detention reservoir in the Tibet area. We should take up the matter with the Chinese government as they are now friends to this country. We should negotiate with them for taking up the investigation for controlling the floods. Chinese are experts in tackling flood problems. Then only the problem of flood in Assam valley can be overcome.

In the northern parts of the country, in the Ganga and the Brahmaputra, it is necessary to establish flood fighting units. At the moment we get the help of the army units when the floods actually occur. That is not so efficient. What we should do is to organise two units—one for the Ganga basin and the other for the Brahmaputra—to swing into action during the monsoon period. They must be equipped with helicopters, launches etc. to be stationed in the basin to deal with any contingency that may arise in these months.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति जी, प्रकृति के प्रकोप पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इस देश की सारी खेती यानी काश्तकारी प्रकृति पर आधारित है। इसलिए हर साल कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ें आती हैं और कहीं अनावृष्टि से सूखा हुआ करता है।

अभी आप के सामने बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और दूसरे प्रदेशों के बारे में कहा गया। मैं भी थोड़े से समय में आप के सामने मध्य प्रदेश की आज की जो दशा है वह रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का एक संभाग रीवा संभाग ऐसा है जो हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है। डा० के० एल० राव जी ने अभी जो आप के सामने कहा कि बानसागर बांध बना दिया जाए, तो उस से पटना की भी रक्षा होगी और रीवां संभाग को भी पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा संभाग छत्तीसगढ है, जिस के दो डिवीजन हैं एक बिलासपुर और दूसरा रायपुर। इन में सात जिले हैं और धान के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र प्रख्यात है लेकिन इस साल यह भय है कि वहां के लोगों को भी चावल खाने को नहीं

[श्री नीतिराज सिंह चौधरी]

मिले। वहां की हालत खराब है और बहुत दिक्कतें हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही दशा नर्मदा खंड के जबलपुर संभाग, भोपाल और इन्दौर संभाग की है विशेषकर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, रायसेन जिलों की। वहां पानी बेमौके और इतना कम पड़ता है कि वहां की जमीन सूख गई और कचरा भी खत्म नहीं हुआ। लोगों ने बार बार बोने की कोशिश की लेकिन बड़े बड़े डले निकलते हैं और पानी नहीं है। लोग बो रहे हैं, बहुत सी जमीन पड़ी रह गई है और जो बोई है पता नहीं वहां कुछ होगा भी या नहीं।

मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख हैक्टेयर जमीन काश्त में आती है जिसमें से 17 लाख 33 हजार हैक्टेयर में पानी की व्यवस्था है यानी 9 प्रतिशत केवल सिंचित है जबकि राष्ट्र की औसत 23 प्रतिशत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में देश का 15 प्रतिशत पानी है जबकि जमीन उस से बहुत कम है। 15 प्रतिशत पानी जो मध्य प्रदेश में है, उस का एक-तिहाई हिस्सा भी काम में लाया जाए, तो मध्य प्रदेश ही क्या, उस के साथ लगे हुए दूसरे हिस्से भी सिंचित हो जायेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि बानसागर बांध से रीवा संभाग सिंचित हो जाएगा और जो दूसरी नदियां हैं जैसे महानदी और बानगंगा, इन से छत्तीसगढ़ का संभाग सिंचित होगा। अगर बरगी बांध को स्वीकार कर लिया जाता है जिस में कोई कठिनाई नहीं है, तो नर्वदा की तलहटी में जो चार, पांच जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर वगैरा, उन में सिंचाई हो सकती है और सारी की सारी समस्या हल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 8 लाख 33 हजार कुएं हैं जिन में से 1 लाख 81 हजार कुओं में बिजली है, 85 लाख कुएं डीजल से चलते हैं और 6 लाख 67 हजार कुओं पर कुछ भी नहीं है। अगर भूगर्भीय पानी का उपयोग इन कुओं को इनरऊाइज करके किया जाए, तो बहुत उत्पादन बढ सकता है। इस साल की परिस्थिति यह है कि पानी नहीं है। पानी नहीं है तो दाना नहीं हो सकता और दाना नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा। जो काश्तकार जबरदस्ती बो भी रहे हैं उस में उत्पादन पानी न होने की वजह से नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक निश्चित योजना होनी चाहिए, जिस योजना के आधार पर लाभ हो सके और वह लाभ निश्चित हो, हमेशा के लिए हो और क्षणिक न हो। मेरे क्षेत्र में बाढ़ भी आई है और डा० राव जब सिंचाई विभाग के मंत्री थे, उन्होंने बाढ की व्यवस्था के लिए आदमी भेजे थे। उन्होंने देखा है कि बांध बनाने की वहां पर जरूरत है। बांध ऐसी जगह बनाने पड़ते हैं जो ऊंचाई पर हो। जो नीचे के लोग होते हैं, उन को हमेशा खतरा रहता है और जैसा कि शंकर दयाल सिंह जी ने कहा कि पटना के बचाने के लिए एक करोड़ लोगों को डुबो दिया गया, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यह कह रहा था कि अगर एक निश्चित चीज करें और योजनाबद्ध तरीके से उस को करें तो हमेशा के लिए लाभ होगा और जो पैसा खर्च होगा उसका लाभ सामने आएगा और अधिक लाभ लोगों को मिलेगा।

छत्तीसगढ की जो विशेष परिस्थिति है और उस में 7 जिलों की स्थिति इतनी विषम है कि सही जानकारी के लिए वहां पर केन्द्रीय दल भेजने की बहुत जरूरत है। जा कर के पूरे सातों जिलों में नहीं घूमेगा तब तक पता नहीं चलेगा। यह बात ठीक है कि देश के दूसरे भागों में अन्न पैदा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में न खरीफ और न रबी होगी और दूसरी जगहों से आप को अन्न भेज कर लोगों की उदर पूर्ति करनी होगी। लेकिन यह कोई स्थाई हल नहीं है। दल जा कर के वहां की वास्तविकता का ज्ञान करेगा और उसके बाद जो कुछ भी निर्णय होगा वह ऐसा होगा जिस से हमेशा के लिये उस क्षेत्र को और देश को लाभ हो सकेगा

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : चेयरमैन साहब, मुझे बहुत वक्त नहीं लेना है क्योंकि मैं फेक्ट्स पेश करना चाहता हूं। राव साहब नें बढिया तकरीर की है जिस में मुखतलिफ पहलुओं को, दक्षिण से ले कर पंजाब तक की सारी बातें कह दीं। मुझे इस बात का खेद है कि यह स्कीमें बहुत देर की पड़ी हुई है और वह उस वक्त की हैं जब कि राव साहब मंत्री थे। पैसा उस वक्त कम लग सकता था और आज ज्यादा लगेगा। आप पहले पैसा दस्तयाब कर सकते थे लेकिन अब पैसा नहीं मिल पायेगा। इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि बाढ को रोकने के लिये तो कम से कम बन्दोबस्त करे। बारिश नहीं होती इसलिये सूखा पड़ता है। अगर आप सूखे का इंतजाम नहीं कर सकते तो गल्ला देश के दूसरे हिस्सों से लाइयेगा, लेकिन बाढ तो हर साल आती है और सारी फ़सल को बरबाद कर देती है। इसलिये बाढ को रोकनें की स्कीमें तो जरूर लागू करें। इस को आप अगर कुछ हद तक ही कर पायें तो भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि बाढ सब कुछ बरबाद कर देती है। पंजाब के बारे में शायद किसी को पता न हो, वह एक बार्डर का इलाका है और इस बार वहां सब से ज्यादा बाढ आयी और दरिया नें सब चीज को खत्म कर दिया। लड़ाई के वक्त हम आदमी देते हैं, वहां से लोग उजड़ते हैं, नई जगह बसते हैं और वहां जमीन को फ़िर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बाढ आ जाय तो सरकार क्या तवज्जह देती है? इसलिये मेरा कहना है कि आप कम से कम जितने बाध पड़े हैं उन को पूरा करें। आप का थीमडैम अभी भी पड़ा हुआ है, उस की तरफ कोई तवज्जह नहीं दे रहा है। कभी किसी ने इस बात को अच्छी तरह नहीं लिया। जितनी देर हो रही है उतना रुपया ज्यादा खर्च होगा और फ़िर कहेंगे कि रुपया नहीं मिल सकता है। इसलिये इन बातों की तरफ आप ध्यान दें।

राव साहब ने बड़ी अच्छी बातें कह दीं, उन का एक चौथाई हिस्सा भी पूरा कर दिया जाय तो बड़ा अच्छा रहेगा। मंत्री महोदय आप के विभाग में कोआर्डिनेशन की सख्त जरूरत है। आप के विभाग में माइनर इर्रीगेशन आदि की एक गैल मुकर्रर होनी चाहिये ताकि फौरन ही खराबी को दूर कर सकें। 20 पौइंट प्रोग्राम में दिया हुआ है कि 5 मिलियन हैक्टर जमीन खेती के नीचे लानी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो जमीन बाढ की वजह से जा रही है उस को तो बचा लीजिये। इस से आप की पैदावार बढेगी। हमेशा तो बम्पर फसल होने वाली नहीं है, कभी खराबी भी आ सकती है इसलिये जो फसल बाढ से बरबाद होती है उस को रोकिये। सारे बांधों को बना कर अगर आप उस पानी को रोक सकें जो आये साल बरबादी करता है तो आप का काम और ज्यादा आसान हो जायगा और आप की प्लानिंग दुरुस्त होगी। प्लानिंग कमीशन और फाइनैन्स मिनिस्ट्री से मिलिये और पैसा लीजिये। हम हर साल इस हाउस में बहस करते हैं, पानी ऊपर से आता है, सूखा बारिश न होने की वजह से पड़ता है, इन सब का बन्दोबस्त अगर आप इस साइन्टिफिक ऐज

[श्री दरबारा सिंह]

में नहीं कर सके तो कब करेंगे। इसलिये आखिर में मेरा यही कहना है कि आप इस बाढ़ को रोकने का इंतजाम कीजिये।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Chairman, the natural calamities have become a normal feature in this country because of the vastness of the country and also because of the change in the monsoons. I do not think any year has passed when the Parliament has not discussed this matter. So, I would seriously suggest that there should be a Minister Incharge of Natural Calamities so that he may coordinate and see that floods which have become an annual feature, are minimised as far as possible. The permanent or semi-permanent solution for floods and drought should be this. We have suggested, while discussing the Constitution 44th Amendment Bill that irrigation and power should be included in the Concurrent List. We have seen how river water disputes have caused havoc in this country. For years together they remained unsolved, whereas water was going into the sea; and we were not able to utilize it. I would suggest that river water and irrigation, which are national assets, be included in the Concurrent List.

Dr. K. L. Rao, who spoke earlier, suggested a number of flood relief schemes for being undertaken in this country. I suggest that gigantic projects like the linking of the Ganga with the Cauvery have to be taken up—the sooner they are taken up, the better it will be, because thereby floods will be controlled and water also made available to the drought-affected areas irrespective of their geographical location.

In Andhra Pradesh, we had an unprecedented drought this year. Even in the coastal districts which used to receive bountiful rainfall, the rivers have become dry; and the south-east and north-east monsoons have failed.

I now come to my area, viz. Rayalaseema which is notorious for its drought and famine. It receives only 20 inches of rainfall a year; and that too is erratic. We experienced a critical situation this year. Never during the last 50 years did we face such a terrible drought; and there is scarcity even of drinking water. I request Government to take serious notice of it. Some relief works of a permanent nature should be taken up to eradicate drought and famine in this area. A memo. has been submitted to the Prime Minister; and I am repeating it on the floor of the House, that the work of taking Krishna water from the Srisailam hydro-electric project to put into execution. After the Bachawat Award, the State Governments have been given the liberty to utilize water allotted to each State, in whatever manner possible. There has been a consistent agitation from the people of Rayalaseema that the waters of Krishna which flows by the side of that territory, should be made available to them.

In this context, there is a demand from the people of Madras City, a population of 4 millions, that since they are suffering from lack of drinking water, the Krishna water should be made available to them. The only way that water could be made available to them is by conversion of the present Srisailam project into a multi-purpose project. The flow of water is to be taken through Rayalaseema, so that it can be supplied to Madras City. I request the Central Government to take advance action to supply water to Madras city through Rayalaseema. Channels through right bank and left bank are proposed to be dug in this area. If these two channels are dug,—which are 200 miles in length—many thousands of labourers will be involved. It is not only a relief work; it is also a productive work. The same is the case with Telengana, where there is a severe drought; and the Andhra Pradesh Government is tak-

ing all possible steps, within its financial limitations, to ward off famine in the State. Unfortunately this year the Godavari barrage has breached the delta. The granary of the country, the Godavari delta, is also facing a serious problem. Huge amounts have to be spent for early construction of a Barrage across the river Godavari so that the food production may not be affected.

Another important thing is that some of the Rayalaseema districts and also some of the Telengana districts are being calssified as drought-prone areas and there is a D.P.A.P. programme in operation in those areas. The D.P.A.P. programme will go a long way because it is a programme under which minor irrigation works are undertaken, underground water survey is undertaken, contour bunding and soil conservation works are undertaken and afforestation and tree plantation works are undertaken. I would request the Central Government to allot more funds for D.P.A.P. programme so that all these schemes can be taken up.

As regards afforestation, because of lack of afforestation and denudation of forests, the situation that we are facing specially in Ralayaseema area, in Anantpur district, the scientists have prophesied that in the course of 30 to 40 years, the entire district will be converted into a desert. We have to stop this calamity. Serious steps have to be taken so that the people are relieved from these drought conditions. This recurring phenomenon of drought has to be stopped. The Central Government must give massive assistance to the State Governments so that they may carry out coordinated works so that they do not come again and again before Parliament to ventilate their grievances and say that flood and drought have not been eradicated.

I once again reiterate that there must be a Minister incharge of Natural Calamities who should coordinate the efforts of all the State Governments and that irrigation and power be included in the Concurrent List.

*SHRI MANORANJAN HAZARA (Arambagh): Mr. Chairman, Sir, I had been listening to the debate going on in the House with great attention. I want to say that our country is not the Phillipines or Japan. Ours is a vast country. In my State that is West Bengal, Midnapur, the 24-Parganas and the Sunderbans are inundated by the sea water. All our rivers are not able to carry the discharge of water in them. There are floods everywhere and after the floods come drought. I will not say that all the schemes undertaken by the Government have proved useless or ineffective. I will rather say that several plans of the Government have brought much beneficial results. After the construction of the Farakka Barrage, the port of Calcutta has no doubt been benefited. But some defects remain in that plan which has not been rectified. The port of Haldia has not benefited from the Farakka Barrage. Due to some defects in the plan a large area of Murshidabad remains inundated in water all the time. So we see that we are constantly troubled by floods on the one hand and drought on the other. If we are to fight out this twin challenge then this department of the Government will have to remain extra alert and this department of the Government will have to be thoroughly reorganised and recast to meet the challenge effectively. There must be proper coordination amongst the administrative Ministries. When Dr. K. L. Rao was the Minister Incharge, he had accepted the scheme suggested to him by us. But unfortunately that scheme could not be implemented for want of funds. Then we approached the Minister of Finance, Shri Chavan.

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Manoranjan Hazara]

Shri Chavan said that if the Planning Commission gives priority then funds could be made available. At that time Shri Subramaniam was the Planning Minister, he sanctioned the priority. So the priority came, funds were allotted and the Lower Damodar project took shape. From the speeches of the various Members in the House today you have heard what is the situation in which the Lower Damodar project finds itself. All the excess water of the rivers of Bihar starting from Pun Pun Phalgu, Karmanasha and the Damodar are mare to pass through the area covered by the Lower Damodar Valley scheme and the entire area is flooded. In this connection the Chief Engineer of the West Bengal Government hit upon an ingenous plan that if dams were constructed on both sides of the Mundeshwari river then the whole problem of flood waters will be solved. The real thing is that there was a conspiracy with the contractors. In the original plan the construction of dams on this river was no-where contemplated. When we came to know of the fantastic scheme of the Chief Engineer, we met Babu Jagjivan Ram and Shri K. C. Pant who controls the DVC scheme, and told them that the floods of the Damodar river cannot be controlled through dams. The British Government tied down the Damodar river with five vicious chains but even then they could not contain the floods and even in 1943 we saw devastating floods in that river. Ten feet of sand and the railway tracks were thrown at a distance of ten miles by raging floods waters. This river cannot be held in check through dams. The excess water will have to be made to pass through scientific methods. When we apprised the hon. Minister of the situation and stood on somewhat firm ground the Chief Engineer of West Bengal surreptitiously constructed a dam on the Damodar river at the point where the Damodar and the Mundeshwari rivers bifurcated. As a result of this the excess water was made to pass through the Mundeshwari river. The flood waters of Patna were discharged in that river as a result of which over five lakhs of people were washed away by the flood waters. All their houses and fields were completely submerged. Through this cruel game the Chief Engineer only tries to prove his point of view i.e. how necessary it was to construct dams on the Mundeshwari rivers. I went to the spot and talks to the SDO of DVC I asked him why this out-of-the-plan dam has been constructed which brought devastation to millions of people and demanded that the dam may be immediately demolished. After that dam was demolished the flood waters went down and the people heaved a sigh of relief. The Government should understand that our scientific and practical outlook is much superior to the plans chalked out by a band of dishonest and corrupt officers of the Government who only feed their self-interest and greed. That is why I demand that this entire department entrusted with control of floods must be wholly reorganised and recast with honest and sincere people incharge of planning and execution. When we apprised Babu Jagjivan Ram of the whole situation, he understood our point of view being highly practical and sincere person. We placed the following charter of demands before him:

1. That the remaining four dams of the D.V.C. be constructed at an early date.

2. From Salimabad near Begua where the Damodar bifuracte from Mundeshwari the entire bed of Damodar be excavated.

3. A sluice gate be constructed at Begua point.

4. The Rupnarain be excavated because it has already lost its capacity to carry water.

The level of the Rupnarain river where the Mundeshwari falls into it has become so high that the waters of the Mundeshwari cannot easily flow into the Rupnarain. Therefore all the people living in this area are mostly inundated by the river water. In these circumstances I will again appeal to the Minister to reorganise their flood control department with knowledgeable and sincere persons. Ficklemindedness of the Government must be removed for with. At one time you are attaching irrigation with the department of Power, then again you are joining it with "Energy". This sort of madness was unknown to me previously. I am in the legislature for the last 26 years and I have never seen any sensible Government indulging in this sort of madness and thereby bringing untold misery and suffering for the people.

Now, Sir, speaking about drought, I can at least speak about West Bengal with authority as I do not have personal experience of other parts of the country. In West Bengal about two crores of people are affected by drought. In the near future a vast area will soon become the playground of vultures and jackals who will feed on the dead. There are no crops worth the name to harvest. This is the actual situation. I will therefore appeal to the Government to reorganise their entire machinery to fight drought with alertness and a scientific approach. There is no other way to fight the dreadful menace effectively. Sir, this is a matter where politics must not find any place. Let us join hands to fight this challenge with a view to lessening the sufferings and miseries of the people. Let us try to save our country together. The opposition is being asked to extend their hand of cooperation. It is said that the opposition is not willing to cooperate with the Government. But Sir, this matter of flood and drought is much above politics. Politics must not be allowed to play with the sufferings of the people. This is a field where the opposition and the Government must join hands and I am inviting your active cooperation to save the people. You come with us we will take you to every district and village and show you what is needed and where. Let all your engineers and administrators come with us we will show them all the deficiencies and the requirements and extend all help to overcome them. Let us fight together these menacing natural calamities and we will surely succeed.

✓ SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): Sir, I rise to speak about the unprecedented drought situation in Kerala, the details of which have already been given in a memorandum by our Chief Minister to Shri Jagjivan Ram dated the 28th September, 1976.

Because of the continued drought situation in Kerala, the farmers, agricultural workers and others connected with agriculture have been put to great hardship. The drought situation has seriously affected the agricultural production and rendered unemployed thousands of workers for whom seasonal agricultural operation is the sole means of livelihood. The quantum of labour employment opportunities lost due to drought conditions in terms of mandays have been roughly assessed as 78,79,448 men and 89,02,753 women.

In order to give some immediate relief to the farmers and agricultural workers, the State Government, in spite of difficult way and means position, has taken certain measures. They have decided to provide 25 per cent fertilizer subsidy to the farmers who lost their paddy crops completely so as to help them to some extent to raise the next crop.

The Kerala Government has suggested certain measures. I will briefly enumerate them: distribution of plant protection sprayers among the agricul-

[Shri C. H. Mohamed Koya]

tural workers who have suffered loss of work due to drought; subsidy of Rs. 75 per hectare for the entire additional area brought under pulses cultivation during the rabi season; operational subsidy for plant protection aquipment to the farmers during the rabi (including summer) season; famine relief works; minor irrigation; reimbursement of fertiliser subsidy. The State Government has sanctioned fertiliser subsidy amounting to about Rs. 20 lakhs. This was done in the expectation that the amount would be reimbursed by the Government of India. But, unfortunately, this has not been done so far.

The proposals mentioned above involve a total amount of Rs. 393 lakhs. The relief schemes proposed are very modest considering the loss suffered, These proposals havs been recommended in the hope that the Government of India will approve them in *toto* and sanction a grant outside the Plan allocations, as has been done in the case of other drought-affected States.

We would also like to request the Government to allot an additional amount of Rs. 3 crores as short-term loan for the purchase of inputs. The amount of Rs. 2.75 crores already provided has almost been completely utilised, and requests for additional funds are coming from the farmers.

The drought situation in Kerala is very serious. Since we are far away from the Capital, we should not be neglected, and that is why, to bring it on record, I have risen to speak.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Mr. Chairman, Sir, the first four Five-Years Plans and the Fifth Five Year Plan, which is in operation now, have not mitigated the drought hazards of Orissa, and Dr. Meghnad Saha's recommendations have not been implemented so far in order to prevent floods. Today, in Orissa, we are facing a very very critical and grave situation and it can be assessed from certain facts and features. For drinking water, cross bunds are put and in certain other places, embankments are cut for this purpose. From this, the seriousness of the situation can be well imagined. Further, in Orissa, 16 per cent of the total land is under irrigation for the last 27 years. Besides that, there is one single croping system there. From these two factors, you can imagine the extent of crisis which has been hitting the people of Orissa. And now a dry rainy season means destitution, scarcity and famine. Two crores of people in Orissa are faced with such a critical situation. Some newspapers had hinted of some hope of kharif crop, but the drought situation has dashed all that hope to the ground.

In view of the situation existing there, I would suggest that certain things need to be done immediately. Firstly, we should create employment opportunities through relief works. The State Government has also sent a note for certain developmental works. My demand is that the Centre should give an immediate and minimum assistance of twenty crores of rupees for this purpose. This does not, however, include the long-term plan. This is the short-term plan. Secondly, the collection of land revenue should be suspended. Thirdly, there should be distribution of gratis relief. The agricultural labour and certain poor people are not being given any work. They are facing starvation and death. Then, supply of drinking water should also be given top priority. Certain fair price shops should also be opened immediately. In spite of the declaration of Shri Jagjivan Ram, the prices have not been controlled. There should be rehabilitation programme for those people who are destined to destitution, I would not say, death. More rigs should be sent immediately. Minor irrigation projects should also be taken up immediately. There are certain inundated channels and we have been demanding that those channels should be brought under the irrigation system.

Sir, as far as reservoir projects are concerned, I need not enumerate them today. For that, the debate in the month of April 1974 as also another debate in 1972 can be referred to. We have exhaustively given the list there. Dr. K. L. R. Rao was the Minister then in 1972. I would not mention about those things today.

Now, the advance Plan assistance is under consideration. There are certain procedures and rules prescribed for that. As far as Orissa is concerned, I want that those rules should be relaxed and the Centre must come forward with suitable assistance to the State. The Centre must send its central team and money and other assistance must be rushed to save the people of Orissa.

श्री पी० गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : चैयरमेन साहब, जब से दुनिया बनी है, इन्सान को सैलाब, तुगयानी, सूखे और कहत के मसायल का सामना करना पड़ा है और उस के सामने ये मसायल दरपेश हैं। इन्सान की जिन्दगी के लिए गिजा जितनी जरूरी है उस से ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर पानी न हो तो इन्सान का जीना ही मुश्किल हो जाएगा।

सैलाब, बाढ, तुगयानी, या सूखा ये अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि आफ़ते आसमानी के अलग-अलग रूप हैं। जब बारिश की अकसरियत होती है तो सैलाब और तुगयानी आते हैं और जब बारिश कम होती है तो सूखा और कहत नाजिल होता है। मूल्क में 40 फीसदी पानी ब्रह्मपुत्र और उस के तावन में चला जाता है और उस का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाता है।

सैलाब की वजूहात बहुत सी बताई गई हैं और कम वक्त में ज्यादा बारिश का होना, नदियों की गहराई कम होना, ढलानों में मदाखलत और जंगलों का बेरहमी से तलफ़ किया जाना है। पहली आबपाशी कमेटी 1901 में मुनक़द की गई थी और उस ने यह कहा था कि हमारे मुल्क में 1170 मिलियन एकड़ फीट नदियों में पहुंचता है और दूसरी आबपाशी कमेटी ने यह बताया कि 4,500 एकड़ फीट पानी हम इस्तेमाल कर पाते हैं आबपाशी के लिए और हर साल हमारे मुल्क में औसतन 67 लाख एकड़ जमीन मुतासिर होती है, 193 लाख अवाम मुताहिर होते हैं, 735 जानें औसतन जाती हैं और तकरीबन 41 हजार मवेशी हलाक होते है और अन्दाजन चार हजार करोड़ रुपये का नुक्सान तुगयानी से हुआ है 1953 से 1974 तक और औसतन 168 करोड़ रुपये का नुक्सान सालाना हो रहा है। 1973 में 631 करोड़ रुपये का और 1975 में 471 करोड़ का नुक्सान हुआ है और मेरा अन्दाजा है कि इस साल इस से भी ज्यादा का नुकसान होगा।

यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस बारे में नेशनल फ्लड कमीशन का कयाम अमल में आया है। 13 रियासतों पर बाढ़ का असर पड़ा है और मैं उन की तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारे आन्ध्र प्रदेश में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और मेरे क्षेत्र में दवलेश्वरम् बेराज को नाकाबले तलाफ़ी नुकसान हुआ। इस बारे में मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं :

[श्री पी० गंगा रेड्डी]

बेसबब नहीं होती रुसवाइयां, कुछ हकीकत थी अफ़साने में।

वहां पर जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार को पूरी तवज्जह देनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली तीन पंचसाला प्लानों में औसतन 13 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और 1966-69 में 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 1972-73 में 318 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह बहुत कम है।

इस बाढ़ के जमाने में हमारी फौज ने तुगयानी का मुकाबला करने के लिए बिहार में और दूसरी जगहों पर काबिलेनाज खिदमत की है और इस के लिए मैं अपने डिफेन्स मिनिस्टर श्री बंशी लाल को मुबारकबाद देता हूं।

अब जहां तक सूखे का सवाल है सूखा जब पड़ता है जब बारिश ग़ायब हो जाती है और हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सूखा पड़ा है और उस को उस का सामना करना पड़ रहा है। बरतानिया बहुत बड़े कहत की जद में है और यहां तक कहा जाता है कि ब्रिटेन में पानी की किल्लत है और उस को शायद बाहर से पानी दरामद करना पड़ सकता है। हिन्दुस्तान के 8, 9 सूबों में पूरी तरह से सूखा पड़ा है और हिन्दुस्तान के 380 अजला में से 74 को ड्राट प्रोन बताया गया है जिस के माइने यह होते हैं कि मुल्क का 20 फीसदी हिस्सा ऐसा है। डी०पी०ए०पी० को कायम कर के सरकार ने एक अच्छा काम किया है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इकबाल ने जो एक शेर कहा है उस को मैं आप को सुना दूं:

नहीं है नाउम्मीद इकबाद अपनी कुश्ते वीरान से।

जरा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी जरखेज हो साक़ी॥

मतलब यह है कि यहां की मिट्टी बहुत जरखेज है और इस को अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो यहां बहुत पैदावार हो सकती है।

अब आन्ध्र की क्या हालत है वह मैं आप को बताता हूं। मेरे क्षेत्र आदिलाबाद में फसल खड़ी सूख रही है और वहां निजाम-सागर रिजरवायर में पानी नहीं है। गन्ने की फ़सल पूरी तरह से मुतासिर है, रायलसीमा में मुतासिर है और दवलेश्वरम् बेराज टटने से बहुत नुकसान हुआ है। विजयानगरम में भी सूखा है और इस के बारे में मैं एक शर कहना चाहता हूं:

अपना क्या हाल है खुद हम को भी मालूम नहीं।

आप पूछेंगे तो फिर आप से शिकवा होगा॥

ड्राट के बारे में मैं कुछ सजश्चन्स देना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा जमीन को आबपाशी की सहूलियतें मुहय्या की जाएं। ज्यादा से ज्यादा फ़सल की पैदावार रबी और खरीफ की ली जाए और काश्त के तरीकों में तब्दीली की जाए। एग्रोनोमिक प्रक्टिसेज में तबदीली की जाए। कनजर्वेशन आफ़

स्वायल किया जाए ताकि नमी देर तक बरकरार रह सके। जरई मजदूरों को तमाम साल रोजगार मुहय्या किया जाए। ज्यादा जंगल उगाये जाएं और मौजूदा जंगलों को बेदरदाना न काटा जाए। ड्राट रसिसटेंट बीज निकाले जाएं। मौजूदा जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जायें। ज्यादा से ज्यादा बिजली फराहम की जाए। जो कुछ अभी तक किया गया है उस के लिए मैं बाबू जी को मुबारकबाद देता हूं और आखीर में यह कहना चाहता हूं कि गंगा, कावेंरी के बारे में स्कीमों को पूरा किया जाए जैसा कि डा० के० एल० राव ने कहा है। जिस तरह से भगीरथ ने भागीरथी को जमीन पर ला कर सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था, उसी तरह से हमारा यह महकमा भी करे तो बहुत अच्छा होगा और बाढ़ और सूखे का मसला हल हो सकेगा।

[شری پی گنگا ریڈی (عادل آباد) :

چیئرمین صاحب جب سے دنیا بنی ہے - انسان کو سیلاب ، طغیانی ، سوکھے اور قحط کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے - اور اس کے سامنے یہ مسائل درپیش ہیں - انسان کی زندگی کے لئے غذا جتنی ضروری ہے - اس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے - اگر پانی نہ ہو تو انسان کا جینا ہی مشکل ہو جائیگا -

سیلاب بارش، طغیانی یا سوکھا - یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں - بلکہ آفت آسمانی کے الگ الگ روپ ہیں - جب بارش کی اکثریت ہوتی ہے تو سیلاب اور طغیانی آتی ہے - اور جب بارش کم ہوتی ہے تو سوکھا اور قحط نازل ہوتا ہے - ملک میں ۴۰ فیصدی پانی برہم پتر اور اس کے تعاون میں چلا جاتا ہے - اور اس کا استعمال ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے -

سیلاب کی وجوہات بہت سی بتلائی گئی ہیں - اور کم وقت میں زیادہ بارش کا ہونا ، ندیوں کی گہرائی کم ہونا ، ڈھلانوں میں مداخلت - اور جنگلوں کا بے رحمی سے تلف کیا جانا ہے - پہلی آبپاشی کمیٹی ۱۹۰۱ میں منعقد کی گئی تھی - اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ۱۱۷۰ ملین ایکڑ فٹ ندیوں میں پہنچتا ہے - اور دوسری آبپاشی کمیٹی نے یہ بتایا کہ ۴۵۰۰ ایکڑ فٹ پانی ہم استعمال کر پاتے ہیں آبپاشی کے لئے اور ہر سال ہمارے ملک میں - اوسطاً 67 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوتی ہے - ۱۹۳ لاکھ عوام متاثر ہوتے ہیں - ۷۳۵ جانیں اوسطاً جاتی ہیں - اور تقریباً ۴۱ ہزار مویشی حلق ہوتے ہیں - اور اندازاً چار ہزار کروڑ روپئے کا نقصان طغیانی سے ہوا ہے - ۱۹۵۳ سے ۱۹۷۴ تک اور اوسطاً ۱۶۸ کروڑ روپئے کا نقصان سالانہ ہو رہا ہے - ۱۹۷۳ میں ۶۴۱ کروڑ روپئے کا اور ۱۹۷۵

[شری پی گنگا ریڈی]

میں ۳۷۱کروڑ روپئے کا نقصان ہوا ہے - اور میرا اندازہ ہے کہ اس سال اس سے بھی زیادہ کا نقصان ہوگا -

یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس بارے میں نیشنل فلڈ کمیشن کا قیام عمل میں آیا ہے - ۱۳ ریاستوں پر باڑھ کا اثر پڑا ہے - میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا - ہمارے اندھرا پردیش میں بہت بھیلکر باڑھ آئی ہے - اور میرے چھیتر میں ہیلمشورم بیواڑ کو نا قابل تلافی نقصان ہوا ہے - اس بارے میں میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں -

بے سبب نہیں ہوتی رسوائیاں
کچھ حقیقت تھی افسانوں میں

وہاں پر جو نقصان ہوا ہے - اس پر سرکار کو پوری توجہ دینی چاہئے - میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی تین پانچ سالہ پلانو میں - اوسطاً ۱۳ کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا تھا - اور ۶۹-۱۹۶۶ میں ۸۰ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے - اور ۷۳-۱۹۷۲ میں ۳۱۸ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے - یہ بہت کم ہے -

اس باڑھ کے زمانے میں ہماری فوج نے طغیانی کا مقابلہ کرنے کے لئے بہار میں اور دوسری جگہوں پر قابل ناز خدمت کی ہیں - اور اس کے لئے میں اپنے ڈیفینس منسٹر شری بنسی لال کو مبارکباد دیتا ہوں -

اب جہاں تک سوکھے کا سوال ہے - سوکھا جب پڑتا ہے - جب بارش غائب ہو جاتی ہے - اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں سوکھا پڑا ہے - اور اس کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے - برطانیہ بہت بڑے قحط کی زد میں ہے - اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بریٹن میں پانی کی قلت ہے - اور اس کو شاید باہر سے پانی درآمد کرنا پڑ سکتا ہے - ہندوستان کے آٹھ نو صوبوں میں پوری طرح سے سوکھا پڑا ہے - اور ہندوستان کے ۳۸۰ ضلعوں میں سے ۷۴ کو قرافت بتایا گیا ہے - جس کے معنی یہ ہوتے ہیں - کہ ملک کا ۲۰ فیصدی حصہ ایسا ہے یہ ڈی - پی - اے - پی کو قائیم کرکے سرکار نے ایک اچھا کام کیا ہے - اس لئے میں یہ عرض کرونگا - کہ اقبال نے جو ایک شعر کہا ہے اسے میں آپ کو سنا دوں -

نہیں ہو ناامیدا قبال اپنی کشتہ ویرانی سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی -

مطلب یہ ہے کہ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے؟ اور اس کو تھوڑا سا پانی مل جائے تو یہاں بہت پیداوار ہو سکتی ہے -

اب آندھرا کی کیا حالت ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں - میرے چھیتر عادل آباد میں فصل کھڑی سوکھ رہی ہے اور وہاں نظام ساگر ریزروائیر میں پانی نہیں ہے - گنے کی فصل پوری

طرح سے متاثر ہے - رائچل سما بھی متاثر ہے اور دلیشور بھرچ ٹوٹنے سے بھت نقصان ہوا ہے وجے نگر میں بھی سوکھا ہے - اور اس کے بارے میں میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں -

اتنا کیا حال ہے خود ہم کو بھی
معلوم نہیں -
آپ پوچھینگے تو پھر آپ سے
شکوہ ہوگا -

فارسٹ کے بارے میں میں کچھ سجھشن دینا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ زمین کو آبپاشی کی سہولتیں مہیا کی جائیں - زیادہ سے زیادہ فصل کی پیداوار ربی اور خریف کی لی جائے- اور کاشت کے طریقوں میں تبدیلی کی جائے -ایگرو اکانمک پریکٹشیز میں تبدیلی کی جائے - کنزرویشن آف سائیل کیا جائے - تاکہ نمی دیر تک برقرار رہے - زرعی مزدوروں کو تمام سال روزگار مہیا کیا جائے - زیادہ جنگل اگائے جائیں - اور موجودہ جنگلوں کو بے دردانہ نا کاٹا جائے - ڈرافٹ ریسسٹینٹ بیج نکالے جائیں - جو موجودہ زمین میں زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائی جائیں - زیادہ سے زیادہ بجلی فراہم کی جائے -

جو کچھ ابھی تک کیا گیا ہے اس کے لئے میں باہوجی کو مبارکباد دیتا ہوں - اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں - کہ گنگا کلویری کے بارے میں سکیموں کو پورا کیا جائے - جیسا کہ ڈاکٹر کے ایل راؤ نے کہا ہے - جس طرح سے بھاگیرت نے بھاگرتھی کو زمین پر لاکر سب لوگوں کے لئے ایک بہت اچھا کام کیا تھا اس طرح سے ہمارا یہ محکمہ بھی کرے تو بہت اچھا ہوگا- اور باڑ اور سوکھے کا مسلہ حل ہو سکے گا-

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति जी देश के कई भागो में इस साल सूखे की बजह से अकाल पड़ा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिलो में से 30-35 जिलों में भयंकर अकाल है जैसा कि पिछले 50 साल में नहीं पड़ा है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र कहलाता है जिस में सात जिले हैं, राजनंदगांव, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा आदि, इन जिलो में इस साल ऐसा भयंकर अकाल है जैसा कि शताब्दी में नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिला में अकाल नहीं पड़ा। इसी तरह से विन्ध्य प्रदेश के सहडोल तथा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, खंडवा तथा नरसिंह पुर में भी भयंकर अकाल है। इस का कारण यह है कि पहले थोड़ी सी जो वारिश हुई और जुलाई में बहुत कम बारिश हुई जिस की बजह से जो मक्का और बाजरा लोगो ने बोया था और ज्यादा वारिश अगस्त में पड़ने से उस की ग्रोथ नहीं हो सकी, और सितम्बर-अक्तूबर में बिलकुल वारिश नहीं हुई जिस की बजह से न खरीफ की फसल हो सकी और न रबी की बुवाई हो सकी। इसी कारण दोनो फसलें वहां नहीं हुई।

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

मध्य प्रदेश की सब से विचित्र स्थिति यह है कि देश में जितना पानी होता है उस का 15 फीसदी पानी मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस का उपयोग कम हो पाया है । अभी तक हमारे देश में भले ही 23 प्रतिशत जमीन में सिंचाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 9 प्रतिशत ही सिंचाई है । इसीलिये अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में अकाल अधिक है और गरीबी अधिक है । इसलिये मेरे कुछ सुझाव हैं ;

पहला सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार बहुत जल्दी ही छत्तीसगढ़ इलाके में जांच के लिये एक दल भेजे, और मैं तो कहूंगा कि हमारे मंत्री श्री शाहनवाज खां साहब, भी दौरा करें । मैं संसद सदस्यों को भी निमन्त्रण देता हूं कि जो भी वहां जाना चाहें जायें, हम उन की की पूरी मदद करेंगे जिस से वह स्वयं वहां की हालत देख सकें ।

दूसरा सुझाव यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत कम सिंचाई की व्यवस्था है इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक रकम मध्य प्रदेश को दें ताकि बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले जा सकें । कितने बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले जायें इस का अंदाजा शायद मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि कम से कम 30 लाख लोगों को वहां पर काम देना पड़े । इसी तरह से राशन की दुकानें भी खोली जायें जिन से गांव और देहात के गरीब लोगों को सस्ते दाम पर अन्न मिल सके । और इस साल चाहे जहां के भी पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी पहाड़ी क्षेत्रों में अकाल है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी अकाल है, अगर वहां सस्ती राशन की दुकानें नहीं खोली जायेंगी तो गरीबों को बहुत तकलीफ होगी ।

तीसरा सुझाव यह है कि छत्तीसगढ़ के इलाके के लिये रेलवे की एक बहुत बड़ी योजना है—राजरा से ले कर बस्तर तक इस लाइन पर काम इस साल से शुरू कर दें जिस से बहुत लोगों को काम भी मिलेगा और योजना का भी प्रारम्भ हो जायेगा ।

दुर्ग जिले में 1806 गांव हैं उन में से 311 गांवों में ऐसी फसल है जिस को कहा जा सकता है कि 8 आने फसल है और बाकी सब गांवों में दो, तीन या चार आने ही फसल है । इसलिये दुर्ग जिले के दो लाख लोगों को राहत कार्य देना पड़ेगा जिस के लिये आप को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिये । साथ ही मैं पुनः कहूंगा कि अधिक से अधिक संसद सदस्य वहां जायें और स्थिति को देखें ।

मध्य प्रदेश में एक करोड़ सत्तासी लाख हैक्टर जमीन में खेती होती है, लेकिन सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जितने भी सिंचाई कार्य वहां खोले जायें वह स्थायी खोले जायें जिससे सिंचाई अधिक और ठीक से हो सके । वहां पानी बहुत मिलता है इसलिये स्थाई सिंचाई के कार्य होने चाहियें । यही मुझे निवेदन करना है ।

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Hoskote): Mr. Chairman, Sir, if there are floods in some parts of the country, there is bound to be drought in other areas; it is depriving all these areas. Drought occurs in other areas. Unfortunately this year, the drought is concentrated in Karnataka and the adjoining Andhra and Telengana areas. There is drought also in some portion of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 80 per cent of rains is obtained in the months of November-December during north-west monsoon. It started right earnestly during this period.

The cyclone which is being formed to-day in the Bay of Bengal is going to give good rain there. What I want to tell you here is this. I have never seen as bad a year as this year in Karnataka. Sir, I had been in charge of this work for 10 years or so which my hon. friends, Shri Shinde and Shri Shahnawaz Khan is now doing. After ten years, I went to my State and there also I was in charge of the same work. I have gone round India for a number of times, when I was in charge of this work. So, I can say that I have never seen as good as the last year. In India we had not uniform rainfall but, fortunately, during the emergency, the rainfall is uniform all over India! This year itself in Karnataka and in the adjoining Andhra the rains have completely failed. It started well. Southwest monsoon started in June in right earnest in the first week of June in Kerala. There was a cyclone and it took away to Gujarat. Gujarat had floods in June. That never happens. There were some areas which were affected due to floods in Gujarat. That rain should have gone to Karnataka and Andhra. It has gone to Gujarat and northern parts of India. Fifty per cent of rains from Southwest Monsoon which should have gone to Karnataka and some parts of Andhra have completely failed. As a result of this, our first crop in Karnataka has completely failed. In northern parts of Karnataka the crops were so bad and because of drought the crops have failed. September-October rain has failed us completely. So, a team to assess the situation, Government of India sent their team. But, by the time the team came to assess the situation, it was not so bad. And so they submitted a report. On the basis of which, Government of India allowed them to have Rs. 7 erores out of which Rs. 3.5 crores only was released. In southwest monsoon, 80 per cent of the rain should have gone to Karnataka. Now the season is over. And the real situation will be known. So, my request is for the Centre to immediately send an official team to assess the real situation and see that funds are released by the Centre.

There was an attempt on the part of every State to see that whenever they come to know that Maharashtra was given Rs. 50 crores for famine, the others did not want to lag behind. So is the case with regard to Karnataka and Tamil Nadu. The Centre is very very wise now. They said that whatever they spend forms part of their Plan. So, whatever amount they are going to spend in the first five years, if they spend now to meet the famine situation, that will be met out of their own plan funds.

That has made the people not to cry wolf. Now, wolf has actually come. Somebody must put a stop to this. The situation is actually very bad and the Centre must send a team to the State of Karnataka and portions of Andhra and Rayalaseema as also Tamilnadu to assess the situation. North East monsoon is going to be good this year. Last year too it was not very bad. This year it is going to be good and we expect a good rain. If on the Central Team's recommendations, enough money is not released to these States to meet the situation, the poor people will starve. There is enough of food in India. To combat the drought situation something must be done. Money and food were lacking twenty years back when we were faced with a similar situation Now that is not the position. Something must be done to the State of Karnataka to meet this situation.

[Shri M. V. Krishnappa]

Only a few gruel centres were started here and there and small minor irrigation works were started. But today the country is in a position to meet the situation. My humble request is, start immediately relief works. Otherwise, the condition of the poor people will become very bad. Already thefts have started. The crops have failed and there is no fodder. The cattle have died in large number. The people have no work. So, there is increase in thefts. The difference between a civilised man and an uncivilised man is 10 meals. If a civilised person is made to miss one meal, he will start telling lies for the second meal. If he is made to miss five meals, he will start stealing. If he is made to miss 10 meals i.e. for 5 days together, he commits murder: So, a civilised man becomes an undivilised brute if he is made to miss his meals for 5 days. So, the poor people should be given earning power by providing them work. I hope the Central Government will immediately send a team to the south.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Sir, I entirely agree with what my friends from the south—Shri Venkatasubbaiah, Shri Ganga Reddy and others—have submitted. Even the Government of India's projects are not going on smoothly. Excepting projects in Haryana, the projects in all other States have been delayed for some reason or other by the Government of India itself, although the State Governments are anxious about their completion. After the plan is approved, sometimes due to non-availability of money, sometimes due to some technical reasons and sometimes due to other reasons, the projects are delayed.

The Godavari Projects was constructed by Mr Cotton at a cost of Rs 5 or 6 crores in 1852. They took just five years to construct it at a time when there was no electricity and no advanced knowhow. There was some damage to this in 1963 and the Mitra Committee was appointed. In 1965 they submitted their report. It was approved by the Government of India in 1970. That is the funny thing. Mr Cotton is regarded as God in Andhra Pradesh because he built this project. The East India Company thought why there should be drought in an area where there is enough water. So, an anicut was constructed. Mr Cotton constructed a dam in Tanjore also in 1848. After gaining that experience he was sent to Godavari delta. Even in those days our cultivators were exporting from Andhra Pradesh sugar to England, rice to Bourbon, England and France, gram to Bourbon, tobacco to various places, hemp to England and oil seeds to England and France. Without any irrigation facilities, electricity or technical facilities like now, they were able to manufacture these things with their skill and export them in those days.

They have exported sugar also. But in these days, with all the experience and money and the assistance of the World Bank, things are not moving fast. They have collected from the delta area nearly Rs. 7 crores for this project but this has been delayed by the Planning Commission. All projects, regardless of their size, are bogged down because of financial constraints. The State Government feels that the Centre has not supplied enough funds to carry out even vital projects like the Nagarjunasagar. Chief Minister Vengala Rao says: "Andhra is one of the leading States in the field of irrigation and agriculture. It is known as one of the river States of India. Seven lakh hectares of additional area can be brought under the major projects like the Nagarjunasagar, Pochampad etc. Provided additional central aid is made available." So, if the Centre can give us Rs. 100 Crores as loan or subsidy, we can provide food to the entire country. Today, nearly 40 people met the Prime Minister and submitted a memorandum. She said that she would consult the Central and State officials including the Chief Minister.

In our area, there is no drought but there is doubt, because we do not know when we will get the water. The State Government is trying its best to complete the project but funds come in their way. Therefore, I request the Central Government to provide sufficient funds to Andhra State to enable them to complete these projects.

MR. CHAIRMAN: There are 49 Members who want to speak and the time left is 155 minutes. So, each member can get 2½ minute if all of you want to speak. Otherwise, some of the Members may not got the chance because I will call the Minister at 6.30 sharp. Now, it is for the House to decide.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): It was quite unfair to give 20 minutes to each Member in the beginning....

MR. CHAIRMAN: For that, you can speak to the Speaker in his Chamber. I am concerned for the present.

SHRI D. N. TIWARY: Then give at least five minutes (*Interruptions*)

MR. CHAIIRMAN: At 6.30 I will call the Minister. If I give five minutes to each, I will go by the list. The discussion will be off exact at 6.30. Should I make it four minutes?

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. CHAIRMAN: All right, the consensus of the House is that I will give five minutes to each and I will go by the list. I will call the Minister at 6.30.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Every year when we come here, we do so to discuss the flood or drought situation. This Ministry has to measure the magnitude of the problem and study the vagaries of nature which are responsible for the sufferings of the people. There is no machinery set up by the government at present. I have been urging for a long time that there is no dearth in this country of natural resources. Water, manpower and lands are all available. Underground water is available, even in Karnataka. Only efforts have to be made to help people when drought hits them, and when floods are there. We have to complete the irrigation projects.

The 5th Finance Commission has discriminated against Karnataka. The flood and drought situation in Karnataka this year is the worst. The State Government has said that 13 districts have been affected. I know the position. Members of Parliament have visited the areas. The first team of officers has visited the areas. There is a demand that a second team should visit the areas. There is no point in demanding the visit of any team. When our officers are busy writing reports, people are dying; and cattle are dying for want of fodder and water. This Ministry must have a board for attending to natural calamities like famine, drought and floods. We must have a permanent machinery. We should have an all-India policy? You must create a Fund, to be used to meet such natural calamities. You should organize the relief activities through the Board. You can create a Famine Board or Floods Board. They can then operate directly. They can send experts and look into all the pending cases relating to irrigation, e.g. n Karnataka. Sufficient financial assistance has not been provided to Karnataka. You have provided Rs. 7½ lakhs. The magnitude of the suffering in the districts affected is such that not less than Rs. 1 crore are required for each district. You have to sustain the programme for 1½ years in Karnataka.

These things are taken very casually. Members voice their grievances, but their pleas are not taken seriously. The entire Karnataka is under the grip of drought. There is a mass exodus; people are going out to places where they can get work.

Even the Famine Code has not been changed. The rate of payment of wages to coolies has also not been changed. Government of India should come in a big way to help in these

[Shri K. Lakkappa]

matters, whether it is Karnataka that is affected, or any other State. A permanent machinery is necessary. It is not there now.

Every year you are allocating funds for works in the drought-affected areas. Have you measured the magnitude of the problem? Drinking water is available; but we are short of rigs. We are not able to supply them to the villages. People and cattle travel for miles to get water. My friend was saying that the price of beef has come down, because all the cattle are used by the butchers. A permanent arrangement should be there. It is no use sending any team. Adequate relief arrangements should reach our constituencies before we return there. People should be satisfied. We must understand the gravity of the situation. Measures should be taken expeditiously. Financial assistance should also reach drought-affected areas, in order to save the people and cattle who are suffering in Karnataka.

SHRI S. N. SINGHA DEO (Bankura): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for the opportunity you have kindly given to me to speak on the flood and drought situation in our country. We have seen that while in some parts of the country, there is devastation of floods and, on the other hand, there is an acute drought as a result of which the people are badly affected and are in a helpless condition. For instance, in the State of West Bengal, we find, that on the one hand, in north Bengal, there is a serious devastation of floods and a large number of people have been made homeless and helpless, on the other hand, we find that the western parts of West Bengal have become the victim of acute drought and the people there are in a very helpless condition.

Since the time at my disposal is very short, I would concentrate on the drought situation in my constituency, in the districts of Purulia and Bankura. In this connection, I want to draw the attention of the hon. Minister to the prevailing chaotic condition of the drought-affected people in the two districts of Purulia and Bankura which form part of my Parliamentary constituency in the State of West Bengal. This year, due to the failure of monsoon, the crops in a large number of fields could not be sown and, in some parts, where the crops were actually sown, due to the failure of rains, all the standing crops have withered away as a result of which a large number of small farmers, landless labourers and even middle-class farmers are in a helpless condition. I would, therefore, request the Government to help the affected people and allot more money to these affected districts of Purulia and Bankura in the State of West Bengal under the Drought-Prone Area Programme so that a large number of medium and minor irrigation schemes, wells, etc. could be taken up to ensure irrigation to the fields and more and more people could be provided with work so that they could earn their bread and save their family members from starvation.

The nationalised banks and cooperative societies should be directed to advance short duration crop loans and long-time agriculture development loans, etc. so that more and more small and medium irrigation projects, such as, embankment on flowing nalas and rivulets for storing of rain water for irrigation purpose to fight out the drought conditions could be taken up on a large scale.

I would also request for opening of gruel kitchens for the affected destitute people and supplying cooked food to middle class people on subsidised rates.

Further, I would request for the supply of ration to all categories of the people at Government fixed rates through the modified fair price shops.

In the end, I would earnestly request the Government to sanction and allot necessary funds for the implementation of the Upper Kansabati river and Darakesher River projects in the districts of Bankura and Purulia so that

the drought which has become a regular feature in this area might not recur again.

So far as I know these two projects have been approved. But the money has not yet been released. Due to this, the work on these two projects is not progressing rapidly. The result is that the lands which could have been irrigated are not getting the irrigation. I would, therefore, request the Government to move in the matter and release the funds for both these projects which have been approved so that the work on these two projects can be taken up immediately without any further delay.

*SHRI S. A. MURUGANANTHAM (Tirunelveli): Mr. Chairman, Sir, many hon. Members, who preceded me, referred to the ravenous drought ravaging many parts of our country. I would like, in particular, to refer to the serious drought searing many areas in Tamil Nadu from where I hail.

Tirunelveli, Ramanathapuram, Madurai, Salem, Coimbatore, Dharmapuri, North Arcot, South Arcot, Pudukkottai, Tiruchirappalli—these are the ten districts of Tamil Nadu afflicted by drought. The Tanjore district, which is traditionally known as Chola Nadu, and which is described as the Granary of the South, has become the victim of drought on account of the perennial river Cauvery not getting adequate water. Even according to the statistics supplied by the Government, 4121 villages in Tamil Nadu are afflicted by drought. The two Central teams which visited these areas have given a graphic account of the seriousness of drought in Tamil Nadu. Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, toured the arid zone of Tamil Nadu in order to have a personal assessment of the drought in Tamil Nadu. Besides her, some Central Ministers also visited these parched areas.

Tirunelveli, Ramanathapuram and Coimbatore, in these three districts in Tamil Nadu, the rains have failed in three successive years. The Palmyra tree which can withstand even acute drought and heat has started withering. The people of Tirunelveli district, whose livelihood is dependent upon this palmyra tree, have become destitutes. As the agriculturists could not get cattle-feed, they have sold and are selling their cattle, which is their mainstay, at distress prices—at 15 per cent or 20 per cent of the purchase price. I can go on enumerating the atrocious consequences of this natural calamity, but paucity of time prevents me from such gruesome narration.

With a view to tackling this awesome drought, the State Government formulated a programme with an outlay of Rs. 31 crores. In two instalments the Central Government gave a sum of Rs. 15.7 crores. The scarcity relief work is being done in digging 6300 drinking-water wells and such other employment oriented schemes. This is not enough. I suggest that greater attention must be paid to start cottage industries and small industries which would be of immediate benefit to these suffering people. Tamil Nadu is, in fact, equivalent to Panjab in regard to augmentation of agricultural production—it is about 4 per cent. You know, Sir, that Tamil Nadu is north of Equator and is dependent entirely upon South-west and North-east monsoons, which usually do not yield enough rains. I state this factor only to emphasise that the Central Government should draw up a permanent scheme for mitigating the effects of recurring droughts in Tamil Nadu. It is really a paradox that we are discussing the flood havoc in some parts of the country and also the drought affliction in some other parts of the country. If this recurring natural phenomena is to be eliminated from our national scene, the Central Government must start the implementation of the magnificent scheme of connecting Ganga with Cauvery. Covering a vast stretch of 3200 miles, the Soviet people have linked Volga with Don. Our technical experts are in no way inferior to those

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri S. A. Muruganantham]

in other countries. They can successfully connect Ganga with Cauvery, covering just 1600 miles. I am sure that the Central Government will come forward to implement this gigantic scheme with the willing cooperation of the people of this country, as this is their long-cherished dream.

Besides this, the State Administration should start negotiations with the neighbouring States of Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka for getting the much-needed water for Tamil Nadu. The former D.M.K. Administration in the State was interested only in propagating separatism and not in procuring water from the neighbouring States. I request that now the Central Government should take the initiative in this matter, as Tamil Nadu is being administered by the President.

During the great Dadhu year famine 100 years ago, as a drought relief work the Tirunelveli-Koilpati railway line was constructed. Now the Nellai-Kumari railway line scheme, which has been worked out with an outlay of Rs. 22 crores, must be undertaken forthwith with greater vigour and verve. So far only 30 per cent of the work has been done. This year only a paltry sum of Rs. 73 lakhs has been provided for this work. I need not say that this will be sufficient only to meet the wages of workers and salaries of the employees. If this work is to be completed quickly, it must be taken as a drought-relief work. This will generate employment to those undergoing uptold hardships on account of drought.

Before I conclude, I would like to stress the imperative necessity of drawing up some permanent schemes and programmes by the Central Government for saving Tamil Nadu from recurring drought.

With these words, I conclude.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): For the last 30 years, Government has been planning in a scientific way how to control floods and to eradicate drought in the country. But the difficulty is that people have been destroying the forests very indiscriminately, with the result that our forests have been reduced to fifty per cent. Also all the pastures have been brought under the plough. That is why, in the country these floods are coming, even twice a year in a State, and drought is also faced, alternately, in the same year. I do not want to create a panic by exaggerating anything. Our Chief Minister, Shri Vengal Rao, has sent a detailed report to the Government of India stating how the whole State is affected by drought. This year there was a breach also as was mentioned by my predecessor.

My constituency is a very fertile area and it contributes every year one lakh tonnes of rice to the Central Pool and one lakh tonnes of sugar besides oilseeds and other things. This year, on account of the failure of late monsoon rains, the current crops of paddy and sugarcane have not suffered much, but all dry crops have been completely lost; also, the future crop, i.e., *adsali*, which is planted in the month of June-July over 16,000 acres is adversely affected; the total investment on these 16,000 acres is roughly Rs. 10 crores, and this money will go waste. The people are feeling very much. The demands from my constituency are these: the whole amount which the people have suffered may be recouped either by the Government of India or the State Government; if that is not possible, the second alternative is that the interest on the bank loan may be waived and the amount may be recovered in easy instalments; if that is not done, the capacity of the peasants to grow paddy and sugarcane next year will be adversely affected, next year there will be no sugar season in my constituency, Nizamabad; the sugar production in our State will be less by one lakh tonnes. That is why, I am bringing this to the notice of the Minister.

My suggestion is this. The Godavari and the Manjire are the rivers which flow through my constituency.

During the last drought situation, Mr. Shinde had sanctioned two lift irrigation schemes on the Godavari in my constituency. Now there is scope for six more lift irrigation schemes. I would request the Minister to sanction money immediately, so that these lift irrigation schemes can be taken up and completed in two or three months. So is the case with the entire country. There are so many rivers flowing in this country, and the water should be lifted. Our Chief Minister has already planned to have about 100 to 150 lift irrigation schemes, but the finances in the State are limited, and our Chief Minister cannot take up more schemes. That is why I suggest to the Government of India to come in a big way. Let us have a final solution for drought. On the one hand water is being wasted by being allowed to flow into the ocean, and on the other hand our fields are starved of water.

Moreover, on account of the floods, the best surface soil, which is worth more than gold, is being washed away into the sea. A day may come when all the fertile fields of India may turn into a desert like Rajasthan. Already we are seeing that the desert of Rajasthan is advancing. Our young leader, Shri Sanjay Gandhi, has taken up the programme of afforestation.

17.00 hrs. ..

The Young Congressmen have taken up this challenge. But unless and until the Government comes in a big way to plant trees and afforest the entire country, these floods and drought cannot be stopped. The Prime Minister has been telling time and again that the reason for these droughts and floods is only deforestation. We would like the Government to take necessary steps in this direction in a big way.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश, देश का एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें हम समझते हैं कि दो-तिहाई भाग बाढ़ से प्रभावित है और इस बार इस प्रदेश में ऐसी जगह बाढ़ आई है, जहां कभी आती नहीं थी । महाभारत के समय में मथुरा में बाढ़ आई थी और उस समय भगवान कृष्ण ने उस क्षेत्र को बचाया था । उसके बाद अब फिर वहां भयंकर बाढ़ आई है जिसके कि वे आदि नहीं थे, इसलिये उनका जन-जीवन बड़े संकट में पड़ गया था ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हमेशा से प्राकृतिक आपदा के शिकार होते रहे हैं । बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर की बस्तियां भयंकर बाढ़ से प्रभावित हो रही हैं । बलिया और आजमगढ़ तो विशेष रूप से प्रभावित हुआ है । माननीय कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने स्वयं आंख से देख कर कहा था कि बलिया बरबाद हो गया है । पहले बलिया सूखे से बरबाद हो गया था और जो कुछ बचा था वह बाढ़ से नष्ट हो गया है । अन्दाजा यह है कि 95 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है । वहां हम समझते हैं कि अकाल की हालत हो गई है । वहां पर 'बेरिया' संसार टोला बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हो गया था, लेकिन वह आज तक नहीं बन पाया है ।

इसी तरह बकुलहा-संसार टोला बांध जो कि 1975 में बाढ़ से टूट गया था, वह अब 1976 की बाढ़ से एकदम साफ हो गया है । उसको पुनः बनाया जाये और जहां पर विशेष गंगा का कटान है, वहां एक रिटायर बांध बनाया जाये और गंगा के करीब जो छोटा सा बांध है, उसको और मजबूत बनाया जाये ।

भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव मेरे जनपद में आये थे और उन्होंने गंगा व घाघरा के कटान को देखा भी था । घाघरा प्रतिवर्ष 4, 5 गांव को काट देती है और गंगा ने भी कटान आरम्भ किया था लेकिन गायघाट पर डा० के० एल० राव

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

के सुझाव पर तटबन्ध बनने से वह कटान से बच गया लेकिन उससे आगे गांव मझउवां, जो कि 10 हजार की आबादी का गांव था, वह गंगा में विलीन हो गया। इसके लिये मैं तीन बरस से चिल्लाता रहा हूं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। हमारे सामने ही गांव चांदपुर, बलुआ, महाराज गंज इत्यादि घाघरा में विलीन होते गये हैं, अब तक हम उनको नहीं बचा सके हैं। अब घाघरा का दूसरा आक्रमण टोला फतहराय पर है। अगर इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जायेगा तो यह गांव भी विलीन हो जायेगा। चक्की चांदैरा भी घाघरा की चपेट में हैं।

मंगई नदी कोपाचीट क्षेत्र में बहती है, जो नरहीं से थोड़ा ऊपर चढ़कर गंगा में मिलती है। इस क्षेत्र के गांव पीपरा, कथरिया दौलतपुर इसकी भयंकर बाढ़ से बरबाद हो जाते हैं। इसने पूरे क्षेत्र को जल-प्लावित कर दिया है। अभी तक इस क्षेत्र में बुवाई नहीं होपाई है, क्योंकि पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बराबर गंगा कमीशन को कहने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। पहले पानी एक महीने में निकल जाता था, लेकिन अब 2, 2 और तीन तीन महीने हो गये पानी नहीं निकलता है। इसके बारे में कोई टैक्निकल एडवाइस लेकर रास्ता निकालना चाहिये। इसका दो-तिहाई हिस्सा जल से प्लावित था और एक-तिहाई में आज भी खेती नहीं हो पा रही है। इसमें पानी भरा हुआ है।

टोस नदी गांव जोरपुर, कोट, थमनपुरा, इन्दरपुर को काटती है। जहां पर वह गंगा से मिलती है, उसके मुंह को बन्द करने की बात आई थी, लेकिन वह कार्य अब तक नहीं हो पाया है। इससे कटान से बचाव की जो कार्यवाही हो रही थी, उसे बन्द कर दिया गया है।

हमारे उत्तर प्रदेश की सारी योजनायें गंगा कमीशन और प्लानिंग कमीशन से बाढ़ और सिंचाई के सम्बन्ध में स्वीकृत थे, लेकिन पैसा न मिलने के कारण ठप्प पड़ी है। ड्रेजर और रिग मशीन के न रहने के कारण ट्यूबवैल नहीं लग पा रहे है। और नदियों के पेट साफ़ नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बाढ आ जाती है और वाटर लॉगिंग हो जाता है।

मेरा सुझाव है कि डा० के० एल० राव के नेतृत्व में एक पार्लियामैंटरी कमेटी बने जो बाढ़ के सम्बन्ध में सारी स्थिति को देखकर प्रायटी के बेसिस पर समस्या का हल खोजे और यह भी देखे कि केन्द्र जो इस सिलसिले में पैसा देता है वह वहां खर्च होता है, उसका सही उपयोग होता है या नहीं।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Andhra Pradesh, Orissa and Punjab are the three surplus States so far as rice production is concerned and they contributed to the Central Pool to a great extent. But this year, I am very sorry to say that due to the lack of timely rain and more particularly, the most important rain of September which is so essential for the rice crop, in the western districts of Orissa and in some parts of Andhra Pradesh like the Srikakulam district, there is absolutely no water in the paddy fields which have developed cracks and the rice crop which we expected to be 18 annas harvesting is withering away and the entire field which should have been lush green by this time has started looking yellow. There is no flowering, nor pollination. We do not expect even half of our harvest.

This area witnessed the worst famine of the century in 1966 when the Prime Minister herself visited that area and saw the plight of the people there. Because there was too much excessive rain in the month of July—there was a cloud-burst and in one day there was a 13" rainfall—all the contour bunds were washed away, people could not transplant the paddy and the entire agricultural

operations were put into jeopardy. As a matter of fact, the entire agricultural operations were delayed and there being no rain in September, it had its adverse effect on the harvest.

The Orissa Government has already told the Centre that we are unable to contribute even one grain this year towards the central pool. Under these circumstances I most respectfully submit and Dr. K. L. Rao will bear me out as he knows the problem of that area, that small and medium irrigation projects are not going to solve the problem because if there is no rainfall in large areas and if there is no rain in the catchment area, the small irrigation projects and small dams will not be filled with water and will not be able to irrigate the command area. So, we must go ahead with major irrigation projects. As a matter of fact, the Upper Indravati project which will irrigate 5 lakh acres of chronically drought-affected Kalahandi district should be taken up in right earnest. It has now been cleared by the Central Water & Power Commission under the 20 point programme and now the inter-State water disputes are solved. It is pending before the technical advisory committee of the Planning Commission and I hope this month it will be cleared. We need resources for that. At that time it was estimated that it would cost Rs. 100 crores. Now everything has gone up and under the revised estimates it will cost anything like Rs. 220 crores. Wherefrom will this money come? The dice of the Fifth Plan have already been cast. A World Bank Team has today arrived in the capital and I most respectfully submit to the centre that they place this Upper Indravati project before them and try to get finance from outside or foreign collaboration because it has a vast potential for development. There is a vast deposit of Bauxite ore in that area—a 1000 million tonnes ore. 600 million tonnes in Orissa and 400 million tonnes in Andhra Pradesh. It is probably the second biggest deposit in the world, if not the biggest. There can be a big electro-metallurgical complex there. All this will need 240 MW of electricity. The country will be benefited by aluminium. The pumps will be energised by this scheme to irrigate fields. We will get water in the drought prone areas.

I respectfully submit to the Government that in the revised Plan, at least they can make a beginning with the Upper Indravati and the spill over will go to the sixth plan. It will not only benefit us but the entire country will be benefited.

श्री मूल चन्द डागा : (पाली) सभापति महोदय, एकक बात है कि सरकार फमिन की पालिसी को बदल दे। यह स्टेट सबजेक्ट है और सारे के सारे मैम्बर इस पर बहस कर रहे है। इन का कोई यह विषय नहीं। शाहनवाज साहब खड़े होंगे पीछे से और कहेंगे कि हम ने इतने करोड़ रुपये राज्यों को दे दिए। 27 साल केबाद तो आप अपनी इस एक नीति को बदलिए। 27 साल के बाद भी राजस्थान आज किस तरह अकाल की चपेट में रहता है और दूसरे राज्यों में भी अब आवाज करना शुरू कर दिया है। मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार यहां काम कर रही है, वह जहां चाहती है वहां पैसा बहाती है तो आज सब मैमोरेंडम ले ले कर आ गए जो राज्य सरकारों के बनाए हुए हैं। जो चीफ़ मिनिस्टर ने लिख दिया है उस मैमोरेंडम से सब पढ़ रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसी जगह है कि जो जितनी जोर से आवाज करेगा और शाहनवाज खां पर जितना ज्यादा जोर डालेगा वह उतना ही रुपया ले जायेगा। इसलिए यह बात हो रही है। आप जो काम करते है, मैं कहता हूं क्या जरूरत है इसकी ? राज्य सरकारें खुद अपना स्टडी करें। यह आप की स्टडी टीम क्या करती है ? जा कर डाक बंगले में ठहरती है, आराम से खाना खाती है, एक दो जगह जाती है। इस

[श्री मूलचन्द डागा]

स्टडी टीम पर हजारों रुपया खर्चा आता है। आज 27 साल के बाद आप यह नहीं कह सकते हैं कि कहां सूखा है कहां बाढ़ है? यह स्टडी टीम आखिर किसलिए भेजी जाती है सिक्स्थ फ़ाइनेंस कमीशन ने एक निर्णय लिया। मैं कहता हूं कि राज्यों को दे दीजिए यह अधिकार। ये राज्य आपसे लोन लें और अपना काम चलाएं।

जितना यह फ़ेमिन और बाढ़ आदि पर रुपया खर्च होता है उस का सही उपयोग रुपये में छः आना होता है। 40 परसेंट पैसा ठीक काम में आता है और 60 परसेंट इंजीनियरों और आफ़िसरों की जेबों में जाता है। यह इस का फ़न है। कहीं राजनैतिक बाढ़ आती है। यह बाढ़ की पालिसी आखिर क्या है? मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करे। जिस क्षेत्र में जितना अधिक रुपया खर्च किया बार बार उसी जगह खर्च होगा। डी पी ए पी का प्रोग्राम अलग मिनिमम नीड्स का प्रोग्राम अलग, क्रैश प्रोग्राम अलग, इतने प्रोग्राम चलाने के बाद भी और अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी सरकार आज फ़ेमिन और बाढ़ का मुकाबला नहीं कर सकती है। आज लोग आवाज़ कर रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है। आप फ़ेमिन में क्या करना चाहते हैं? फ़ेमिन कोड 1930 या 36 का बना हुआ है। कोई अप टु डेट फ़ेमिन कोड नहीं, कोई यूनिफ़ार्म पालिसी नहीं। अब लास्ट टाइम क्या हुआ? महाराष्ट्र के फ़ाइनेंस मिनिस्टर और महाराष्ट्र के ऐग्री-कल्चर मिनिस्टर थे, करोड़ों रुपया वहां चला गया।.... (**व्यवधान**). . . . इसलिए फ़ेमिन के मामले में कोई पालिसी हो। फ़ेमिन के वक्त में यह जो सस्पेंशन का कल्चर है, अकाल होता है या बाढ आती है, काश्त-कार उस का शिकार होता है तो आप का लैंड रेवेन्यू सस्पेंड किया जाता है। मैं कहता हूं सस्पेंड करना क्या है उस को खत्म करो। दो साल तीन साल के बाद उस की रिकवरी करते हैं और विद इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस को क्या लाभ हुआ? सोयल कन्जर्वेशन के वक्त यही होता है। कहते हैं कि सरकार भी खर्च कर रही है और तुम्हारा भी खर्च होगा। उस के बाद उस से रकम वसूल की जाती है।

मैं चाहता हूं छठे फाइनन्स कमीशन का जो तरीका है उसकी जगह पर कोई नया तरीका बनाना चाहिए। जहां तक हमारे राजस्थान का सवाल है, आप सिर्फ राजस्थान कैनाल बना दीजिए, फिर हम आपके पास नहीं आयेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज): सभापति, जी इस साल की बाढ़ और सालों की बाढ़ से भिन्न थी। हर साल लोग उम्मीद करते हैं कि जुलाई-अगस्त में बाढ़ आयेगी और उसके लिये तैयार भी रहते हैं लेकिन इस साल बाढ़ मिड-सेपटेम्बर के बाद आई। बिल्कुल अनअवयर्स लोग बाढ में फंसगये। उनको अनुमान ही नहीं था कि इस समय भी बाढ आ सकती है इसलिये उनकी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि उसको फेस कर सकें। जुलाई अगस्त में जब बाढ आती है तो बाढ़ के आने के बाद लोग खेतों में कुछ बो देते हैं ताकि कुछ पैदा हो जाये लेकिन जब मिड-सेप्टेम्बर में बाढ़ आती है तो फिर उसके बाद कुछ भी उपजाया नहीं जा सकता, उसके बाद सिर्फ रबी को फसल ही बोई जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि बाढ़ के सम्बन्ध में शहरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब भी कहीं किसी शहर में पानी आने की बात हुई तो चारों तरफ से, केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बेचैन हो जाती हैं

लेकिन कहीं देहात में बाढ़ आती है तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता । इस साल बाढ़ देखने के लिये मैं पटना और दूसरी जगहों पर भी गया । पटना की सरकार ने सोफा सेट और कुर्सियां तो बचा लीं लेकिन देहातों की जीविका को खत्म होने दिया । दूसरी बात वहां कही जाती है कि आपकी सरकार, क्या सेन्ट्रल और क्या प्रोविंशियल, अरबन ओरिएन्टेड है रूरल ओरिएन्टेड नहीं हैं । देहात वालों की झोंपड़ियों से पानी बह जाता है लेकिन कोई पूछता नहीं । अगर पटना में दो हाथ पानी भी आ जाये तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है । इसी बात से मालूम होता है कि हमारी सरकार अरबन-ओरिएन्टड है, रूरल वालों की ओर कम ध्यान देती है ।

तीसरी बात है फाल्टी प्लानिंग की । पटना शहर को बचाने के लिये आपने गांव बनाया, बहुत मजबूत और बहुत ऊंचा बांध बनाया । हर रिवर की दो साइड होती हैं । गैजेज में दक्षिणी इम्बैंकमेंट है और उत्तरी ईम्बैंकमेंट है । आपने दक्षिणी इम्बैंकमेंट पर पटना को बचने के लिये 10–12 करोड़ रुपया खर्च करके बहुत मजबूत बांध बनाया लेकिन उत्तर की ओर जो कगार है उस के लिये कुछ नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि पटना कगार से पानी बहकर उधर चला जाता है, उसको इधर स्प्रड करने की उत्तर में जगह नहीं है । इसलिये उधर मैनमेड फ्लड आ गया । एक फाल्टी प्लानिंग की वजह से उधर बाढ आ गई । इसलिये यदि आ,पको बांध बनवाना है तो एक तरफ ही नहीं दोनों तरफ बनवायें । अगर कहीं पर बंजर भूमि है या वहां पर कोई बस्ती और गांव नहीं है तो एक साइड में भी आप बांध बनवा सकते हैं लेकिन जहां दोनों साइड में बस्तियां हों वहां भी एक साइड में ही आप बांध बनवाते हैं तो दूसरी साइड क्या होगा? आपकी फाल्टी प्लानिंग की वजह से हम लोग मारे जा रहे हैं । अगर दूसरी ओर भी बांध होता तो पानी बीच से चला जाता और किसी को तकलीफ नहीं होती । यह उचित नहीं है कि एक ओर आपकी दृष्टि रहे और दूसरी ओर देखें भी नहीं । इसीलिये कहा जाता है कि आप अरबन ओरिएन्टड हैं और रूरल को बाई-पास करना चाहते हैं । ऐसी भावना लोगों के दिल में जमती जा रही है वह ठीक नहीं है ।

चौथी बात यह है कि आप जो रिलीफ देते हैं उसका देना न देना बराबर है । आप दो चार दिन का खाना दे देंगे और अधिक देने के लिये न आपके पास साधन हैं और न आर्गेनाइजेशन ही है । परमानेन्ट सल्यूशन के लिए आप नेशनल फ्लड ऐंड ड्राउट कमीशन बना दें जो कि हर प्रान्त में जाकर देख कि वहां पर क्या करने से बाढ़ रोकी जा सकती है और ड्राउट का किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है । वह कमीशन चारों तरफ घूम कर जो रिपोर्ट दें, सेन्टर उसकी इम्प्लीमेंट करें, एस्टेट पर इसको नहीं छोड़ना चाहिये । कारण यह है कि फ्लड को रोकना एक ही स्टेट के बस की बात नहीं है, वह इन्टर-स्टेट-लिंक्ड रहता है और जब लिंक्ड रहता है तो पानी का बहाव एक स्टेट में रहे, दूसरे को छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा । इसलिये नेशनल कमीशन की सिफारिशों का इम्प्ली-मेंटेशन सेन्टर के द्वारा हो ।

यही स्थिति ड्राउट की है । ड्राउट क्यों आता है और यदि आता है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाय? इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करके योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिये और समस्या का समाधान करना चाहिये । इस दफा बिहार में जहां सैकड़ों वर्षों से कभी बाढ़ नहीं आयी थी, वहां पर बाढ आई, उन लोगों को बाढ़ का कोई अनुभव नहीं था, इसलिये उनको ज्यादा तकलीफ हुई । हम लोगों के यहां बाढ़ आती है, तो हम उसको बरदाश्त कर

[श्री डी० एन० तिवारी]

सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बहुत बाढ़ों को देख चुके हैं, लेकिन जिनके यहां कभी बाढ़ नहीं आती, सितम्बर महीने में इस दफा उनके यहां बाढ़ आई, जिससे उनको हमसे ज्यादा दिक्कत हुई ।

श्री राम हेडाऊ (रामटेक) : सभापति महोदय, यह देश नदियों का देश है, किन्तु यहां का पानी फोकट में बह जाता है, बाढ़ आती हैं, हानियां होती हैं और दूसरी तरफ खेती को पर्याप्त पानी देने की योजना न होने के कारण खेती भी सूख जाती है, जिससे अन्न की बड़ी हानि होती है। इस वर्ष भण्डारा और चांदा जिलों में चावल की बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन बारिश न होने के कारण बहुत हानि हुई, जो 16 आने फसल होनी थी, वह करीब 10 आने ही रह गई। विदर्भ की स्थिति इस प्रकार की है कि वहां हर वर्ष सूखा पड़ता है। वहां देखा जाय तो वैनगंगा, बान गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं जो किसानों की फसलों को बहा कर ले जाती हैं, उन नदियों का उपयोग खेती के लिये नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र के लिये किसी भी योजना को—चाहे बांध की योजना हो या सिंचाई की योजना हो—कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं—वैन-गंगा प्रोजेक्ट का 1935 में सर्वे हुआ था, किन्तु उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट का पैसा महाराष्ट्र की जायतवाड़ी-प्रोजेक्ट के लिए खर्च कर दिया गया। इस प्रकार की जो राजनीति चलती है इससे वहां असन्तोष बढ़ता जाता है। अभी डागाजी ने कहा कि महाराष्ट्र काफी पैसा ले गया, लेकिन वह पैसा खर्चा कहां हुआ ? जहां कि लीडरशिप पावरफुल होती है वहां वह पैसा चला जाता है, लेकिन विदर्भ का न कोई मां है और न बाप है—यह हालत विदर्भ की हो रही है . . .

एक माननीय सदस्य : गलत बात है।

श्री राम हेडाऊ : गलत नहीं है, आप हमारे साथ विदर्भ चलिये, हम आपको दिखलाते हैं कि वहां क्या स्थिति है, लोग कितना चिल्लाते हैं—तुम्हारे नाम से।

यदि वैनगंगा प्रोजेक्ट बन जाय तो उससे मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और विदर्भ को पानी मिल सकता है और बाढ़ से होने वाली हानि को रोका जा सकता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नागपुर, अमरावती और भण्डारा ऐसे जिले हैं जहां सन्तरे की बहुत अच्छी पैदावार होती है, लेकिन अब वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुएं में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। यदि वहां पर शीघ्र पानी की व्यवस्था नहीं की गई, जगह जगह पर पानी के संग्रह करने की कोई योजना नहीं बनाई गई तो भविष्य में यह परिणाम होने वाला है कि करोड़ों रुपये के सन्तरे के पेड़ जिनको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है, सब खत्म हो जायेंगे और फिर दिल्ली वालों को सन्तरा खाने के लिये नहीं मिलेगा। इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ सूचनायें आपके सामने रखना चाहता हूं—प्रदेशों के बीच नदियों के पानी के झगड़े चल रहे हैं—मैं चाहता हूं कि देश की तमाम नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाया जाना चाहिये, राज्यों के अधीन पानी की कोई भी योजना नहीं होनी चाहिये; क्योंकि राज्यों के अधीन होने से झगड़े ज्यादा बढ़ते हैं। केन्द्र द्वारा पूरे देश का सर्वे करा कर जलाशयों की योजना बनाई जानी चाहिये। ये योजनायें राजनीति से बिल्कुल प्रभावित नहीं होनी चाहियें। बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण हो, खाद्य उत्पादन बढ़—इस दृष्टि से योजनायें बनें तथा उन योजनाओं से देश की एक-एक इंच भूमि को पानी मिल सके—ऐसी व्यवस्था की जाय। जलाशयों से बिजली निर्माण करके जलमार्गों के द्वारा आवागमन की व्यवस्था की जाये और जल

पर केन्द्र का शासन हो और नियंत्रण हो। देश में सन्तुलित विकास की दृष्टि से योजना बनें और ऐसी योजना न बनें जिससे वहां के काश्तकार चिल्लाते रहें और उनको पानी न मिले और फसल सूख जाये। इसके लिये जिले के लोक प्रतिनिधियों की राय मांगी जाये और उस पर विचार हो और सर्वे होने के बाद योजना बने और और उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो। 27 साल हो गये हैं और इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया है और इससे हमारे देश को बहुत हानि हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : सभापति जी, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि बाढ़ और सूखा हमारे देश में आता है तो हम कहते हैं कि यह दैवी प्रकोप है और हम इतने भाग्यवादी हो गये हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करता हूं कि यह सब प्रकृति के प्रकोप से हुआ है। मनुष्य की भी इसमें जिम्मेवारी है।

सभापति महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में 6 हजार गांवों में 30 लाख आदमियों को इससे क्षति पहुंची है और सैकड़ों आदमी मरे हैं और उससे कहीं ज्यादा पशु तबाह हो गये हैं। 15 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक करोड़ रुपया इसके लिये इकट्ठा किया है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ 18 लाख रुपया दिया है जब कि दूसरे राज्यों को जहां उससे कम क्षति हुई है उससे अधिक पैसा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का सवाल है, इस साल बाढ़ नहीं आई होती अगर सम्बन्धित राज्यों ने अन्तर-प्रान्तीय फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड समय पर बना दिये होते और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया होता। जहां तक बांध बनाने और दूसरे रिलीफ वर्क्स का सम्बन्ध है, ये एड-हाक ऐरेंजमेंट हैं और उनसे स्थायी प्रभाव नहीं पड़ पाता है वहां की जनता के ऊपर और केन्द्र से जो सहायता दी जाती है उसके काफी बड़े हिस्से का दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको कुछ स्थायी काम भी करने चाहिये। यह सही बात है कि फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के आपके पास पैसे की कमी है किन्तु आपके पास जन-शक्ति है, मैनपावर है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बांध बनाने या नाले और नहरें चौड़ी करने का काम आप बाढ़ आने से पहले करें और उस काम को पंचायतों और ग्राम सभाओं की मार्फत किया जाए और जो जन शक्ति है, उसका उपयोग आप करें। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक आप स्थायी काम नहीं करेंगे आप बाढ़ का सामना नहीं कर सकेंगे और लोगों को तबाही से नहीं बचा सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमको फ्लड कन्ट्रोल के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये और रोजगार देने के काम को भी प्राथमिकता देनी चाहिये और इस तरह के काम जो हैं उनको बाढ़ आने से पहले शुरू कर देना चाहिये। बाढ़ जब आ जाती है तब आप परेशान हो जाते हैं और जनता जो है वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और इंजीनियर और अफसर लहरें गिनने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिये बाढ़ की नौबत न आने पाये, उसके लिये प्रोटेक्शन वर्क्स पहले से ही करने चाहिये।

मैं अपने सैनिक विभाग को और बंसीलाल जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके जवान जब जब बाढ़ आती है बड़ी मजबूती के के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ लोगों की

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

जान बचाने का काम करते हैं और उन्होंने समें काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। इस लिए मैं उन को फिर बधाई देना चाहता हूं कि जहां जहां इस तरह की स्थिति होती है वहां सैनिक जाकर मदद करते हैं। मैं यह चाहता हूं कि वे सैनिको से गांवों के लोगों को ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करें ताकि उन का भार हल्का हो सके।

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं पिछली 20 अगस्त को शिन्दे साहब ने कहा था कि जंगल कटने नहीं चाहिये लेकिन 1951 में जब बनमहोत्सव शरू हुआ और 1973 तक 34 लाख हेक्टेयर जमीन में जंगल कटे। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली हो और चाहे पटना हो, बाढ़ें जहां भी आती हैं उन के मूल में जो बात हैं वह यह है कि पेड़ो को काटा जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि पहाड़ों में पेड़ को बचाइये और अधिक से अधिक मात्रा में बनों को लगाइये। जितने ज्यादा बन लगेंगे उतना स्वायल इरोजन नहीं होगा और जमीन मजबूत होगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने 5, 7 साल पहले यमुना, गंगा, ब्यास, सतल ज और चिनाव आदि नदियों में बांध बना दिये होते, तो आज यह नौबत न आती। टिहरी में अगर बांध बन गया होता तो पटना की बरबादी नहीं होती। इसी प्रकार देहरादून का लखड़ाव डैम अगर बन गया होता तो दिल्ली में तबाही न हुई होती। इसलिये अब भी समय है कि आप इस योजनाओं को प्राथमिकता दें और इन कामों को मस्तैदी के साथ पूरा करें।

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि एक तो जंगलों की रक्षा करें और दूसरे पहाड़ों में बांध बनवायें और पहाड़ों का इरोजन रोकें।

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, the problem of flood and drought is not a problem of any particular State, but of India, as a whole. It is only accidentally that there is normalcy throughout India; the general feature is that there is excessive rainfall in some areas and less rainfall in others. The solution for this should be that the excess water in an excessive rainfall area or in a flood-prone area is reserved for the dry season. Sufficient storage must be created for it. That is the first thing to be done.

Next, we should control the rivers along with having afforestation. Without this, we cannot normalize the rains, drought or floods. This problem can be solved, because we have got the Himalayas in the north. We have got a regular monsoon which no other country has. Still we are suffering; and is it not an aspersion on any civilized nation? It is also an aspersion on us. This must be taken seriously.

In China, after 1949, they have turned their Rivers of Sorrow into a River of Plenty and Happiness. They have fully controlled the floods. They have penetrated the mountains and they are self-sufficient in foodgrains. They have got sufficient stocks. Their agricultural land is less compared to ours, but their production is much more than ours. Why this difference? In our country, the government has got sufficient number of scientific projects; but where is the money? The State Government has no money. The Central Government has got other things to do. They cannot give money. But how has China solved the problem? By radical land reforms, they have encouraged the initiative of their 80 crores of people. Those people have solved the food problem of their areas, in their own interest. There are 50,000 communes. They have solved the food problem throughout their country. That being so, why should our people suffer and

starve? You should solve the problem in a radical manner; and for that purpose, the labour power of our human beings should be utilized. It can be done by radical land reforms. If you are really serious about it, you can take to that course. If we can do it peacefully, it is very good; but if we cannot, we must solve the problem somehow. It is the government's responsibility to take measures for solving the problem. It is a serious problem. It is no use asking for money. We must have a total perspective, for the solution of the problem. We must have the initiative of the masses, that is, of more than 40 to 50 crores of people in the rural areas. Their manpower must be utilised to solve these problems of drought and flood. The scientific aids are there; the scientific knowledge is there. But, at present, mostly the big land-owners and profiteers are making money out of these drought and flood situations. They give loans to the poor suffering people to get more in return, whether it is drought or flood. In this situation, the problem is a very serious one and the Government should seriously consider it.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that our country has always been subjected to floods of late more often than before.

The hon. Members have said that this time, there has been an unprecedented flood or an unprecedented drought. Every time, it is said that it is an unprecedented flood or drought. But nothing has been done to stop flood or drought. Every year we go on saying it. In fact, this year also, there was a flood. In north Bihar, there is always a problem of floods. But this time, even in south Bihar, there was so much flood that many bridges were washed away and many houses collapsed. Many dams were blown off. When the dams were blown off, all the snakes went into the river and the tribals and others who were crossing the river used to be beaten by the snakes. Many people lost their lives. I personally think that the Bihar Government is not very much aware of the flood situation in our area and, therefore, they are perhaps not very mindful of giving any compensation for the damage caused in our area.

Drought is the way of life in our area. We are always in the grip of famine. But so far the Government of India or the Government of Bihar have never paid any attention to the famine or drought situation in our area. Nothing has been done. As my hon. friend, Shri Shankar Dayal Singh, said, Maharashtra and other States get a lot of funds for the flood and drought situations. But Bihar has been very unlucky in this respect because they do not get anything in proportion to the losses sustained by them either due to the flood or due to drought.

I think it is high time that the Government of India give a serious thought to the flood control and try to divert the water of the Ganges to other channels and make the maximum use of water resources. We were thinking in terms of taking the water from the Ganges to the Godavari and we were perhaps contemplating to spend about Rs. 2500 crores spread over a period of 15 years. I would request the Government of India to have a general survey of flood situation in the country and prepare a master plan for the flood control in the entire country. We are not gaining by taking short-term measures and finding temporary solutions. We are losing every time whatever money is being spent on these things. If we think about having a permanent solution, the amount of money involved on that will not be much.

One thing is certain that so far as drought situation is concerned, the people are always in the grip of the fear of drought. Even when there is no drought, they start crying that there might be a drought.

[Shri Kartik Oraon]

I was told that in the flood areas, because the floods bring with them the deposits of silt, next year there would be a bumper crop and that is why people sometimes cry and are worried when there are no floods. So, it is a curse which is sometimes a blessing in disguise But they take away so much of life and property. So, we should think more in terms of protecting the life of the people and also in terms of a permanent solution.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव): सभापति महोदय, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम नदियों की वंदना करते है । सम्भवत: इस वंदना के पीछे नदियों को प्रलयंकारी रूप का प्रभाव रहा होगा नदियों की बाढ के साथ साथ सुखा भी प्रगति का एक प्रकोप है । यदि मानव समाज से पूछा जाये कि वह सुखा और बाढ, इन दो विपत्तियों में से किस को कम हानिकारक समझता है, तो उस का उत्तर यही होगा कि बाढ से भले ही बहुत कष्ट हो, लेकिन सुखे की अपेक्षा हम बाढ को स्वीकार करगे, क्योंकि बाढ़ क्षति पहुंचाते ने साथ साथ कुछ दे भी जाती है ।

डा० के० एल० राव ने 1966 में बाढ-नियंत्रण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत एक नदी का पानी दूसरी नदी या नहर में डालने का विचार था । यह व्यवस्था नहीं की जा सकी । नदियों पर बांध बना कर हम बाढ की रोक-थाम कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं और सिचाई की व्यवस्था कर सकते में । लेकिन सुखे के बारे में हम क्या करेंगे ।

छत्तीसगढ क्षेत्र में, जो भंडारा जिले से आरम्भ होता है और जिले में नागपुर, राजनंदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजगढ और सरगूजा आदि जिले शामिल हैं, केवल धान की खेती होती है । अगर वहां पानी बरसा, तो धान पैदा होता है और अगर न बरसा, तो एक-दम सुखा पड़ जाता है । इस सदन में कई बार कहा गया है कि हम उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां पोटेंशल आफ़ रेन है । छत्तीसगढ में 40, 50 इंच बारिश होती है, लेकिन चूंकि हम नदियों के प्रवाह को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए सारा पानी बह कर बेकार हो जाता है ।

हमारा देश इतना सौभाग्यशाली है कि संसार में जितना पानी आकाश से धरती पर पड़ता है, उस का दसवां हिस्सा हमें प्राप्त होता है । इस के अतिरिक्त हमारे देश में 83 नदियां ऐसी हैं, जिस में निरन्तर पानी बहता रहता है । लेकिन घूम-फ़िर कर बात आती है कि पैसा नहीं है । जब तक पैसे की व्यवस्था होती है, तब तक डैम बनाने के सामान के दाम बढ जाते हैं । 1,000 करोड़ पये की जो योजना बनाई गई थी, आज शायद उस के खर्च की रक़म 3,000 करोड़ पये हो गई होगी ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी योजना बनाई जाये, उस को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए । एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए, जिस के द्वारा यह देखा जाये कि किसी डैम का निर्माण किस ढंग से हो रहा है । हर हफ्ते रिपोर्ट आये कि कितना बना और अगर योजना के अनुकूल नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, उस में व्यवधान क्यों हुआ, आदि ।

प्लानिंग कमीशन को यह चाहिए, आज तमाम योजनाएं वह बनाते हैं

लेकिन उन का कोई कंट्रोल रूम नहीं है । पैसा जो स्टेट को दे दिया आप का दायित्व है कि आप देखिए कि काम उस पैसे से हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है तो कितनी गति से हो रहा है, प्रगति से काम चल रहा है या नहीं ? अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है ? जब तक केन्द्रीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिस से आप यहां बैठ कर नियंत्रित कर सकें तब तक काम सही ढंग से नहीं चल सकता ।

यह जो ड्राउट है उस में धरती को हम देखते हैं तो उस में दरारें पड़ जाती हैं, पानी पीने को नहीं प्राप्त होता है । धान पैदा नहीं हुआ । पीने को पानी नहीं प्राप्त होता है तो फिर हम को बड़ी कठिनाई होती है और फिर हम सरकार के दरवाजे खटखटाते हैं कि राहत के लिए कुछ काम किया जाय । हमारे मध्य प्रदेश के सीमित साधन हैं और आदिवासियों का इलाका है । हर तीसरा व्यक्ति वहां आदिवासी या हरिजन है । सर्वहारा समाज का वहां बाहुल्य है । तो आप यहां से कोई ठीम भेजिए, रिपोर्ट उस की आए और काम आरंभ हो ।

अंत में मैं यह कह कर बैठना चाहता हूं कि कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए 50 करोड़ पया दीजिए, टीम के सर्वे के आधार पर दीजिए नहीं तो वहां के लोग जैसे दो वर्ष पहले तकलीफ में आ गए थे, बेचारे त्राहि त्राहि करने लगे थे, दाने दाने को मोहताज हो गए थे वही हालत हो जाएगी । हमारी धरती भी प्यासी है और धान कास कटोरा भी खाली है । इस का कोई इंतजाम कीजिए ताकि लोग भूखों न मरें ।

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): Regarding floods and drought, I would not like to deal with the temporary relief aspect because many Members have emphasised it. It has become a perpetual problem for many parts of the country, particularly floods and drought in North Bihar and drought in Rajasthan and other areas. Here I would like to emphasize on some durable solutions for this problems.

The genesis of floods in Bihar is that those rivers which bring water from the Himalayas cause floods; and those very rivers drain out the water from the fields and cause drought also. We have tried earth embankments. Even if the embankments are strong and durable, which they are very seldom, the water course will not change from south to north, water comes to south in a more concentrated way and the Ganga is over-flooded and invades the south. That is why in the meeting of the Central Ministry where the Deputy Minister, Shri K. N. Singh, and many officers were present, I had, unfortunately, predicted that the floods would come to the south. And it happened unfortunately; we had a virtual deluge in Patna. Once that was there, some people like us felt that Government would now make up and think of a permanent solution. But the solution found was that Rs. 17 crores were provided for earth embankments to protect Patna. This huge amount was not a minor temptation for many politicians, engineers and contractors. Again, this year there were floods in large areas around Patna. Our fear is that, now, every year, this tantalysing appetite for easy money will bring in devastating floods, sometimes from the south, sometimes from the west, sometimes from the north and sometimes from the east. This is a national crime. The earth embankments may provide a temporary relief, but limiting ourselves only to earth embankments has given rise to this national crime. In Darbhanga town last year, more than Rs. 1 crore worth of embankments were made. The construction of embankments was so timed as to collapse with the coming of the floods. The floods were delayed, but the collapse of the embankments

[Shri Bhogendra Jha]

could not be delayed; without the floods, they collapsed. Now, enquiries are going on. But we know what will happen. That is the tragedy. Now, the floods are travelling south. What is the solution? There is a solution which is technically feasible and practicable, but unfortunately that is not being implemented because of the vested interests of politicians, engineers and contractors in temporary relief works.

Pandit Jawaharlal Nehru was serious about it, and he personally got a survey made. In 1950, Barachetra dam project over the river Kosi was prepared with a capacity of 18 lakh kilowatts of power. In the 20-point Programme, the Prime Minister has put a target of 26 lakh kilowatts of power for the whole country, whereas this project on the Kosi alone can give 18 lakh kilowatts of power. It can irrigate 38 lakh acres; it can completely eliminate floods and it will become navigable upto Barachetra. Similarly, Sisapani Barrage over the river Kamla and the Noonta Barrage over the river Bagmati can completely eliminate floods and drought for the whole year and can ensure power not only for Bihar but also for the rest of the country.

Why was this not done? I am quoting from a note received from Shri C. C. Patel, Additional Secretary, under his letter dated 11th December, 1975. It says:

> "The construction of the high dam was postponed to a later stage as at that time there was no market for the huge block of power and stored water was not required for irrigation."

We have been experiencing power shortage in the country and this is the report of the Government of Bihar that this power, 18,000 KW cannot be utilised. It is like saying that as I have got my belly full of mangoes, you should not plant a mango tree. One must realise that the mango tree will give fruits only after four years.

The Bihar Government had constituted in January 1974 the Kosi Board of Consultants and in their note dated 14th September, 1974 on the desirability of construction of a storage dam at Barahkshetra on Kosi river, they said:

> "The Board feels that the time is now ripe to take up the Barahkshetra dam project in hand. The project would give a positive solution to the silt problem, being upstream and downstream of the Bhimnagar Barrage. This project would also effectively reduce the highest peak floods to safe limits."

This is the official opinion. They also said that the project will now be economically feasible. They also said that the hydro power would be a boon to the region. They also suggested that further investigations of this project which is of national importance should be entrusted to the Central Water and Power Commission, as they had carried out the investigations for the earlier 1950 project also.

With regard to Gandak project, a major part of the canal construction has been completed and I feel that some dam has to be constructed where Sapatgandaki is formed, so that this is tackled at the source itself and the floods are avoided. When it is technically feasible and is desirable, we cannot understand, why this is not being done. As I said, this House should put a stop to only temporary things, because that is a national waste and it is a crime against the country and the people.

When I read of floods in Madhubani and by the time I reach Samastipur, the floods have already reached there. They are receding from Darbhanga and there is drought in Madhubani and Sitamarhi. For these things, some

permanent solution has to be thought of. Whenever there is a flood, we want temporary measures and temporary solutions, and later on forget about that. The Ministers are there, the Government is there and the experts are there and they must try to find out permanent solutions. If they do not do it, it is a crime against the nation.

I am ashamed of asking for Rs. fifty crores for Bihar, because I am certain at least Rs. thirty crores will go down the drains and only Rs. twenty crores will be utilised.

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : सभापति महोदय, देश में हर वर्ष बाढ के कारण करोड़ों रुपये की क्षति होती है और न मालूम कितनी जानें चली जाती हैं । इस वर्ष उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ से पीड़ित रहा । जिस जिले से मैं आता हूं वह गंगा यमुना के बीच है और न मालूम कितनी छोटी छोटी नदियां बीच से गुजरती हैं । पिछले सितम्बर में जो वहां पर बाढ आई उससे अकेले हमारे जिले में 16 करोड़ का नुकसान हो गया और करीब 82 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । फ्लड का यह जो परमानेन्ट फ़ीचर है उस को हल करने के लिए कोई परमानेन्ट सल्यूशन ढना होगा । एक समय पर एक मुसीबत आई उसका आप उपाय करने लगे उसके बजाये कोई परमानेन्ट पालिसी या सल्यूशन होना चाहिए । हम देखते हैं बख्तन फ़क्तन फ़्लड कमीशन्स ने अपनी सिफ़ारिशें दी हैं उन पर सरकार को बड़ी तेजी से अमल करना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है—हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपये की एक दस साला योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है । इस योजना को अगर केन्द्रीय सरकार स्वीकृति दे दे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दस सालों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिये जो उपाय किये जायेंगे उस से हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को तसल्ली और तस्कीन मिल जायगी ।

हमारे यहां कोई नेशनल फ्लड पालिसी नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस को ले-डाउन किया जाय । जहां तहां काम करने से काम नहीं चलेगा । आप जानते हैं—हमारे मथुरा में कितनी जबरदस्त बाढ आई थी, उस से बहुत भारी नुकसान हुआ था । जहां जहां नदियों में नाले आ कर मिलते हैं, बाढ़ के दिनों में पानी का घनत्व बहुत बढ जाता है, इस से जो पुल उन नदियों पर बनाये जाते हैं वे छोटे पड़ जाते हैं, कभी कभी तो वह जाते हैं, मैं चाहता हूं कि उन नदियों पर पुल बड़े बनाये जायें ।

जहां बाढ की समस्या है, वहां वाटर-लागिंग की समस्या भी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये का नुकसान इस बात से होता है कि वहां कोई एफ़िशियेन्ट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी के निकालने की कोई रास्ता नहीं बनाया जाता है । मैं चाहता हूं कि इन जिलों का सर्वे कराया जाय, सारे देश में जहां जहां पानी का वाटर-लागिंग होता है, उस पानी को निकालने के लिये योजना बनाई जाय ।

नहरों की जो बम्बे और गूलें होती हैं, मेरा मतलब ब्रान्चज से है, उन की सफ़ाई नहीं की जाती है । थोड़ा सा भी पानी आने से उन में बाढ आ जाती है—मैं चाहता हूं कि इन की सफ़ाई की व्यवस्था की जाय ।

गंगा और जमना नदियों के किनारे लोग मकान बना कर रहने लगते हैं, जब

[श्री हरी सिंह]

बाढ़ आती है तो बहुत नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि इस मनोवृत्ति को रोकना चाहिये, लोग वहां पर परमानेन्ट नेचर के मकान न बनायें, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो रहना चाहते हैं वे टैम्परेरी मकान बना कर रहें। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Because of the drought situation in the south, particularly in Andhra Pradesh, a grave situation is Prevailing. Recently, I had been to my Parliamentary constituency as well as to other parts of my State. There I met hundreds of poeple who told me what their difficulties were because of the drought.

The peculiar situation this year is that since about 30 years for the first time in the month of July the rain was very heavy. The rainfall was not only heavy but timely. Thinking that there will be sufficient water not only in the tanks but also in the wells and other projects, the agriculturists have cultivated almost the whole land which is in their possession. In cultivation they have invested a lot of money. They have grown commercial crops. Dry crops are also there. Paddy and everything is there. But, unfortunately, what happened since the 1st of September is that there is no rain at all. Since about 2 months on account of lack of rain they have suffered and all crops including the commercial crops, paddy and everything are completely damaged and they are in difficulties. When I saw their faces, I was very much pained, I tell you. You know the difficulty of the agriculturists because you are one of them. After this emergency if at all any section is affected, it is only the poor peasants. It is only the agriculturists who are affected, not others. The employees, the traders, the industrialists and even politicians are all happy. But these people are the only people affected. Whatever they produce, they do not get remunerative prices and when this kind of a situation prevails, they also suffer. This is the situation that is prevailing in our country, particularly, in the rural areas. I am sorry to say that the Government is not doing anything for them. 80 per cent of us represent them here. We are all from the agriculturist community. Even then we do not represent them effectively. Whenever we represent, we are dubbed as landlords, Kulaks and what not. This is the situation. I think the Central Government must provide whatever amount is required by the State Government.

In Andhra Pradesh, in spite of the peculiar situation prevailing over there, our Chief Minister is very kind. He is asking people not to raise hue and cry. He says that he will approach the Central Government and will request the Prime Minister to see that something is provided so that the difficulties of the poor peasants are mitigated.

18.00 hrs.

Today about 40 people met the Prime Minister and submitted a memorandum in regard to the drought situation in our State and requested for the sanction of Rs. 50 crores so that the projects which are incomplete can be taken up by our State Government.

We have got very good rivers. Recently, our Chief Minister rightly described our State as the State of rivers. We have got beautiful rivers Godavari, Krishna, Tungbhadra, Vasudhara. There are so many rivers. Inspite of these rivers we have not been able to take up the projects. We had taken up projects like Pochampad project, Nagarjuna Sagar, Somasilla project, Srisailam Project, Vasudhara project. But they have not been completed because of lack of funds.

We approached the Central Government to sanction the requisite amount as these projects would not only serve Andhra Pradesh but they can serve the whole country also. Last year and before that also the country was in difficulties and we were importing a lot of foodgrains from other countries. At that time Andhra Pradesh was the only State which came to the rescue of the whole country. It is described as 'annapurna' of the country. If the projects which have been undertaken by our State Government ...

MR. CHAIRMAN: Your time is up.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Oh God, so soon.

If the Central Government gives the amount, whatever is required, after completion of the projects the State will not only feed itself but also the country as a whole. The Central Government must come to our rescue in the interest of the country. We must be provided with this amount. We are experiencing difficulty.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhdeo Prasad Verma.

(Interruptions)

Please do not shout. I cannot do favour to you. I have given you five minutes. I am giving five minutes to each member.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I am sorry to remark, whenever you speak you take an hour, but you do not allow other Members. This is unfair.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhdeo Prasad Verma.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I shall point out when you speak next.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhdeo Prasad Verma.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: What is this? I have not spoken anything. This is very bad.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (नवादा) : सभापति महोदय, अभी सितम्बर के महीने में जो भयंकर बाढ़ बिहार में आई... (व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: Wait a minute. It is known to the House that there are large number of Members on the list. The House decided that everybody should be given five minutes. Even then all the Members will not be called. To show protest against the Chair and to utter such language, with such shouting is not desirable. I am not doing any favour to anybody whatsoever. I am giving five minutes. I will not given a minute less.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please hear, do not shout. Please hear.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: You also shout whenever you are here.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are showing disrespect. I will have to report this.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I do not care.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let it go on record as to what he is doing.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: You show arrogancy. We are affected. Everbody is affected by this. You think yourself a great man. You do not deserve to be in the Chair.

MR. CHAIRMAN: All this should go on record.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Let it go on record. I am not worried.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhdeo Prasad Verma.

(Interruptions)

श्री मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिहार में सितम्बर के महीने में जो भयंकर बाढ़ आई थी, उसे प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और भारत सरकार के अधिकारियों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस कदर भयंकर बाढ़ बिहार में आई थी और इस बारे में इस सदन में भी और बाहर भी काफ़ी कहा जा चुका है। जिन स्थानों में आज तक लोगों ने बाढ़ नहीं देखी थी जैसे माननीय बाबू जी का भगुआ क्षेत्र, वहां भी बाढ़ आयी। इस बाढ़ से गरीबों और फ़सल की बरबादी हुई। आज हालत यह है कि लोगों के सामने भुखमरी का सवाल पेश है। इस बाढ़ के सम्बन्ध में हर साल हम लोग चर्चा करते हैं इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का स्थाई निदान हो इस पर आप विचार करें। अरबों रुपया जो अब तक आप राहत कार्यों पर खर्च कर चुके हैं उतने पये में आप इस बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान कर सकते थे।

हम जिस जिले से आते हैं, गया, औरंगाबाद और नेवादा यह जिले पहले दो बाढ़ से और नेवादा सुखाड़ से ग्रस्त रहते हैं। जिन इलाकों में पहले बाढ़ आयी है वह अब सुखे का मुकाबला कर रहे हैं। गया, औरंगाबाद और नेवादा जिलों की कुछ स्कीमें हैं जिन को अगर पूरा कर दिया जाय तो बाढ़ और सुखाड़ से हम बच सकते हैं। एक मुहाने रिजरवायर की स्कीम है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की है, वह योजना आप के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी तरह से तिलैया डाइवर्जन स्कीम है, जिस के सम्बन्ध में माननीय के० एल० राव ने आप को कई बार कहा है, वह भी पड़ी हुई है, इसी तरह से सकरी रिजरवायर की स्कीम थी आप के यहां पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं को आप शीघ्र कार्यान्वित करायें ताकि बाढ़ और सुखे की समस्या का स्थाई हल निकल सके।

मैं समझता हूं कि निवादा को स्थाई रूप से ड्राउट प्रोन एरिया में आप ने रखा है। एक करोड़ रुपया आप ने पहली बार 1972-73 में दिया और जितनी भी स्कीमें हैं, और सड़क आदि के काम को हाथ में लिया गया, वह सब अधूरी पड़ी हुई हैं, उन योजनाओं के लिये आज तक निवादा में भारत सरकार की ओर से एक पैसा नहीं भेजा गया। तो इस तरह की स्कीमों को हाथ में लेने से क्या लाभ जो पूरी नहीं होती हैं और फिर सुखाड़ क्षेत्र आप निवादा को घोषित कर देते हैं। इस से कोई फायदा नहीं होने वाला है। निवादा की प्रथम किस्त देने के बाद दो साल से देना बन्द कर दिया है, परिणामतः सारी स्कीमें बन्द पड़ी हुई हैं।

इस बाढ़ में आप बहुत अच्छा राहत कार्य किया है। लेकिन जिन गरीब भूमिहीन किसानों के एक भी कच्चे मकान इस बाढ़ में नहीं बचे हैं उन को 50, 100 रु० देने से क्या राहत मिल सकती है? इतने में तो फूंस का छप्पर भी नहीं पड़ सकता, मकान कैसे उन बेचारों के बन जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि बाढ़ और सुखे की भीषण समस्याओं को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले, राज्यो पर न छोड़े। अगर राज्यों पर इस काम को छोड़ा तो इस समस्या का कभी भी निदान नहीं हो पायेगा।

बाढ़ से बचने के लिये जो बाढ़ नियंत्रण का सुझाव आया है मैं उस से सहमत हूं। मेरा निवेदन है कि सुखाड़ क्षेत्र में जमीन के नीचे से पानी निकाल कर सिंचाई का समुचित इंतजाम किया

जाय । आप जिओलाजिकल सर्वे करायें जमीन के अन्दर ग्राउन्ड वाटर का और उस से सिंचाई का प्रबन्ध करायें । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सदा सूखा बना रहेगा ।

अभी माननीय बाबू जी नें ऐलान किया था कि शीघ्र ही बिहार के अन्दर किसानों को समय पर अच्छे बीज दिये जायेंगे । मैं आप को सूचना देता हूं कि रबी के लिये गेहूं, चना आदि का बीज सब जगह आप नहीं पहुंचा पाये हैं । बस मुझे यही निवेदन करना है ।

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan): Mr. Chairman, Sir, famine and drought are not new to this country.

Speaking for our State, I was asked by Members of Parliament from Karnataka to lead a team of 12 Members to look into the scarcity conditions in Karnataka. Only Karnataka State, this year, has been fully isolated from the railfall map of this country. If I have to explain all the misery of the people of my State, it will take a long time and I will not do it. But it is an admitted fact that the unfortunate condition of Karnataka is that there is no water in tanks, no water in wells, no crops and not even preliminary agricultural operations have taken place. If at all some preliminary operations had taken place, due to the subsequent failure of the monsoon or inopportune rain, the crops withered away. Coffee, which is an important foreign exchange earner, exported to the international market from Karnataka, has withered away. Cocoanut, areca and sugarcane have withered away. The loss to both rabi and kharif crops due to the failure of rains is unimaginable. On this matter, we submitted a memorandum to the hon. Prime Minister, our beloved leader. She was very sympathetic and said, she is willing to send a second team. We are happy about it. We also met our Agriculture and Finance Ministers and they are also sympathetic. So, we have no grouse. But until and unless the Chief Ministers write a letter to the Centre, the Centre is not in a position to send any team, first or second. That is one bottleneck. Secondly, the Chief Ministers—whether it is due to political or administrative or other reasons best known to them—are thinking that the money that the Central Government is going to give to meet floods or famine is only the money that is going to be given from the next plan allocation and it is not any money of the Central Government which it is giving. I am unable to understand why the Chief Ministers have been made to have this kind of view. Why does not the Central Government have a special reserve fund for flood and famine? I request the Government to call the Chief Ministers of all the States and tell them that they have to review the old regulation made by all the Chief Ministers regarding the Sixth Finance Commission's recommendation. Without correspondence, the Centre will not send a team. Without separate allocation of money, the States cannot cater to the needs of the people. So, the people die and the cattle die. 20 per cent of the people of Karnataka are have-nots. They get 40 P to one rupee every day. 20 per cent have 5 acres and less of land. They are small and marginal farmers or agriculture labour. What would be the fate of these 40 per cent if sufficient work is not given? For that, sufficient amount has to be earmarked. For a hungry elephant, if 6 paise worth of buttermilk is given, will it be sufficient? When Karnataka Government wanted Rs. 21 crores, the first team estimated the requirement at Rs. 7 crores and the actual amount released was just Rs. 3 1/2 crores! Now the minimum need of Karnataka is Rs. 50 crores.

I have some proposals which I submit to the government through you. All irrigation projects under progress which are going to be commissioned

[Shri N. Shivappa]

shortly if channel works are completely done within a short period of six months like Hemavathi, Harangi, Krishna, Ghataprabha and Kabani, must be completed. If that is done, a minimum of 5 lakh acres will be irrigated and people will get permanent relief. Secondly, minor irrigation works should be augmented by allotting sufficient money. Thirdly, open well irrigation has to be taken up. This will create a lot of labour potential for the poorer sections. It will also tap underground water as an eternal solution for the famine. Famine is in our daily life. Indian agriculture is a gamble on the monsoon. I request the Central Government to send a second study team to Karnataka. The whole State, all the 16 districts, all the 120 talukas, are in the full grip of famine. People have no money; they have no food. They even do not have the capacity to purchase food. Cattle have no fodder. Polluted water is being drunk by the people. So, my humble request through you to the Government is that kindly relax and make flexible the old bureaucratic procedural aspects so that we can have control over drought and floods in all parts of the country.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): In India, we are having drought in certain areas and floods in other areas. So, the drought and floods are the twin problem of India which have become insuperable. Almost all the Members unanimously put before the Government permanent and long-term solutions to control floods and drought situation.

For centuries, our forefathers, great economist, politicians and others have been demanding the execution and implementation of the Ganga-Caveri-Cape Comerin Project. If this project is completed, I hope, there will be no drought or flood situation in India. This will solve the problem of drinking water and we will get enough water for irrigation. The unemployment problem will also be solved to a great extent. This will be one of the important projects from the national integration point of view. Therefore, we want that Ganga-Caveir-Cape Comerin Project should be taken up as soon as possible. The World Bank has accepted this Project in principle and they have provided Rs. 2000 crores for the implementation of this Project. I do not know why our Government is not undertaking this project immediately. I am sorry to say that this important point has not found place either in the 20-Point Programme or the 5-Point Programme of the young gentleman, Shri Sanjay Gandhi. I suggest, let it be the 26th point in this Programme.

In Tamil Nadu, Ramnad district is a chronically drought affected area from time immemorial. Another district, Madurai, has also been affected due to continuously failure of rains for the last five or six years.

There is now no drinking water in my constituency of Dindigul, as well as in the Mudukulathoor area of Ramnad. I request the Government to grant more and more of loans. Government of India have granted Rs. 7½ crores as loan for drought relief work. This amount, for Tamil Nadu, is nothing but a small popcorn given to a hungry elephant. Not less than Rs. 50 crores should be allotted to Tamil Nadu to enable it to cope up with the very grave situation which has arisen there and to save the poor villagers, middle classes, working community and the down-trodden people. The rivers in the Tanjore district, which is the producing centre of paddy, have dried. The rivers in Tiruchi, Madurai and Tirunelveli districts have also become dry. There is no production of rice. We request the Government of India to include the problem of river waters in the Concurrent List. That problem has to be solved by the Government of India. It should not be left to the

State Governments. This item has so far not been included in the Central List, or in the Concurrent List.

I appeal to the Government of India to take up the problems of Cauvery waters as also of waters of Godavari, Krishna and Narmada. Drought conditions are prevailing throughout Tamil Nadu, except in Madras City and Chingleput. The farmers are not producing any crop at all. Government is taking drastic steps to loans. They are going to recover the loans by impounding the cattle and taking away agricultural implements. I request the Government of India to instruct the Government of Tamil Nadu and all the nationalized banks not to recover loans taken from government, banks and societies. The Centre should also instruct the Government of Tamil Nadu not to collect land revenue also this year.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): India is basically an agricultural country. We are having various types of climates all over the country. We have drought somewhere; and somewhere we have floods. In fact, this is a perennial problem. The problem of the States has already been discussed. Members have narrated how people have been affected. The difficulty today is that drought and famine are treated like an orphan child. The Central Government unfortunately thinks that famine and drought conditions are State subjects and that it can wash off its hands. We would like to know from the hon. Minister to tell us, when he replies to the discussion as to what is the stand of the Central Government.

Before the 5th Finance Commission's recommendations were there, out of the outlay in this regard, 25 per cent was to be contributed by State Government; 25 per cent by the Centre and the remaining 50 per cent was given as loan to the State Government. This is how the State Governments were able to carry out their relief works. After the Finance Commission's recommendations, the whole pattern has changed. There is no contribution from the Central Government. They say that they have given the States a 5-year outlay. There is a divisible surplus which is divided among the States. The States can only have an advance from this surplus, according to their individual share, and thus fight these calamities. I would like to ask the hon. Minister: is this a reasonable situation? If we do not find a permanent solution to fight these droughts and floods, how do you expect the States—whenever these problems arise whether in the North, South or elsewhere—to tacle these problems? This is the purpose of our discussion in the House. The Central Government must think of a *via media* for providing better implementation and for giving financial assistance to the States whenever such calamities occur. These floods and droughts occur in different parts of the country. In some States they may occur once in 3 years; and in some others, once in ten years.

Rajasthan, as you know very well, has been perennially a drought-prone area. The people living there have been used to droughts. They have been leaving Rajasthan during drought periods and migrating to neighbouring States and then returning to their homes after the rains during the winter. In the last three years, instead of drought, we are having floods in Rajasthan. In 1973-74, we had heavy floods. Food had to be dropped by helicopters like Bihar and Orissa. We had a similar situation in 1975 and also in 1976.

The whole topographical and climatic conditions of Rajasthan seem to have changed. There has to be some explanation given for this change by our scientists as to why this change has taken place. In Rajasthan, we have not grown trees or taken up any other natural development works. We were having no drinking water. Now, the situation has changed. There

[Shri N. K. Sanghi]

should be some explanation for it. According to laymen, it is possibly because of the atomic blast at Pokharan and that might have affected the climate. But the hon. Minister should give an explanation for this. Is it that in Rajasthan there may be another spell of drought? We should have a proper scientific investigation into the change of climate in Rajasthan.

During the last rains, Jodhpur city with a population of 400,000 people was cut off from the roads and the railways. Both rail lines were breached and the roads were washed away. The city became an island with no communication. Jodhpur was cut off from Jaipur, the capital of Rajasthan. There was no means of communication for a few days. This was an unprecedented situation, unknown in history. The hon. Minister will have to give an answer to that.

The Rajasthan Government has already sent a memorandum to the Central Government indicating that 390 villages were affected, 4 lakh persons were affected, 13,000 houses were damaged or destroyed, cattle worth Rs. 1 lakh was lost, crops worth Rs. 2.50 lakhs were damaged and a loss of Rs. 12 crores occured due to damage of bridges, roads and dams. This is the situation in Rajasthan. I do not come here to ask for more finances. The State Government has asked for Rs. 18 crores as a financial outlay to meet the situation.

We have a project like the Rajasthan Canal. It is known to all of us that it is a national project. I am sure, both the Central Government and the State Government are very keen to complete it. It was to be completed in 10 years. Now, it is spread over to 25 years. The cost outlay has increased from Rs. 200 crores to Rs. 500 crores. The Rajasthan Canal project is a very important project so far as defence and strategic matters are concerned. During the last two Pakistan wars, we have seen that our forces could not cross their canals, like the Ichogal canal of Pakistan. They proved to be natural barriers. The Rajasthan Canal, when completed, will also prove to be our maginot line. So, this has to be considered from the defence and strategic value besides its economic value.

I can give you a number of examples. But the time at my disposal is very short. I can tell you how this Canal will help us, in the matter of our defence strategy. This Canal will help in increasing our population on our border. We have seen in China, Sinkiang, Soviet Russia and Mongolia how they have increased their population by such development works. I would request the Central Government to take over the Rajasthan Canal project as a Central project and that it is completed on a war-footing so that when it is completed this will help us to fight this perennial problem of drought and flood.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Chairman, Sir, the country of ours is a land of many paradoxes, poverty amidst unexploited riches of nature, recurring floods amidst chronic drought. While a severe drought gripped the States of Orissa, Karnataka, Tamil Nadu etc., this year, scorching lands and crops, drying up tanks and wells, parching the throats of large populations scrambling for drinking water, the States of U.P., Bihar, Punjab, etc. were visited by furious floods of unprecedented magnitude in living memory.

As we all know, Orissa is visited intermittently by droughts and floods over the decades and the losses over the years have been colossal and, perhaps, more than what it would have cost to finance a plan of flood control. In the current year, serious drought conditions are developing in a considerable area of the State due to erratic rainfall particularly the unprecedented dry spell persisting since about the second week of September, 1976. Disconcerting reports about the situation are now being published in

the local daily papers. However, much credit must go to the State Government because even during the Puja holidays, the State Government deputed very senior officers to the State to make an on-the-spot assessment of the situation in all the 13 districts of the State and on the basis of their report, the Government have taken timely measures to combat the situation.

But considering the vastness of the areas, the percentage of population affected and the magnitude of the problem it creates as days are passing by, no State Government can meet the challenge satisfactorily without the help of the Central Government. The anticipated crop loss of paddy, millets, maize and ragi, it is reported, will be as high as 40 per cent to 50 per cent of the total production in the State. The Rabi Programme could not be planned out by the average cultivator because of dearth of moisture in the soil. The inadequacy of rainfall has affected storage in reservoirs of major, medium and minor irrigation projects. The inflow of water is very inadeuqate in Hirakud and smaller projects are showing signs of drying up and may not be useful till the next monsoon.

In this situation I appeal to the Central Government to send a Central Team. I am told that they have decided to send a Central Government Team to assess the situation in these chronically drought and flood affected areas in Orissa to prevent a worsening of the situation which is threatening to take place.

Apart from these temporary measures, it will go a long way towards tiding over the present situation and also towards helping the people of Orissa, if the Centre takes up a project like the Subernrekha project. I am very glad to know that the State Governments of Bihar and Orissa have agreed to implement this project but from where can they get the money? It should come immediately from the Centre so that this major chunk of the area is saved from famine.

There is also another major project—the Bhimkunda project—which has been pending for five or six years with the Central Water and Power Commission. My appeal is that unless this project is taken up immediately, the chronic problem of droughts in the State of Orissa cannot be overcome.

MR. CHAIRMAN: Through the cooperation of the Members in not taking more than five minutes each, we have been able to cover most of the Members and now only eight are left. The whole Bill has been finished in one-and-a-half hours.

AN HON. MEMBER: You may call these eight Members also; all the eight are not here.

MR. CHAIRMAN: Most of them are here. If they take five minutes each, it may take about an hour more —and the Minister's reply is also there. So I am prepared to give four minutes each.

श्री जगदीश नारायण मंडल (गोड्डा): सभापति महोदय, हमारे देश में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिहार में तो बाढ़ का प्रभाव ऐसी जगहों पर पड़ा जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आई थी। हमेशा उत्तर बिहार में बाढ़ें आया करती थीं, लेकिन इस बार तो दक्षिण बिहार बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिस से अरबों रुपये की क्षति हुई है और बहुत बड़ी संख्या में जान-व-माल का नुकसान हुआ है। इस में सन्देह नहीं कि सरकार की ओर से काफ़ी मदद दी गई, लोगों के जान-व-माल की रक्षा की गई। अब उन की रबी की फ़सल की बुआई होने वाली है, मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ़ जाना चाहिये। रबी की फ़सल के लिये बीज, खाद इत्यादि का प्रबन्ध किया जाय ताकि लोग जल्द से जल्द बोआई पूरी कर सकें तथा जब तक फ़सल पैदा न हो, सरकार को चाहिये कि उन के

[श्री जगदीश नारायण मंडल]

खाने की व्यवस्था करें, ताकि उन को तकलीफ़ न हो ।

उसी तरह से आज सुखाड़ की स्थिति हमारे यहां है और कई जिलों में तो यह बड़ी भयानक है । आप संथाल परगना और भागलपुर की स्थिति देखिये, जिस जिले के, सभापति महोदय आप भी रहने वाले हैं । संथाल परगना में आज हम देखते हैं कि 6 प्रखंडों मे से एक, दो प्रखंड तो बाढ़ से प्रभावित हैं और बाकी चार, पांच प्रखंड सूखे से प्रभावित हैं । वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत से कुओं में पानी तक सूख गया है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है । वहां पर 50, 60 प्रतिशत जो रोपने का काम किया गया था, पानी न पड़ने के कारण सब के सब बीज सूख गये हैं और हमारे पास चिट्ठियों पर चिट्ठियां आ रही हैं कि धान फूट नहीं रहा है और एक भयंकर स्थिति वहां पर पैदा हो गई है । ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि जिस तरह से उस ने बाढ़ में प्रबन्ध किया है, उसी तरह से सुखाड़ में लोगों की सहायता कर के पानी का कुछ प्रबन्ध वहां पर करे । जिस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है वहां पर सरकार को तत्कालीन रिलीफ के कामों का प्रबन्ध करना चाहिए । वहां पर मिट्टी वगैरह खोदने का काम होना चाहिए । खिचड़ी बांटने के लिए लाल कार्ड का प्रबन्ध होना चाहिए । सस्ती रोटी की दुकानें खोलने का प्रबन्ध होना चाहिए, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जानी चाहिएं और अनाज खरीदने के लिए ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए । वहां पर जो लोग हैं वे बहुत गरीब हैं और 80, 85 प्रतिशत उन में आदिवासी और हरिजन हैं । वहां पर 32, 33 लाख लोग बसते हैं और उन की हालत बहुत खराब है । इसलिए उन के लिए आप को कोई व्यवस्था करनी चाहिए । वहां पर जमीन ऊंची नीची है और इरीगेशन भी केवल 2 प्रतिशत में है । इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक वहां के लोगों की हालत को सुधारने के लिए आप कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे, उन की हालत दयनीय रहेगी और वे लोग बराबर सूखे से पीड़ित रहेंगे । वहां पर 32, 33 लाख एकड़ जमीन मे धान की फसल होती है और एक ही फसल होती है । इस के अलावा दूसरी फसल नहीं होती है और इस साल हालत यह है कि 4 प्रतिशत धान भी वहां पैदा होगा, यह कहना मुश्किल है । सब का सब एरिया वहां बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुआ है । सरकार को चाहिए कि वहां पर तत्काल लोगों की सहायता करे ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि उस एरिया में कहलगांव गंगा की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम शुरू हुई थी लेकिन वह अभी पूरी नहीं हुई है । उस से लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और भागलपुर और संथाल परगणा के लोगों को लाभ हो सकता है । उस को पूरा कर के अगर दामोदर नदी में ले जा कर गिरा दिया जाए, तो लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है । इस तरह से आप देखें कि हमारे संथाल परगणा जिले में जो स्कीमें हैं, वह पूरी नहीं हुई है । 25 साल हो गये हैं और अभी वहां पर कुछ नहीं हुआ है । सर्वे वगैरह ही होता रहता है और काम कुछ नहीं होता है । इसलिए अगर इन स्कीमों को पूरा कर दिया जाए तो सिंचाई का ठोस इंतजाम हो सकता है और लोगों की हालत सुधर

सकती है । अगर वहां पर कोई ठोस काम नहीं किया गया, तो वहां के लोगों की हालत हमेशा दयनीय रहेगी और उन को हमेशा सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति जी, बिहार में जो यह भयंकर बाढ़ आई है, उस के लिए लोग यह कहते रहे है कि यह दैवी विपत्ति है और बराबर उस को देवी विपत्ति के नाम से पुकारते रहे हैं । हमारे माननीय कृषि मंत्री बाबू जी ने भी यह कहा है कि इतनी भयानक बाढ़ बिहार में बहुत वर्षों के बाद आई है । ऐसी बाढ़ पुनपुन में 1903 में आई थी और उस के बाद अब यह बाढ़ आई है । इस का असर क्या हुआ ? इस का असर यह हुआ जैसा कि पं० डी० एन० तिवारी ने कहा कि पटना को बचाने के लिए नये बांध बनाये गये और गंगा के दूसरी तरफ बाई ओर बांध नहीं बनाया गया और सारा गंगा का पानी छपरा, सारेण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और कटिहार जिले तक चला गया। उधर हजारीबाग में 7 दिनों तक वर्षा होती रही और वह सारा पानी पुनपुन में चला या । नवीन बांध से पटना तो बच गया लेकिन उत्तर बिहार के बहुत बड़े भू-भाग में पानी ही पानी हो गया । मैं ने कई बार केन्द्रीय सरकार से आरजू की है कि समस्तीपुर जिले के बरूआ बांध (गंगा) की मरम्मत करा दी जाए । पुराने जमाने में तो यह काम हो जाया करता था लेकिन इस बार नहीं हुआ हालांकि हमारे केन्द्रीय उप-सिंचाई मंत्री श्री केदार नाथ सिंह ने इस में बड़ी दिलचस्पी ली लेकिन ब्योरोक्रेटिक बोटलनेक्स की वजह से काम नहीं हो पाया। अगर वहां पर बरूआ बांध की मरम्मत का काम ठीक तरह से पूरा हो जाए, तो लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से बच जायेगी और सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे संसदीय क्षेत्र (समस्तीपुर) में, मैं देख रहा हूं कि कई साल से बूढ़ी गंडक "जवान" हो गई है और काफी नुकसान कर रही है । इस साल उस से नुक्सान कम रहा लेकिन फिर भी एक छोटा सा सुझाव अपने वैज्ञानिकों को माननीय मंत्री जी के द्वारा देना चाहता हूं । अगर हम केवल कैलेमिटी की ही बात करते रहें तो वैज्ञानिक किस दिन के लिये हैं ? इन को अब जागना चाहिये, नहीं तो जितने पोलिटीशियन्स हैं वही टेक्नोक्रैट बनेंगे और वही सुझाव देंगे जो कि उन्हें पसन्द नहीं होगा । उन से पूछा जाय कि 5, 10 साल बाद नदियों की क्या हालत हो जायगी अगर ड्रेजिंग नहीं की गई । सेडीकेंटेशन रोक्स हिमालय पहाड़ों की बह बह कर नदियों की बैड को ऊंचा कर देगी और आये दिन हमें बाढ़ का सामना करना पड़ेगा । इसलिये ड्रेजिंग का समुचित इंतजाम कीजिये । जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जैसे कोसी, बूढ़ी गंडक, नारायणी और गंगा, इन में ड्रेजिंग के लिये आप दो, दो चार, चार ड्रैजर्स दे सकते हैं । लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है । बड़े बड़ टेकनोक्रट्स कहते हैं कि हम लोग लोक सभा में ऐसे ही सुझाव दे रहे है । हिमालय से काफी नदियां निकलती हैं, बरसात में उन में बाढ़ आती है जो नुकसान करती है और सारा पानी व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है । पहले के जमाने में क्रौस बंध छोटी नदियों में बना दिये जाते थे, लेकिन अब कोई ध्यान ही नहीं देता । अगर इस दिशा में हम कुछ कर सकें तो खेतों को पानी दे सकते हैं और बाढ़ को भी नियंत्रित किया जा सकता है ।

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

गंगा के क्षेत्र में कैश क्रौप होती है, लाखों मन मिर्च, मसाले होते हैं। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो इस उपजाऊ क्षेत्र वाले लाके में आप क्रौप इन्श्योरेंस शुरू कीजिये। इस काम में आप बिहार सरकार की मदद कीजिये। इतनी सुन्दर मिटटी के बहते हुए भी सारी फसल सूख जाती है। इस समस्या का गम्भीरता से कोई हल निकालना चाहिये।

1971 में आप ने गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन कायम किया और उस का हैडक्वाटर भी पटना में रखा। कभी कभी उप-मंत्री जी वहां जाते भी हैं। मगर वहां के लोग क्या करते हैं यह कोई नहीं देखता। उन के काम पर भी आप की निगाह होनी चाहिये। आज लाखों लोग मुसीबत में हैं, सकड़ों लोग मर गये बाढ़ में और सैंकड़ो करोड़ रु० का नुकसान हुआ है जिस के कारण वहां की आर्थिक स्थिति 10, 15 साल पीछे चली गई है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गम्भीरता-पूर्वक सोचिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर) : सभापति जी, हमारे देश में वैसे ही सूखा और बाढ़ का प्रभाव अलग अलग जगह पर पड़ा है। वह प्रतिवर्ष की स्थिति है और इस में कोई संदेह नहीं है कि हम अक्सर इस पर चर्चा भी करते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत यह हुई कि इस वर्ष जून के शुरू में वर्षा हुई जब कि खतों में काम नहीं हो सकता था, और जुलाई में वर्षा नहीं हुई जिस से खेती का काम पिछड़ गया, जिस की वजह से फ़सल ठीक से नहीं ली जा सकी। जुलाई के आखिर में जब वर्षा हुई तो लोगों ने धान और मक्का लगाना शुरू किया। लेकिन पूरी खेती नहीं हो पाई थी कि अगस्त के आखिर में और सितम्बर में जो अतिवृष्टि हुई उस का प्रभाव यह पड़ा कि जो कुछ खेती की गई थी उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ खेती में वैसे ही काम नहीं हो सका था, लेकिन जो धान की खेती की गई थी, उस भय के मारे इतने लोग घबरा गये जहां मकान गिर रहे थे, चारों तरफ खेत डूबे हुए थे, लोग मेंड़ों को ठीक से भी नहीं बांध सके। नतीजा यह हुआ कि जो पानी बरसा था वह भी निकल गया और धान की फसल खराब हो गई। पानी जो लगातार बरसा, एक तरफ खेत में पानी आ जाने से जमीन को नुकसान हुआ और एकाएक पानी निकल जाने के बाद जमीन सख्त हो गई और जुताई नहीं हो सकी जिस का कुप्रभाव रबी की फसल पर भी पड़ेगा।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरयू के बीच का क्षेत्र इतना उपजाऊ है और धरती के नीचे इतना पानी है, अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाता और पहाड़ पर नदियों को वास्तव में बांधा गया होता, तो उस पानी का हम बिजली के लिये भी इस्तेमाल कर सकते थे और नहरों के द्वारा हम उस पानी का सिचाई के लिये भी उपयोग कर सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे धन के साधन का कारण हो, चाहे उस तरफ ध्यान न दिये जाने का परिणाम हुआ हो, आज उत्तर प्रदेश अपने पूरे खाने भर के लिये भी पूरा प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है। जहां ऐसी उपजाऊ जमीन हो, अगर वहां की नदियों का पानी ठीक से बांधा जाये, तो हम बिजली का भी लाभ उठा सकते हैं और सिंचाई के लिये भी पानी का उपयोग कर सकते हैं और ऐसी व्यवस्था से अपने प्रान्त की

हीं नहीं, दूसरे प्रान्तों की भी सहायता कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदश में गन्ने की बहुत खेती होती है, और उससे इतनी चीनी पैदा करते हैं जो सारे देश को देते हैं । हमारे यहां पश्चिमी हिस्से में गेहूं की भी अच्छी उपज होती है और धान की भी अच्छी उपज होती है, लेकिन परेशानी यह हो जाती है कि बहुत सी बड़ी-बड़ी नदियां बाहर से आकर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत हानि पहुंचा जाती हैं ।

इस सम्बन्ध में प्राचीन काल के जो छोटे-छोटे बांध थे, जो तालाब होते थे, जिनसे सिंचाई करते थे, उन तालाबों का पट्टा कर दिया गया, उसके बजाय अगर सिंचाई के लिये पानी रोकने के लिये कोई नई व्यवस्था कर दी जाये तो उससे क्षेत्र को बड़ा लाभ हो सकता है और जो सूखे से पीड़ित रहते हैं, वे भी उसका लाभ उठा सकते हैं ।

मेरा सुझाव है कि सिंचाई की व्यवस्था और जहां नदियों के जल की समस्या है, इनको केन्द्रीय विषय बनाया जाये । प्रान्तों के बस की यह बात नहीं कि वे इसको सुलझा सकें । वे केन्द्र से सहायता पाने पर ही इस काम को करते हैं । अगर उनको केन्द्र से सहायता लेकर ही करना है, तो केन्द्र को इस विषय को अपने हाथ में लेना चाहिये । अगर इस तरह से बिजली, सिंचाई और बांध का काम केन्द्र अपने हाथ में लेता है तो मैं समझता हूं कि सारे देश की स्थिति अच्छी हो जायेगी और हम इसपर अच्छा नियंत्रण पा सकेंगे ।

श्री चिरंजीव भा (सहरसा) . सभापति महोदय, प्रति वर्ष बाढ़ आती है और इस देश में लाखों व करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है । इसके नियन्त्रण के लिये कोई सुनियोजित योजना होनी चाहिये ।

मैं बिहार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । 16 जनवरी, 1976 को इसी सदन में हमारे कृषि मंत्री श्री माननीय जगजीवन राम ने कहा था कि 1975 में जो बिहार में बाढ़ आई, खास कर पटना में, उससे 10 करोड़ 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, फिर दूसरे बरस 1976 के सितम्बर में जो बाढ़ आई है, उसमें लगभग 2 अरब रुपये का नुकसान हुआ है । स्वयं माननीय बाबू जी ने कहा है कि विगत 5, 6 शताब्दियों में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी । यह इस वर्ष की भीषणता का स्वरूप रहा है । हर साल इस तरह की रफ्तार से बाढ़ आती है, इस अवसर पर सरकार जो कुछ रिलीफ देती है उसके तत्काल कुछ राहत हो जाती है, लेकिन अगले वर्ष फिर वही रफ्तार जारी रहती है । इस तरह से तो प्रति वर्ष यह बाढ़ का क्रम बन्द होने वाला नहीं है ।

आवश्यकता इस बात की है कि स्थायी-रूपेण बाढ़ नियंत्रण के लिए सुनियोजित योजना बने और उसको कन्ट्रोल किया जाये । माननीय प्रधान मंत्री जी भी इस अवसर पर वहां गई और 21 सितम्बर को उन्होंने जो अपना व्यान दिया उसमें बताया कि दरअसल में वहां पर क्या स्थिति है । बिहार सरकार केन्द्र की सहायता से और अपनी पूरी शक्ति लगा कर जो कुछ कर सकती थी, वह उसने किया है । लेकिन जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है, उस को देखते हुए लोगों को "ऊंट के मुंह में जीरे का फोड़न" के समान मदद मिल सकी है ।

इस बार 6,50,000 हैक्टर क्षेत्र में बाढ़ आई है । उस से फसल की पूरी बर्बादी हुई है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी बह गई है और सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल आदि सार्वजनिक सम्पत्ति की भी अपार

[श्री चिरंजीव झा]

क्षति हुई है । बिहार सरकार ने सार्वजनिक भवनों आदि की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की है । इस के अतिरिक्त उस ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना बनाई है । लेकिन बिहार सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह उस योजना को कार्यान्वित कर सके । इस लिए केन्द्र को इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की पूरी सहायता करनी चाहिए ।

कोसी को शोक की नदी कहा जाता है । हम लोग बराबर उस से पीड़ित रहे हैं । दो तटबन्धों के द्वार पर इसे सीमित क्यों किया गया है किन्तु इसकी समस्या का पूरा निदान नहीं दे पाया है । अतः स्थायी समाधान के लिये आवश्यकता है कि कोठार डम की पुरानी योजना को कार्यान्वित किया जाय तथा, डगमारा बैराज का निर्माण कराया जाये । जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हर वर्ष नदी के तल की ड्रेजिंग की व्यवस्था की जाये । दोनों तटबन्धों के बीच के तीन सौ गांव बराबर पीड़ित रहते हैं । इस बार अगस्त में वहां पर एक नाव-दुर्घटना में लगभग 150 आदमी डूब कर मर गये । हर साल इस तरह की दुर्घटनायें होती रहती हैं । अतः सरकार को उन लोगों के स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : सभापति महोदय, मेरे मित्रों ने सूखे और बाढ़ के बारे में तफसील से कहा है । देश के बहुत से भाग--आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यू० पी०, बिहार और उड़ीसा वगैरह--सूखे और बाढ़ के शिकार बने हैं ।

हमारे यहां किसानों को उम्मीद थी कि इस साल खरीफ की फसल अच्छी होगी, क्योंकि कुछ पानी पहले बरसा था । लेकिन सितम्बर के बाद पानी बिल्कुल नहीं बरसा । तालाबों में भी पानी सूख गया । यहां तक कि आदमियों और जानवरों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिला । आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा और तेलंगाना में खासतौर पर सूखे की हालत है ।

मिनिस्टर साहब को मालूम ही है कि गोदावरी बैराज टूट गया है । उसकी मरम्मत के लिये कई करोड़ रुपये की जरूरत है । आज आन्ध्र प्रदेश के मैम्बरान-पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को एक मैमोरैंडम पेश किया है । हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर उस पर हमदर्दी से विचार करके आन्ध्र प्रदेश के रिलीफ के लिये काफी मदद देंगी, ताकि वहां सूखे से निजात हासिल हो सके । सैंट्रल गवर्नमेंट को गोदावरी बैराज की मरम्मत के लिये स्टेट गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिये ।

आन्ध्र प्रदेश में बीबीनगर-नाडीकुडा रेलवे लाइन मंजूर हो गई है और प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन कर चुकी है । स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा ने 4 साल में उसकी तकमील करने की एश्योरेंस दी थी । उस रेलवे लाइन का एस्टीमेट 25 करोड़ रुपये से ज्यादा है । पिछले साल उसके लिये 50 लाख रुपये का एलाटमेंट किया गया । इस तरह तो वह लाइन 50 साल तक भी पूरा नहीं होगी ।

मैं समझता हूं कि रेलवे से फंड ले कर बीबी नगर से नाडीकुडा रेलवे लाइन को कम्पलीट किया जाय तो एक तरफ से रेलवे भी कम्पलीट हो जायगी और दूसरी तरफ ड्राफ्ट के समय में मजदूरों को मजदूरी भी मिल जायगी ।

फेमिन रिलीफ के लिए माइनर इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन की तरफ खास तवज्जह दें तो बेहतर रहेगा । अभी तक रायल

सीमा में और तेलंगाना में डी पी एस के प्रोग्राम नाफिज हैं लेकिन सूखे की वजह से वहां की हालत और अबतर हो गई है। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक टीम भेज कर स्टेट गवर्नमेंट की सहायता करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिल जायगी तो वह इन कामों को कर सकेगी। अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में बहुत सी नदियां हैं, उन में खम्मम पोचमपाड और नागार्जुन सागर की योजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी)। सभापति महोदय, घंटों की प्रतीक्षा के बाद आप ने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राज्य मंत्री श्री शाहनवाज खां का ध्यान उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। मंत्री जी सन् 1946 में सीतामढ़ी गये थे जिस समय पूरे देश में ढिल्लन, सहगल, शाहनवाज का नारा गूंज रहा था, सभी जवान और बच्चे यही नारा दे रहे थे, उस समय वे वहां गये थे। मैं उनको सीतामढी ले गया, उन को याद होगा। सीतामढ़ी में 29 करोड़ की लागत से बागमती सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है। काम तो प्रारम्भ हुआ है बागमती में लेकिन जहां नूनथर पहाड़ से बागमती नदी निकलती है और आपकी जो योजना उस पर बांध की है वह नेपाल बार्डर बर्गीनिया तक आप बनाना चाहते हैं जिसकी लम्बाई करीब 105 मील की है। लेकिन मंत्री जी को मालूम होगा वह नदी नूनथर पहाड़ के नीचे जहां आपका बांध बनाया जा रहा है उससे निकल कर दूसरी तरफ़ चली गई है जिसकी वजह से जो करोड़ों रुपये का बांध बनवा रहे थे, वह सब बरबाद हो गया। मैंने इसकी सूचना पिछले सेशन में दी थी। जगजीवन बाबू से भी निवेदन किया था। के० एन० सिंह साहब सीतामढ़ी गये थे। संयोग की बात है कि के० एन० सिंह साहब ने प्रोगाम बनाया सीतामढ़ी जाने का लेकिन जिस दिन हम लोग माला ले कर प्रतीक्षा कर रहे थे, उस दिन वे नहीं गए। गए कब? जब मैं सीतामढी में नहीं था तब वह पधारे। वहां के ठेकेदारों और बड़े-बड़े इंजीनियरों ने जो लाखों रूपये इसमें खा गये है काफ़ी के० एन० सिंह का स्वागत किया। लेकिन हमारी शिकायत है कि के० एन सिंह ने जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे निमंत्रण पर जाने का प्रोग्राम बनाया तो जिस दिन उन्होंने समय दिया वहां जाकर वहां की स्थिति देखने का उस दिन वे नहीं गये और 15 दिन के बाद गये जिसकी सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी। इसलिये मैं आपके माध्यम से श्री शाहनवाज खां साहब को पुनः निमंत्रण देता हूं कि आप आजादी के पहले सीतामढ़ी गये थे, 16 जनवरी को, मुझे वह तिथि भी याद है, लाखों की संख्या में हम लोगों ने आपका स्वागत किया था, मैं पुनः आपको सीतामढ़ी चलने का निमंत्रण देता हूं।

वहां जो भयावह स्थिति बागमती में हो गई है, नदी की धारा बदल गई है, करोड़ों पये कि बर्बादी हुई है उसको आप चलकर देखें। वहां पर पये की लूट हो रही है। बागमती नदी में नारायणपुर बांध के नजदीक एक कच्चा बांध बनाया गया। उस बांध का कार्य मई के महीने में शुरू हुआ। मई के महीने में उस बांध का कार्य इंजीनियर्स ने और कन्ट्रैक्टर्स ने इसलिये शुरू किया कि 15 दिन के बाद फिर फ्लड आ जाये और बिना कोई काम किए करोड़ों पये भुना लें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप यहां से एक उच्चस्तरीय समिति बना कर भेजें जो कि वहां जाकर सीतामढ़ी नारायणपुर बांध की जांच करे। उसमें 15 दिन में 8 लाख रुपये का खर्चा बताया गया है जबकि उसमें 8 लाख का खर्चा नहीं हुआ है, केवल 50-60 हजार पये ही खर्च हुये हैं और बाकी साढ़े सात लाख रुपया वहां के इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर्स ने लूट लिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि

[श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव]

आप वहां पर जांच समिति जरूर भेजें । वह समिति वहां पर जाकर जांच करे और जिन अधिकारियों का भी उसमें दोष हो उनको जितना शीघ्र हो सके पकड़ कर सीखचों में बन्द करें । यदि आप ऐसा करेंगे तो तभी काय सफल हो सकेगा वरना उसमें करोड़ों रुपये का गबन अभी तक हो चुका है वह आगे भी होता रहेगा । मैं पुन: आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिये आप जल्दी से जल्दी एक जांच समिति बनायें और वहां भेजें ।

आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

19.00 hrs.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): Mr. Chairman, Sir, we are passing indeed through a very critical time having floods and droughts engulfing half of our subcontinent. Here in this connection I want to point out that Government of India should take help of the space scientists to know as to when a flood or a drought would occur.

Sir, it has been invariably experimented in Colarado in the USA, USSR and Japan that the space scientists can very well know upto one year before as to when a flood or drought will affect the country. Not only with the help of the space scientists can we immediately gauge the magnitude of devastation but also we can assess the accurate damage. I would like to quote a space scientist in this respect:

> "It would be able to assess the damage caused by floods immediately after the flood has occurred whereas aerial assessment of the damage might take days and weeks."

The Indian Government has patronised space research department and, I think, we are second to none in the way we are progressing. So, we should not lose sight of this important factor.

Sir, Mr. Battacharyya of the Opposition party was speaking about China as to how they have been able to control the floods. It is true that Pandit Jawaharlal Nehru sent a delegation to China to study as to how through voluntary labour a mighty dam had been constructed in a few months time which would have otherwise taken many years. But then, Mr. Chairman, we must remember that China is a regimented society and the people there have been coerced and forced to work. In a democratic society like ours we should appeal to the people to give voluntary labour. I must thank Mr. Sanjay Gandhi for giving a lead in this direction by appealing to the people for voluntary labour for developmental projects. If I may quote an economist even within the coming fifty years India's problems are going to be so vast that we will not be able to tame the rivers far less constructing the mighty dams, reservoirs and such other things with Government resources.

Mr. Chairman, Sir, now I come to my own constituency where the river Subarnarekha has been causing devastation not only in Orissa but also in Bihar and West Bengal. I must thank the Prime Minister, who by her leadership has initiated a process of inter-State negotiation to solve the inter-State water disputes and may I quote Hindustan Standard of 11th September where it has commended our Food and Agriculture Minister:

> "The Union Minister of Agriculture and Irrigation, Mr. Jagivan Ram, has initiated a welcome trend in inter-State relations by persuading Chief Ministers to settle these in water disputes amicably."

It is a very welcome sign, but as far as Subarnarekha dispute is concerned, the signature of the West Bengal Chief Minister is still wanting. Unless it is done, this entire process of inter-State negotiations will end in failure. Although a reservoir has not been constructed to reduce the discharge from

7 lakh cusecs to 3 lakh cusecs to mitigate the intensity of flood, there are other ways to tackle the situation. For example, there is something like a drainage scheme which the Orissa Government could take up with the help of the Union Government. Although several years have passed with flood devastation ruining the economy of the land year after year, this drainage system has not been taken up. There was also a proposal to have a straight cut system from the river to the ocean to clear the water from Subarnarekha. This has also not been done. The model also has not been done in the Pune Model Room.

I must now speak about drought. As many as 13 districts of my State of Orissa have been affected. Orissa is a State where hardly 20 per cent of the area is irrigated and 80 per cent area is un-irrigated. It depends on the dynamism of the State Government, on the dynamism and initiative of the officers to save the people from such a calamity. But what has happened in Orissa? The administration is lethargic. In the *Hindustan Standard*, there is a Samachar report which says.

> "Since 400 pumpsets of the State Lift Irrigation Dept. are out of order, those available with the community Development Department are pressed into service."

The Orissa Government knows, every Government knows, that the emergency of drought and floods is a seasonal affair. So why were they not alive to the situation? Why was the Irrigation Department not alive to the contingency arising?

I must congratulate our esteemed Prime Minister who has donated Rs. 1 lakh from the National Relief Fund to the cyclone-affected areas of North Balasore. The Orissa Government had stated that the cyclone of last September was mild to medium. I had written a letter to our great Prime Minister giving the facts. She had her reports from other sources also. Immediately she sent Rs. 1 lakh.

I must impress upon you that this is not a small thing which can be brushed aside in an inappropriate manner. It concerns the whole country. We have to think how all these mighty rivers can be controlled; we have to think how underground water can be utilised for the agricultural development of our country. If these things are done, I am sure the economy would speed up and there will be a regeneration in the economy of our country.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत सी बातें यहां पर बाढ़ और सुखे के सम्बन्ध में कही गई हैं। हिन्दुस्तान इस मामले में बदकिस्मत है जो देश के किसी हिस्से में या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। मैं बिहार के जिस भूभाग से आता हूं, वह इस मामले में सबसे बदकिस्मत है, वहां हर साल या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, लेकिन इस साल तो बाढ़ ने एक दूसरा ही नक्शा दिखाया है। जिन जिलों में इससे पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी, इस साल उन जिलों में बाढ़ आई है। कहने के लिये तो यह कहा जाता है कि यह प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन पता नहीं इस दिशा में हमारी सरकार और वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? यदि सारी नदियों को एक साथ मिला दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जो प्रकोप हर साल आया करता है, उसको रोका जा सकता है। इसके बारे में हमारे मंत्री महोदय ने भी कहा है कि वे इसके बारे में विचार कर रहे हैं। खुशकिस्मती से हमारी प्रधान मंत्री जी भी उन दिनों वहां गई थी और उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं बिहार की स्थिति को देखा था।

पिछले साल की बाढ़ से पटना बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तब वहां के आस-पास के जो

[श्री राजेन्द्र प्रकाश यादव]

लोग थे, आस-पास के जिलों के जो लोग थे, उन्होंने सद्भावना के तौर पर दुःख प्रकट करते हुए अपने यहां दशहरे का त्योहार नहीं मनाया था । लेकिन इस साल जब कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप था पटना में दशहरे का त्योहार बड़ी धूम-धाम से मनाया गया, लाखों रुपया उस पर खर्च किया गया । कहने को तो यह लगता है कि लोकल-ऐरेंजमेंट था, लेकिन यह चीज वहां के लोगों के एटीच्यूड को रिफ्लैक्ट करती है । यदि इस भावनासे लोग चलेंगे तो न वह प्रदेश आगे बढ़ेगा और न यह देश बढ़ पायेगा ।

अन्त में मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाय और भारत सरकार एक इन्टीग्रेटेड प्लान बनाये ताकि आईन्दा आने वाले बरसों में बाढ़ पर पूरा नियंत्रण किया जा सके ।

SHRI P. GANGADEB (Angul): The drought havoc in Orissa this year has been so severe that the western districts are groaning in an atmosphere of sorrow and helplessness. I know, the Orissa Government have approched the Centre for adequate solution, but the fact is that the Union Government's quick action in the matter is badly wanted. Delay in action will not help matters. In fact, it will defeat the very purpose which is sought for. In other words before the end of the winter season, the help should reach at all the grass root levels in the State. Orissa is one of the most underdeveloped states in India with perhaps the lowest per capita income in the whole of this country. The irony of the situation is that Orissa is endowed with rich natural resourcese and yet the state is in the lowest rung of the ladder of economic growth and progress. While its growth is gather meagre in terms of millions of people in that state, there are the forces of nature quite against us. Quite often we are facing floods or drought or both, practically every year. In this situation, shall we put all the blame on nature, say like weather, monsoon or soil all of which go under the term of ecology, and raise our hands and say: we can do nothing. Or, shall we defy the forces of nature and usher in an era of plenty and prosperity, as the Israelis have done where no trace of water could be found a few years back. I am sure our Government knows better what to do in the present situation to solve the problem. It is high time that an impartial enquiry committee is established to go into the human and natural assets of the State and chalk out a balanced plan in consultation with the State of Orissa. The Committee should ensure not only the development of the resources but also distribution of justice. I hope the Union Government will agree to my suggestion and work on it without any loss of time.

MR. CHAIRMAN : I hope now there no more Members to speak. I call on the hon. Minister. I thank hon. Members for taking just five minutes; only because of that I was able to finish the list of about 47 Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): Mr. Chairman, I am very grateful to the hon. Members who have taken part in this debate. The fact that 47 hon. Members have spoken and taken part speaks volumes about the interest that they are taking in the very vital problem of floods and drought in the country.

May I also compliment you for the excellent manner in which you have given a chance to every Member? You have accommodated each and every Member and I really feel sorry that one Member felt aggreived and I think he will get over this.

Sir, the hon. Members have spoken with great feeling and expressed sorrow on what has happened in different parts of the country. I have taken a note of every suggestion that has been made by the hon. Members. Although I would not be in a position to reply to every individual suggestion here, I assure all the Hon. Members that whatever valuable suggestions they made will be received with the utmost consideration of our Ministry.

Sir, the question is about the floods. It is one of the most important national problems of the country. As early as 1954, our revered late Pt. Jawaharlal Nehru had taken up this question in a very serious manner as to how to deal with this problem. During the period that our Government has been in existence, we have done a considerable amount of work in controlling the floods. Numerous dams have been constructed all over the country—whether it is the Bakra Dam or the Sharda Sahayak Dam or any other dam in the South, huge dams have been constructed in many parts of our country. Those dams are now yielding rich dividends. We are fully aware that there is yet a great deal to be done. The problem is immense. Its magnitude is also fully realised by the country and that is why the Ganga-Flood Control Commission, the Brahmaputra Flood Control Commission and now the National Commission on Floods under the Chairmanship of Shri Hathi have been set up. This shows the great importance that is being attached to this very vital problem. The House is fully aware of our difficulties, our inabilities to undertake the work to the extent that we want. Everybody knows the reason for it. Huge amounts are involved in the construction of these dams and we have to construct them within the resources available in the country. We are doing everything possible to control the floods. There have been many problems in the past. There have been inter-State disputes regarding the rivers. My senior colleague, Shri Jagjivan Ram, in his usual thorough manner has taken up this problem and he has settled all these inter-State river disputes and I hope whatever we have not been able to do in the past, we will now be able to complete them as early as possible.

Sir, this year, the floods had done considerable amount of damage in various parts of this country, mainly in UP, Rajasthan, Bihar, parts of Orissa and Assam. I will not waste the time of the House in giving statistics. But the damage has been considerable. Approximately 83 lakhs hectares of land have so far been reported to have been affected. Naturally the crops in those areas also have been affected. Nearly 12 lakhs of houses have either been damaged or have collapsed. The estimated value of the houses damaged is Rs. 48 crores. We have listened to the hon. members who have given their version of the damages done in their own States and the central assistance required by them. But, our limitation is the limitation of finance. The demands that have been received from the various States are of the order of Rs. 450 crores, which is a huge amount. Hon. members are aware that the sixth Finance Commission has now laid down a policy that a certain margin money is allowed to each State. Some hon. members from U.P. complained that their State had not been treated fairly in the allocation of margin money. The procedure which had been adopted was that the average of the amount spent on flood relief works in the last 15 years from 1956-57 to 1971-72 was taken and the margin money was fixed in relation to that average. So, I can assure the hon. members from U.P. that there is no ill-will or discrimination against U.P. This is the formula we have adopted.

The Central teams have visited most of the affected areas. As soon as they are affected, the State Governments

[Shri Shahnawaz Khan]

send their memorandum to the Centre. As soon as the memorandum is received the central teams go and visit those States and make their recommendations to the high-levelled Committee and the funds are then released. But without waiting for any assistance from the Centre, with the margin money available with the States, they can undertake relief operations straight way. One hon. member referred to bottlenecks, etc. As I said, the margin money is available with the States and they can straight way undertake these works. For further relief, advance assistance is given from the plan allocation. The Centre has now no extra funds to allocate to any State for natural calamities besides what the sixth Finance Commission had decided. It is this procedure that we are following.

Now I come to drought. Due to irregular and irrational rains, many States have been affected by drought. We have listened to all the hon. members who described the conditions prevailing in those States. It is true that due to late onset of monsoon and the long spell of drought in between, certain areas have been affected by drought. But, only recently, we held a conference with all the Chief Ministers and I am glad to inform the House that the overall situation is not as alarming as it has been made out here. I admit that in certain areas of Karnataka and Kerala there has been less rain than the normal but in most of other places, rains have been fairly normal and the Chief Ministers, while giving assessment of the prospect of the kharif season, have assured us that although the crop may not be as good as last year's bumper crop, all-time record crop, the overall position in the country is satisfactory. I can assure the House and through the House the country that in spite of the alarming situation that has been painted here, we have sufficient stock to deal with any situation and in all the States we have surplus stocks. Everywhere our godowns are full and we are confident that we can deal with any situation. The position is that offtake from our central distribution system has declined and there is less pressure because of easy availability of foodgrains in the market. The demand on the public distribution system has been declining. I can say that there is no alarming situation or any apprehension on this account in the country.

The drought, of course, has become a part of our life. Certain areas have been drought-prone areas for centuries. Our efforts is to see that the dependence on rain is minimised as much as possible. We have taken in hand, at present, almost in every State of the country drought-prone area projects in 74 districts and we are going to spend about Rs. 180 crores from the Centre with a matching grant from the States and loans from the banks. Our main efforts in those areas is to provide water, find out how we can increase the irrigation potential. You will be glad to know that in certain areas like Rayalaseema which were drought-prone areas and where it was not possible to bore tubewells, our drought operations have been going on and with the assistance of some friendly countries we have bored through granite rocks and gone below it and found plenty of water in those areas. We are going to exploit that. In areas like Sikar in Rajasthan which was predominately a drought-prone area, we have bored deep and found huge reserves of underground water.

It will be our endeavour to ensure that all the water that is available under the ground is also fully utilized. Also, it will be our effort to impound all the surplus water and than use it at a time when there is scarcity of water throughout the country. Certain types of rigs are being manufactured in the country. Certain other types of rigs which bore

through hard rocks, are not yet being manufactured in the country; but efforts are being made to produce them in the country; we are producing a certain number of tungsten-tipped rigs in the country. We are also trying to produce diamond-pointed rigs which can bore through the hardest of rocks. I admit that we have not yet achieved self-sufficiency. But we will contnue to try to explore for water including that which is underground and also to make use of every drop of water that can be impounded, either in the dams or tanks or *bandhs*. That is the direction in which we are going; and the Government is paying great and special attention to the development of water resources.

For the 5th five-year plan, the target set by our Prime Minister is 5 million hectares of land, to be irrigated through major and medium irrigation; and another 6 million hectares to be irrigated through minor irrigation. We hope that at least 10 million hectares of land would be irrigated during this Plan. That is the pace at which we would like to go.

The drought-prone area projects in 74 districts have been going on. I had an opportunity of visiting those areas. I have visited the Kolar area in Karnataka, where excellent work is being done on sericulture i.e. on the development of silk worm and production of silk. Similarly, we are locating different areas to find out what can be done in those areas to bring prosperity to those people; and like the development of sericulture, we are trying to develop shellac in the Ranchi area. Similarly in all other areas we are doing whatever we can, to make sure that those drought-prone areas which had been neglected so far, do receive the attention that is required for them. The relief and rescue operations that have been taken, have been mentioned by the hon. Members. I would also like to add my word of praise for the excellent work done. I would like to pay tribute to our Defence Services—whether they are of the Indian Air Force or of the Army—for the excellent work done and for the great sense of devotion to duty which they have shown in performing this humanitarian work. I would also like to pay a tribute to the various State officials and State agencies who had mobilized so many country-boats and ensured that the relief stores were sent to areas which were almost unapproachable.

I am very grateful to my hon. friend Dr. K. L. Rao who is an expert and an authority on irrigation, and on control of floods. He has made very useful suggestions and given very-well-thought-out proposals. We will naturally give, due weight to those suggestions and we will try and implement them as much as we can.

There have been some allegations that the funds that are allotted for such relief works are squandered away or they are not properly utilised. Certain instances have been mentioned; certain individual cases have been mentioned. I can assure the hon. Members, particularly my friend from Sitamarhi, that we will look into that matter and do whatever is possible to take remedial steps. But the control on finances naturally from the Centre is given to the States. The State Governments are responsible for exercising proper vigilance over the funds that are spent there.

I entirely agree with my friend from Rajasthan who has spoken so vehemently and with such a great feeling on the early completion of the Rajasthan Canal. It is one of our most important projects in the country and a great deal of our hopes to achieve self-sufficiency in food depends on the early completion of the Rajasthan Canal. We sincerely hope that the State Government will

[Shri Shahnawaz Khan]

do everything possible to complete it as early as it can. The Centre will naturally help to the maximum extent possible.

SHRI K. SURYANARAYANA: Also the early completion of the Godavari project.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: There are many projects. We would very much like the early completion of these projects because on them depends the future welfare and prosperity of the country.

I would like to inform the House that this year we have stopped all imports of foodgrains. We sincerely hope that a situation will not arise when we have to import foodgrains. In spite of all the floods and droughts, we hope that we will still be able to produce enough foodgrains in the country.

May I once again thank all the hon. Members who have participated in this debate. So many suggestions have been made. As I said in the beginning, I will not be able to answer every point that has been made here. We will give every consideration to all your suggestions. My hon. friend, Shri Mohapatra, with his usual flair told us to take full advantage of the space research and the advances made in the field of space research. I fully agree with him. We will try to take the maximum benefit out of that.

SHRI ARJUN SETHI: What about sending Central teams to the affected States so that they can make an on-the-spot assessment and give their report?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: The affected States first send memoranda to us. As soon as the memoranda are received, the Central teams are sent to those States. They make an on-the-spot assessment and give a report. My friend, Shri Daga, felt that there was no need to send any Central team because the State Governments are quite competent to send their reports. Anyhow, when we receive the memoranda from the States, we shall send Central teams there.

सभापति महोदय : बाढ़ और सुखाड़ पर बहस समाप्त होती है और सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाता है ।

The House stands adjourned *sine die*.

19.30 hrs.

The Lok Sabha adjourned sine die.

GMGIPND—L—2114 L S—15-11-76—